04 - महाराष्ट्र : भाजपा की महायुती व विपक्ष की आघाड़ी में मनभेद

05 - वैवाहिक मामलों में समझौते के बाद मुकरना संभव नहीं!

A Daily News Magazine

इंदौर

मंगलवार, 02 अप्रैल, 2024

06- अधिकारी-कर्मचारी निर्वाचन कार्यों को पहले दें प्राथमिकता : कलेक्टर

07- होली मिलन समारोह में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय शामिल हुए

इंदौर एवं भोपाल से एक साथ प्रकाशित

वर्ष 9 अंक 172, नगर संस्करण, पृष्ठ 8, मूल्य रू. 2 (डाक पंजीयन संख्याः MP/IDC/1529/2016-2018)

subahsaverenews@gmail.com

facebook.com/subahsaverenews

www.subahsavere.news

twitter.com/subahsaverenews

सुप्रभात

आधा खुला दरवाज़ा
आधा बंद होता है
वह आधा प्रतीक्षा होता है
आधा संशय होता है
आधा बंद दरवाज़ा
आधा खुला होता है
वह आधा आशंका होता है
आधा अभय होता है
आधा बंद आधा खुला
दरवाज़ा आधा होता है
वह आधा जागता है
आधा सोता है ॥

– नरेश जैन

प्रसंगवश

वरुण गांधी की निजी और सियासी जिंदगी में होने वाले उतार-चढ़ाव

अजय बोस

वरुण फिरोज गांधी को आगामी लोकसभा चुनावों के लिए पार्टी की ओर से टिकट देने से इनकार करना 44 साल पहले 1980 में इंदिरा गांधी की सत्ता में विजयी वापसी के तुरंत बाद हुए उनके जन्म से अंतहीन उतार-चढ़ाव को उजागर करता है। इंदिरा गांधी के राजनीतिक वारिस संजय गांधी के पुत्र के तौर पर उनके सितारे वाकई में बहुत उज्ज्वल थे लेकिन उनके जन्म के तीन महीनों के भीतर वरुण की दुनिया ढहने लगी। दरअसल, वरुण के जन्म के तीन महीने बाद ही उनके पिता संजय गांधी का विमान दुर्घटना में निधन हो गया।

दो साल बाद हालात और खराब हो गए, जब उनकी दादी ने उनकी विधवा मां मेनका गांधी को उनके नए राजनीतिक उत्तराधिकारी बड़े बेटे राजीव गांधी के चुनाव लड़ने के लिए निर्वासित कर दिया। वरुण को मेनका से छीनने के प्रयास तो नाकामयाब रहे लेकिन इस बीच मेनका गांधी ने गांधी परिवार छोड़ दिया। एक घबराया हुआ दो साल का बच्चा अपनी मां का हाथ पकड़कर देश भर के अखबारों के पहले पन्नों पर बैनर की सुर्खियों और तस्वीरों से सबका ध्यान खींच रहा था। इसके दो साल बाद इंदिरा गांधी की हत्या सिख सुरक्षा गार्डों ने स्वर्ण मंदिर में सैन्य अभियान के बदले के तौर पर कर दी थी।

वरुण की जिंदगी में लगातार होते उतार-चढ़ाव– इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी की नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने अभूतपूर्व रिकॉर्ड जीत दर्ज की। यहां पर वरुण और मेनका की किस्मत और खराब होते दिखाई दिए।

इस चुनाव में मेनका गांधी ने अपने पति के पुराने निर्वाचन क्षेत्र अमेठी से अपने राजीव गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ा। लेकिन मेनका गांधी को 270,000 से अधिक मतों से हार मिली। मेनका के राजनीतिक गुमनामी के कगार पर खड़े होने की वजह से वरुण की भविष्य की राजनीतिक संभावनाएं भी धुंधली लग रही थीं।

हालांकि, 1980 के दशक के अंत में राजीव गांधी का कार्यकाल खत्म होने के साथ ही वरुण के जिंदगी के उतार- चढ़ाव का ग्राफ फिर से ऊपर जाने लगा। बोफोर्स घोटाले से कलंकित और वीपी सिंह और अरुण नेहरू जैसे प्रमुख सहयोगियों द्वारा छोड़े गए, राजीव गांधी ने 1989 के राष्ट्रीय चुनावों में जनता दल के नेतृत्व में गठबंधन दलों के एक प्रेरक समूह की वजह से सत्ता गंवा दी। इस दौरान मेनका पीलीभीत लोकसभा क्षेत्र से जनता दल के टिकट से जीत गईं। राजीव का सत्ता खोना और पीलीभीत से जीतना मेनका की खुशी की दो वजहें थीं।

हालांकि, जनता दल सरकार गिरने के बाद हुए मध्यावधि चुनावों में वह पीलीभीत सीट पर बीजेपी से हार गईं. लेकिन अपने बेटे वरुण गांधी को ये सीट सौंपने से पहले वह 4 बार इस सीट से जीत चुकी हैं। गांधी परिवार से जुड़े वरुण गांधी अपने परिवार में सबसे कम उम्र में राजनीति में आने वाले नेता बने। 2004 में वरुण अपनी मां के साथ बीजेपी में शामिल हुए। साल 2009 में जब वह पहली बार चुनाव लड़े तो संसद में बड़े अंतर से जीत कर पहुंचे।

ये जीत का अंतर उनकी चाची सोनिया और चचेरे भाई राहुल और यहां तक कि उनकी अपनी मां से भी अधिक यानी 4 लाख 20 हजार वोट अधिक थे। दिलचस्प बात यह है कि अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी से उनकी जीत का अंतर 1984 में राजीव गांधी और मेनका गांधी के बीच के अंतर यानी 10 हजार वोट से अधिक था।

बीजेपी में वरुण का राजनीतिक कद तेजी से बढ़ा और लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और राजनाथ सिंह सहित कई वरिष्ठ नेताओं को लगा कि गांधी परिवार पर यह एक बड़ी राजनीतिक पकड़ है।

वास्तव में, 2013 में उन्हें बीजेपी का सबसे कम उम्र का राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया था, जिससे उनकी आकांक्षाओं को और भी आगे बढ़ाया जा सके। उन्होंने पहले ही अपने निर्वाचन क्षेत्र में युवा कार्यकर्ताओं को आकर्षित करने और धीरे-धीरे उत्तर प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी अपना प्रभाव बढ़ाने में अपनी छाप छोड़ी थी। आज के बीजेपी में उनका कोई भविष्य नहीं लेकिन इस उभरते राजनीतिक सितारे के लिए दुर्भाग्य से 2014 में मोदी-शाह की जोड़ी ने वरुण गांधी को उस पायदान से नीचे गिरा दिया, जहां पर बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने उन्हें पहुंचाया था।

साफ तौर पर वरुण का राजनीतिक महत्व प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के तत्कालीन अध्यक्ष की नजर में कुछ नहीं था। इसी अध्यक्ष ने अभी-अभी चुनावी रूप से गांधी परिवार को ध्वस्त कर दिया था और उन्हें तेजी से एक तेजतर्रार नेता के तौर पर उभर रहे थे। जिनके पास एक ऐसी पार्टी में भरोसा करने के लिए बहुत सारे स्वतंत्र विचार थे जहां सर्वोच्च नेता में आपका अंध विश्वास ही सफलता की कसौटी थी।

2017 के राज्य विधानसभा चुनावों के बाद उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के उदय के साथ वरुण गांधी की मुश्किलें और बढ़ गईं, योगी के चुने जाने के बाद अन्य दावेदारों के लिए राजनीतिक रसूख की शायद ही कोई गुंजाइश बची थी। वरुण अपनी पहली जीत के बाद लगातार दो संसदीय चुनाव जीतने में कामयाब रहे हैं, लेकिन उन्हें उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित रूप से हाशिए पर डाल दिया गया है।

अपने बदलते सितारों के साथ वह राजनीतिक रूप से प्रासंगिक बने रहने के लिए कभी-कभी हिंदुत्व की नफरत को लेकर बयानबाजी करते हैं, लेकिन अक्सर रोजी-रोटी के गंभीर मुद्दों का पर बोलते हैं। वरुण भले ही पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की कई मौके पर इज्जत करते हैं लेकिन इसके साथ ही प्रदर्शनकारी किसानों की ओर से अपनी आवाज उठाते हैं और निजी तौर पर विपक्ष के संपर्क में रहते हैं। उनके चचेरे भाई राहुल गांधी और चाची सोनिया भी शामिल हैं, भले ही वह बीजेपी से नाता तोड़ने से इनकार करते रहे हैं।

दुर्भाग्य से, यह जानने के बावजूद कि वर्तमान नेतृत्व के तहत बीजेपी में उनका कोई भविष्य नहीं बचा है, इसके बावजूद वैकल्पिक राजनीतिक करियर बनाने के लिए वरुण के पास विकल्प सीमित हैं। कांग्रेस और न ही समाजवादी पार्टी के पास उन्हें देने के लिए बहुत अच्छा पद नहीं है और न ही वे इसकी ओर झुकाव दिखाते हैं और बाद की बहुत अस्थायी चुनावी संभावनाओं को देखते हुए विपक्ष के दोस्ताना इशारों से उन्हें लुभाया नहीं गया है।

(दि क्विंट हिंदी में प्रकाशित लेख के संपादित अंश)

अप्रैल-मई में ज्यादा गर्मी, 20 दिनों तक चलेगी हीटवेव

● म.प्र.- महाराष्ट्र समेत 6 राज्यों में असर ज्यादा ● आईएमडी ने कहा- तापमान सामान्य से ऊपर रहेगा

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारतीय मौसम विभाग ने इस साल ज्यादा गर्मी का अनुमान लगाया है। अप्रैल से मई के बीच तीन महीने तापमान ज्यादा रहेगा। वहीं इस बार 20 दिनों तक हीटवेव की संभावना जताई गई, जो अमूमन 8 दिनों तक रहती है। आईएमडी के मुताबिक, अगले तीन महीनों में देश के छह राज्यों मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में गर्मी का ज्यादा असर रहेगा।

अप्रैल-जून के दौरान भारत के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर रहने की संभावना है। मैदानी इलाकों के अधिकांश हिस्सों में सामान्य से अधिक लू चलेगी।

मंत्री किरेन रिजिजू बोले- देश का बड़ा क्षेत्र हीटवेव से प्रभावित होगा, हम तैयार

मौजूदा हीटवेव की स्थिति पर अर्थ साइंस मिनिस्टर किरेन रिजिजू ने कहा, हमारे अनुमान के मुताबिक, देश का एक बड़ा क्षेत्र हीटवेव से प्रभावित होने वाला है, जिसमें पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश जैसे राज्य शामिल हैं। चूंकि अगले कुछ दिनों में लोकसभा चुनाव हैं, इसलिए हमने हीटवेव को लेकर सावधानी बरती है। तैयारियों को लेकर राज्य सरकारों के साथ दो दिन बैठक भी की गई।

हीटवेव के चलते फसल पर क्या असर होगा

आईएमडी ने सोमवार को कहा कि तापमान में बढ़ोत्तरी से गेहूं की तैयार फसल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आईएमडी डायरेक्टर जनरल मृत्युंजय मोहापात्रा ने कहा, मध्य प्रदेश में इस समय तापमान 37-40 डिग्री सेल्सियस के आसपास है और अगले सप्ताह 42 डिग्री तक जाने की संभावना है। चूंकि राज्य में गेहूं की कटाई का 90 फीसदी काम पूरा हो चुका है, इसलिए कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अगर तापमान 35 डिग्री से ऊपर चला गया तो भी पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। गेहूं की फसल अक्टूबर में बोई जाती है वहीं कटाई अप्रैल के आसपास शुरू होती है। भारत ने 2022-23 के दौरान 1,105.5 मिलियन टन गेहूं का उत्पादन किया। इसमें से उत्तर प्रदेश का हिस्सा 30.40 प्रतिशत, मध्य प्रदेश का 20.56 प्रतिशत, पंजाब का 15.18 प्रतिशत, हरियाणा का 9.89 प्रतिशत और राजस्थान का 9.62 प्रतिशत था।

वह स्थिति जब हवाएं बन जाती हैं हीटवेव

भारत में जब किसी मैदानी क्षेत्र का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक एवं पहाड़ी क्षेत्रों में कम से कम 30 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक तक पहुँच जाता है तो इसे हीटवेव की स्थिति माना जाता है। इसके अतिरिक्त सामान्य तापमान से 7 डिग्री सेल्सियस अथवा उससे अधिक की बढ़ोत्तरी को गंभीर हीटवेव की स्थिति माना जाता है।

केजरीवाल तिहाड़ जेल भेजे गये

15 अप्रैल तक बैरक नंबर 2 में अकेले रहेंगे

● ईडी बोली- दिल्ली सीएम ने बताया कि विजय नायर आतिशी-सौरभ को रिपोर्ट करता था

नईदिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली की शराब आबकारी नीति केस में सोमवार को सीएम अरविंद केजरीवाल को 15 अप्रैल तक के लिए तिहाड़ जेल भेज दिया गया। वे जेल नंबर 2 में अकेले रहेंगे। 21 मार्च से जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जुड़े दो मामलों पर राउज एवेन्यू कोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई।

राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी ने दावा किया कि केजरीवाल ने पूछताछ में बताया कि आतिशी और सौरभ भारद्वाज को विजय नायर रिपोर्ट करता था। ईडी ने कहा कि केजरीवाल हमें सहयोग नहीं कर रहे हैं। वे हमें गुमराह कर रहे हैं। इस पर कोर्ट ने पूछा कि ज्यूडिशियल कस्टडी के लिए ये दलीलें कितनी सही हैं?

- जेल में अरविंद टीवी देख सकेंगे, हफ्ते में दो बार लोगों से मिलेंगे- अरविंद तिहाड़ में टीवी देख सकेंगे। हफ्ते में 2 बार उन लोगों से मिलने की इजाजत है जिनके नाम पहले से लिखे हैं। उनकी पत्नी और लॉयर अब तक उनसे मिलने गए हैं। अरविंद डायबिटिक हैं। इसीलिए उनके पास बिस्किट और कुछ ऐसा हल्का फुल्का नाश्ता रखा रहता है ताकि वो 2-3 घंटे में खाते रहें। उनकी डायट में उनके डायबिटिक होने का ध्यान रखा गया।
- **भाजपा का मकसद चुनाव में केजरीवाल को जेल में रखना : सुनीता केजरीवाल-** अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने कहा कि भाजपा का मकसद चुनाव के दौरान केजरीवाल को जेल में रखना है। उनसे 11 दिन पूछताछ की गई, पूछताछ पूरी हो गई। कोर्ट ने उन्हें दोषी नहीं ठहराया। फिर उन्हें जेल में क्यो रखा जा रहा है?
- **बांसुरी स्वराज बोलीं- तथ्यों पर बेल खारिज हो रही-** भाजपा नेता बांसुरी स्वराज ने कहा- ईडी के सारी के सारी तथ्य देखने के बाद और दलीलें सुनने के बाद कोर्ट को ये लगा कि ये बेल का मामला नहीं है और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बेल खारिज करने की आवश्यकता है। बार-बार आम आदमी पार्टी के नेताओं की बेल खारिज हो रही है क्योंकि जो भी जांच एजेंसियां तथ्य रख रही हैं।

आरबीआई की 90वीं एनिवर्सरी पर पीएम मोदी बोले

बैंकिंग सिस्टम 2014 में डूबने की कगार पर था

● अब ये प्रॉफिट में, पिछले 10 साल में जो हुआ वो तो सिर्फ ट्रेलर है

● 90 रुपए का स्मारक सिक्का लॉन्च किया

मुंबई (एजेंसी)। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) आज अपनी 90वीं एनिवर्सरी मना रहा है। इस मौके पर मुंबई में आयोजित स्मृति समारोह में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, साल 2014 में भारत का पूरा बैंकिंग सेक्टर समस्याओं और चुनौतियों से जूझ रहा था। आज ये बैंकिंग सिस्टम प्रॉफिट में हैं।

पीएम ने ये भी कहा कि हमें देखना होगा कि अलग-अलग सेक्टर्स को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए हमारी क्या तैयारी है? अभी 100 दिन मैं चुनाव में बिजी हूं, तो आपके पास भरपूर समय है। आप सोचकर रखिए, क्योंकि शपथ लेने के दूसरे दिन ही झमाझम काम आने वाला है। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने गवर्नर शक्तिकांत दास के साथ 90 रुपए का स्मारक सिक्का भी लॉन्च किया। ये सिक्का 99.99 प्रतिशत शुद्ध चांदी से बना है। इसका वजन 40 ग्राम है। ये सिक्का नौ दशकों के आरबीआई के समृद्ध इतिहास और उपलब्धियों का प्रतीक है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 90 रुपए का स्मारक सिक्का लॉन्च किया। पीएम मोदी ने कहा- 21वीं सदी में इनोवेशन का बहुत महत्व रहने वाला है। इसलिए हमने अंतरिम बजट में इनोवेशन के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का रिसर्च फंड बनाया है। 'कटिंग एज टेक्नोलॉजी' पर जो प्रपोजल आएंगे, जो लोग इस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, हम उनके लिए कैसे प्रीपेयर हों, ये सोचना बहुत आवश्यक है।

● ज्ञानवापी व्यास तहखाने में पूजा पर रोक लगाने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश

पूजा और नमाज दोनों जारी रहे

वाराणसी (एजेंसी)। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के व्यास तहखाने में पूजा के खिलाफ मस्जिद कमेटी की याचिका पर सोमवार (1 अप्रैल) को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में वाराणसी जिला कोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा था, जिसमें हिंदुओं को ज्ञानवापी मस्जिद के दक्षिणी तहखाने 'व्यास तहखाना' के अंदर देवताओं की पूजा करने की इजाजत दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी दक्षिणी तहखाने में हिंदू पक्ष के पूजा करने की यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया।

म.प्र. भोजशाला में चल रहे सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट का 'वैज्ञानिक सर्वे' पर रोक लगाने से इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला परिसर के चल रहे 'वैज्ञानिक सर्वे' पर रोक लगाने से मना कर दिया। हालांकि कोर्ट ने निर्देश दिया कि ऐसी कोई खुदाई नहीं की जाएगी।

सभी विभाग चुनाव से संबंधित व्यवस्थाएं समय-सीमा में करें

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री राजन ने दिये निर्देश

भोपाल (नप्र)। सभी विभाग चुनाव से संबंधित सभी व्यवस्थाएं समय-सीमा में सुनिश्चित करें। सभी विभागों में चुनाव संबंधी तैयारियों के लिये नियुक्त नोडल अधिकारी इन व्यवस्थाओं की सतत् मॉनिटरिंग करें। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री अनुपम राजन ने यह निर्देश आज विभिन्न विभागों के चुनाव से संबंधित व्यवस्थाओं की तैयारियों की समीक्षा के दौरान दिये। श्री राजन ने गृह विभाग द्वारा किये जा रहे कार्यों की तैयारियों की समीक्षा करते हुए कहा कि चुनाव ड्यूटी के दौरान किसी सुरक्षा कर्मी की दुर्घटना होने पर उसके खाते में अतिशीघ्र प्रावधानित राशि पहुँचनी चाहिए। पुलिस डिप्लायमेंट प्लान शीघ्र तैयार करें। कानून व्यवस्था की दैनिक रिपोर्ट भेजें। मतदान एवं मतगणना दिवस पर शराब की बिक्री पर प्रतिबंध सुनिश्चित करें। अन्य प्रदेशों के करीब मध्यप्रदेश के पड़ोसी जिलों में भी मतदान एवं मतगणना के दिन शराब की बिक्री पर प्रतिबंध सुनिश्चित करने के लिये जरूरी कदम उठाएं।

एक साथ दिल्ली पहुंचे सीएम मोहन और पूर्व सीएम शिवराज

बीजेपी की मेनिफेस्टो कमेटी की बैठक में हुए शामिल

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान सोमवार को एक साथ दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर में भाजपा की केंद्रीय घोषणा पत्र समिति की बैठक में शामिल हुए। भाजपा की घोषणा पत्र (संकल्प पत्र) समिति में मप्र से दो सदस्य मुख्यमंत्री मोहन यादव और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी सदस्य बनाए गए हैं। उन्होंने मध्य प्रदेश की जनता से विभिन्न माध्यमों से लिए गए सुझावों को लेकर दिल्ली की बैठक में जानकारी दी।

राजनाथ सिंह ने की बैठक की अध्यक्षता- संकल्प पत्र समिति के अध्यक्ष रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस बैठक में मुख्य रूप से शामिल हुए। इस समिति में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और पीयूष गोयल सह संयोजक हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, भूपेंद्र यादव, अर्जुन मुंडा, स्मृति ईरानी, अर्जुन राम मेघवाल, ओपी धनखड़, अश्विनी वैष्णव, रविशंकर प्रसाद, सुशील मोदी, हेमंत बिस्वा शर्मा, केशव प्रसाद मौर्य सहित समिति के सदस्य बैठक में शामिल हुए।

भोपाल का तापमान
अधिकतम 36 °c
न्यूनतम 26°c

सुबह सवेरे

इंदौर ■ मंगलवार, 02 अप्रैल 2024

जो अग्नि हमें गर्मी देती है , हमें नष्ट भी कर सकती है ; यह अग्नि का दोष नहीं है।

चाणक्य नीति

संक्षिप्त समाचार

नेहरू के लिए कच्चाथीवू की अहमियत नहीं थी

नई दिल्ली (एजेंसी)। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कच्चाथीवू मसले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि ये ऐसा मुद्दा नहीं है, जो आज अचानक उठा है। ये मसला संसद

और तमिलनाडु में लगातार उठता रहा है, इस पर बहस हुई है। इस मसले पर मैंने मौजूदा मुख्यमंत्री को 21 बार जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि मई 1961 में तत्कालीन प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था, मैं इस छोटे से द्वीप को बिल्कुल भी महत्व नहीं देता और मुझे इस पर अपना दावा छोड़ने में कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। उनका रवैया ऐसा था कि जितना जल्दी कच्चाथीवू को श्रीलंका को दे दिया जाए, उतना बेहतर होगा। यही नजरिया इंदिरा गांधी का भी था।

कांग्रेस से 3500 करोड़ रुपए की टैक्स डिमांड

- सुप्रीम कोर्ट में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा- लोकसभा चुनाव तक कोई एक्शन नहीं लेंगे

नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (1 अप्रैल) को कांग्रेस के 3500 करोड़ की टैक्स डिमांड के खिलाफ याचिका पर सुनवाई की। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि लोकसभा चुनावों के मद्देनजर विभाग कांग्रेस के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेगा। हम चुनाव के दौरान किसी भी पार्टी के लिए परेशानी खड़ी नहीं करना चाहते।

मामले की सुनवाई जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच में हुई। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की दलील के बाद सुप्रीम कोर्ट ने केस की अगली सुनवाई जुलाई के लिए तय कर दी है। बेंच ने यह भी कहा कि 3500 करोड़ रुपए की मांग का इन अपीलों से कोई संबंध नहीं।

चीन ने अरुणाचल की 30 जगहों के नाम बदले

- 7 साल में चौथी बार ऐसा किया; अरुणाचल को फिर अपना हिस्सा बताया

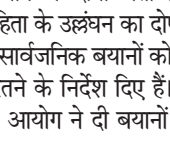

बीजिंग (एजेंसी)। चीन ने अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताकर वहां की 30 जगहों के नाम बदल दिए हैं। चीन की सिविल अफेयर मिनिस्ट्री ने इसकी जानकारी दी। हांगकांग मीडिया हाउस साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक, इनमें से 11 रिहायशी इलाके, 12 पर्वत, 4 नदियां, एक तालाब और एक पहाड़ों से निकलने वाला रास्ता है। हालांकि, इन जगहों के नाम क्या रखे गए हैं, इस बारे में जानकारी नहीं दी गई।

लोकसभा चुनाव 2024

भाजपा की चुनाव घोषणा समिति की पहली बैठक

- 2047 तक 'विकसित भारत' के रोडमैप पर चर्चा

नईदिल्ली (एजेंसी)। लोकसभा चुनाव की तारीखों के एलान के बाद से ही तमाम राजनीतिक दलों में घोषणा पत्र को लेकर कवायद तेज हो गई है। भाजपा ने 30 मार्च को चुनाव घोषणापत्र समिति का ऐलान किया था, जिसके अध्यक्ष भाजपा नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। सोमवार को भाजपा की चुनाव घोषणापत्र समिति की पहली बैठक हुई, जिसमें 'विकसित भारत' एजेंडे का रोडमैप केंद्र में रहा। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल से 1 जून के बीच होने हैं।

बैठक में विकसित भारत के रोडमैप पर चर्चा- गोयल- बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने पत्रकारों से कहा कि पार्टी को अपनी मिस्ड कॉल सेवा के माध्यम से 3.75 लाख से अधिक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐप (नमो) पर लगभग 1.70 लाख सुझाव मिले हैं। उन्होंने कहा कि बैठक में 2047 तक विकसित भारत के रोडमैप पर चर्चा की गई। हमारे घोषणापत्र के लिए लोगों की भागीदारी पीएम मोदी के नेतृत्व में उनके विश्वास और उनसे उनकी अपेक्षाओं को दर्शाती है।

पिछली बार भी राजनाथ सिंह ने ही संभाली थी कमान- गौरतलब है कि 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 20 सदस्यों वाली मैनिफेस्टो कमेटी बनाई थी। तब उसकी कमान तत्कालीन गृहमंत्री राजनाथ सिंह को ही सौंपी गई थी। इस बार भी उन्हें ही यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। कहा जा रहा है कि भाजपा अप्रैल के दूसरे हफ्ते में घोषणापत्र जारी करने की योजना बना रही है।

एक्टर से सांसद बने अनुभव मोहंती भाजपा में हुए शामिल

बीजेडी से दिया था इस्तीफा, बोले- घुटन महसूस कर रहा था

नईदिल्ली (एजेंसी)। बीजद के लोकसभा सांसद अनुभव मोहंती ओडिशा में सत्तारूढ़ पार्टी छोड़ने के कुछ दिनों बाद सोमवार को भाजपा में शामिल हो गए, उन्होंने कहा कि वह वहां 'घुटन' महसूस कर रहे थे। भाजपा में उनका स्वागत करते हुए, इसके राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने कहा कि विपक्ष एक साथ आकर अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सफल नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि मुझे अपने नेता से कोई शिकायत नहीं है। मेरे भाजपा में शामिल होने का कारण यह है कि हमारा देश जिस गति से विकास कर रहा है। भारत को दुनिया का नंबर एक देश बनाने का प्रयास किया जा रहा है।

न्यूरो-विविधता जागरूकता को बढ़ावा देने अभियान की घोषणा

भोपाल। ACAT आधार परामर्श और चिकित्सा परिषद एक सामाजिक विकास संगठन है, जो आवश्यकता में व्यक्तियों और परिवारों को परामर्श, चिकित्सा, और सहायता सेवाएं प्रदान करने के लिए समर्पित है। समावेशिता और न्यूरो-विविधता के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, ACAT को एक सहानुभूति और समझदार समाज के लिए काम करने का लक्ष्य है।

ACAT आधार परामर्श और चिकित्सा परिषद अपने आगामी यात्रा की शुरुआत के लिए एक Curtain Raiser के इवेंट की घोषणा करता है, जो समावेशिता को बढ़ावा देने और न्यूरो-विविधता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक साल लंबे अभियान की शुरुआत करेगा। यह पहल 27 सितंबर, 2024 को संगठन की 20वीं वर्षगांठ के लिए योजित की जाएगी।

2 अप्रैल, 2024 को योजित होने वाले Curtain Raiser इवेंट को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस पर आयोजित किया जाएगा, और यह भोपाल के ईपीसीओ कॉन्फ्रेंस हॉल में होगा। विशिष्ट मेहमान इस मौके को गौरवित करेंगे, और इवेंट का थीम 'लाइट अप ब्लू' होगा, जो संगठन की न्यूरो-विविधता के बारे में जागरूकता और स्वीकृति को बढ़ाने के लिए है। इवेंट की मुख्य विशेषता संगठन के विभिन्न आवश्यकताओं वाले व्यक्तियों के समर्थन को प्रतिष्ठित करने के रूप में 10 बच्चों का ग्रेजुएशन एंड मेनस्ट्रीमिंग समारोह किया जाएगा ।

कर्टेन रेजर इवेंट में एक डॉक्यूमेंट्री का अनावरण भी होगा, जो संगठन के 20 साल के उत्कृष्ट यात्रा को चित्रित करेगा, जो संगठन के स्थापना दिवस को मनाने के लिए निर्धारित है। साल भर तक, ACAT ने अपने दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए एक श्रृंखला इवेंट्स की योजना बनाई है।

मई में, संगठन डिजिटल आदि की बढ़ती चुनौती का सामना करने के लिए पहले बैच के Digital Champions को फेलोशिप और प्रमाणपत्र देगा। अभियान को आगे बढ़ाते हुए, जून में, "On the Career Path" एक इवेंट का आयोजन किया जाएगा जिसमें छात्रों को उनके भविष्य के करियर के लिए जागरूकता और अवसर प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा, संगठन जुलाई में डॉक्टर्स डे, अगस्त में पर्यावरण दिवस और स्वतंत्रता दिवस का आयोजन करेगा, जो समाज के कल्याण और पर्यावरणीय संवेदनशीलता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

साल भर के अभियान को ACAT के 20वें संस्थापन दिवस के ग्रैंड सेलिब्रेशन को सितंबर 2024 साथ समाप्त किया जाएगा, जो इस मिशन के अटूट समर्पण के दो दशक को चिन्हित करेगा।

रबीन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय को मिला 'यूनिवर्सिटी ऑफ द ईयर अवॉर्ड'

भोपाल। हाल ही में दिल्ली शहर में आयोजित हुए इंडिया एजूकेशन अवॉर्ड्स में रबीन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय को 'यूनिवर्सिटी ऑफ द ईयर' अवॉर्ड से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान विश्वविद्यालय को उच्च शिक्षा में निरंतर उत्कृष्ट कार्य, स्ट्रैटेजी और इनोवेशन के लिए प्रदान किया गया है। समारोह में यह सम्मान रबीन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉ. विजय सिंह ने प्राप्त किया। पुरस्कार को प्राप्त करते हुए डॉ. विजय सिंह ने कहा कि विश्वविद्यालय में हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरुप ऐसा वातावरण तैयार कर रहे हैं जहां विद्यार्थियों में कुशल कौशल सहित उद्यमिता एवं भारतीय संस्कृति का विकास हो। इस उपलब्धि पर विश्वविद्यालय के कुलाधिपति श्री संतोष चौबे जी ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रारंभ से ही गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक संस्कृति को बढ़ावा देता आ रहा है। आरएनटीयू देश का पहला कौशल आधारित विश्वविद्यालय है। विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश का एकमात्र विश्वविद्यालय है जहां नीति आयोग के अटल इन्क्यूबेशन सेंटर का सफल संचालन किया जा रहा है। विश्वविद्यालय की प्रो-चांसलर डॉ. अदिती चतुर्वेदी वत्स और कुलपति डॉ. रजनी कांत जी ने भी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि विश्वविद्यालय लगातार उत्कृष्टता हासिल करने का प्रयास कर रहा है। विश्वविद्यालय शोध और नवाचार के क्षेत्र में भी उत्कृष्ट कार्य कर रहा है।

प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में बोले सीएम योगी

मुझे डर नहीं लगता, पब्लिक की सुरक्षा में मेरी सुरक्षा

नोएडा (एजेंसी)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जनता-जनार्दन खुश तो हम खुश। हमारे लिए इससे अधिक खुशी कुछ भी नहीं। लोग कहते हैं कि अपराधियों पर कार्रवाई करते हैं, डर नहीं लगता है। मैं कहता हूं कि पब्लिक की सुरक्षा में मेरी सुरक्षा

निहित है। एक सरकार थी जो कर्फ्यू लगाती थी, एक सरकार है जो शानदार कांवड़ यात्रा निकाल रही है। उन्हें कर्फ्यू प्यारा था, हमें जनता की खुशहाली प्यारी है। 10 वर्ष में देश के अंदर बना सकारात्मक वातावरण अभिभूत करने वाला है। एक तरफ स्वार्थी परिवार है, जो गौतमबुद्ध नगर को अभिशप्त बना लेता है तो दूसरी तरफ मोदी का परिवार है, जो कुर्सी की चिंता किए बिना नोएडा में विकास कार्य करता है। ये बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहीं। वे सोमवार को जीएल बजाज ऑडिटोरियम, नॉलेज पार्क में आयोजित प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।

पहली बार भारत का रिकॉर्ड 21 हजार करोड़ का रक्षा निर्यात

रूस, इजरायल समेत 84 देशों को बेचे उत्पाद

नई दिल्ली (एजेंसी)। देश का रक्षा निर्यात पहली बार बेतहाशा बढ़ा है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में रक्षा निर्यात 21 हजार करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इंटरनेट मीडिया पर देश की एक बहुत बड़ी सफलता की घोषणा कर बताया कि

भारत ने 84 देशों को अपने रक्षा उत्पाद बेचकर यह चमत्कारिक लगने वाला लक्ष्य हासिल किया है। इस दिशा में सिर्फ एक वित्त वर्ष में 32.5 प्रतिशत का उछाल आया है।

- **50 कंपनियों ने दिया अहम योगदान-** उन्होंने कहा कि रक्षा निर्यात बढ़ाने के लिए न सिर्फ भारत के रक्षा निर्माण क्षेत्र को प्रेरित किया गया बल्कि तकनीकी रूप से आधुनिक बनाने की सुविधाएं बढ़ाई गई हैं। इससे सरकारी और निजी क्षेत्र की कंपनियों के लिए उत्साहजनक वातावरण बन गया है। भारत के रक्षा निर्यात की इस सफलता की कहानी को अंजाम तक पहुंचाने में करीब 50 भारतीय कंपनियों ने अहम योगदान दिया है।

कांग्रेस सीईसी की बैठक हुई, सोनिया-खड़गे रहे मौजूद

- तेलंगाना के उम्मीदवारों की लिस्ट आ सकती है; अब तक 212 कैंडिडेट्स का ऐलान

नई दिल्ली (एजेंसी)। कांग्रेस सोमवार (1 अप्रैल) को तेलंगाना के प्रत्याशियों का ऐलान कर सकती है। कांग्रेस मुख्यालय में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, केसी वेणुगोपाल, तेलंगाना के

मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी समेत कई कांग्रेस नेता शामिल रहे। यह पार्टी की दसवीं लिस्ट होगी। कांग्रेस अब तक देशभर में 212 उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। इसके पहले 29 मार्च को कांग्रेस ने नौवीं लिस्ट का ऐलान किया था। इसमें राजस्थान के 2 कैंडिडेट के नाम बदले गए और कर्नाटक से 3 उम्मीदवारों का नाम घोषित किया गया था।

भाजपा सांसद दिलीप घोष और कांग्रेस नेता श्रीनेत को आयोग ने लगाई फटकार, दी चेतावनी

नई दिल्ली(एजेंसी)। चुनाव आयोग ने भाजपा सांसद दिलीप घोष और कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत को उनके महिलाओं के खिलाफ दिए आपत्तिजनक बयान को लेकर फटकार लगाई है। आयोग ने साथ ही दोनों नेताओं को चेतावनी दी है कि वे अपने बयानों को लेकर सावधान रहें और आयोग की अब उन पर चुनाव के दौरान खास नजर रहेगी। चुनाव आयोग ने दोनों नेताओं को चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का दोषी माना है और भविष्य में सार्वजनिक बयानों को लेकर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं।

आयोग ने दी बयानों को लेकर सावधानी बरतने की चेतावनी

भाजपा सांसद दिलीप घोष और कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत के बयानों को लेकर चुनाव आयोग ने दोनों नेताओं को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। अपने जवाब में दोनों नेताओं ने स्वीकार किया कि उन्होंने चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया और निजी हमले किए। जवाब मिलने के बाद आयोग ने दोनों नेताओं को चेतावनी दी है कि अब वे आगे से सार्वजनिक बयानों को लेकर सावधानी बरतें। साथ ही चुनाव के दौरान दोनों नेताओं के बयानों की चुनाव आयोग द्वारा विशेष समीक्षा की जाएगी। आयोग ने कहा कि वह आश्वस्त है कि दोनों नेताओं ने निम्न स्तर का व्यक्तिगत हमला किया और यह आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन है।

मार्च में 1.78 करोड़ रुपये का जीएसटी कलेक्शन

सालाना आधार पर 11.5 प्रतिशत बढ़ा आंकड़ा

नई दिल्ली (एजेंसी)। मार्च में जीएसटी कलेक्शन में 11 प्रतिशत से अधिक का इजाफा हुआ है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि वस्तु व सेवा कर (जीएसटी) संग्रह मार्च में सालाना आधार पर 11.5 प्रतिशत बढ़कर 1.78 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया है। वित्त मंत्रालय के अनुसार यह अब तक का दूसरा सबसे बड़ा जीएसटी कलेक्शन है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल 20.14 लाख करोड़ रुपये का जीएसटी संग्रह हुआ- अप्रैल 2023 से मार्च 2024 के वित्तीय वर्ष के लिए सकल जीएसटी संग्रह 20.14 लाख करोड़ रुपये रहा, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 11.7 प्रतिशत अधिक है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए औसत मासिक सकल संग्रह 1.68 लाख करोड़ रहा, जो पिछले वित्तीय वर्ष के 1.5 लाख करोड़ से अधिक है। मार्च 2024 के लिए सकल वस्तु और सेवा कर जीएसटी राजस्व सालाना आधार पर 11.5 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 1.78 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया। यह जीएसटी संग्रह का अब तक का दूसरा सबसे बड़ा आंकड़ा है। मंत्रालय के अनुसार कुल जीएसटी संग्रह में यह इजाफा घरेलू लेनदेन से जीएसटी संग्रह में 17.6 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि के कारण हुआ है।

इंदौर में दो लड़कियों की दिनदहाड़े किडनैपिंग की घटना में हुआ खुलासा

नई-नवेली सहेली और उसके अनजान दोस्त के साथ दिनभर ऑटो में घूमी

इंदौर (नप्र)। इंदौर में नाबालिग लड़की और एक युवती को किडनैप करने और उन्हें पुलिस द्वारा बचाने की घटना में नया मोड़ आ गया है। पुलिस सूत्रों का दावा है कि दोनों लड़कियां नशे की आदी भी हैं। इनके कारण दो थानों की पुलिस कई घंटे परेशान होती रही। आखिरकार केस दर्ज करना पड़ा। बावजूद, ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब दोनों पीड़ितों ने पुलिस को भी नहीं दिए हैं। दरअसल, घटना खजराना चौराहे पर रविवार शाम करीब 6:30 बजे की है। बंगाली चौराहा जाने वाली रोड पर दो युवकों के साथ बाइक पर एक युवती थी। उसने अचानक कांस्टेबल विजय को इशारा कर मदद मांगी। सूबेदार बृजराजसिंह के साथ विजय ने पीछा कर बाइक को 300 मीटर दूर बंगाली चौराहा ओवरब्रिज से पहले रोक लिया। आरोपी लक्की चौहान निवासी मालवीय नगर और शुभम गोयल निवासी सुंदर नगर के चंगुल से उसे बचाया। उसके साथ एक और लड़की अन्य गाड़ी पर थी, उसे भी थाने लाए। टीआई संजीव श्रीवास्तव ने बात की। इसके बाद उसे तिलक नगर भिजवाया। टीआई अजय नायर ने रात में पीड़िता की कहानी के बाद आरोपी लक्की, शुभम गोयल और शुभम मिश्रा पर एफआईआर दर्ज कर ली। लक्की और शुभम गोयल को पकड़ा था जबकि तीसरा आरोपी शुभम मिश्रा फरार है। आरोपी लक्की चौहान

लिस्टेड गुंडा है। उस पर हत्या सहित 10 से ज्यादा केस दर्ज हैं। पकड़े जाने के बाद दोनों आरोपियों ने भागने की कोशिश की लेकिन लोगों ने घेराबंदी कर उन्हें पकड़ा और फिर से पुलिस के हवाले किया।

रेस्क्यू तक की अनसुनी कहानी, पीड़िता की जुबानी...

खातीपुरा में अपनी नानी के साथ रहती हूं। दसवीं पढ़ रही है। काफी दिनों से एक बीमारी से जूझ रही थी। उसके लिए बुरहानपुर के वैद्य से दवा मंगवाई थी। दवा लेने के लिए मुझे रविवार दोपहर 3 बजे सरवटे बस स्टैंड जाना था। सरवटे स्टैंड के लिए घर से निकली और दोपहर 2 बजे गौरी नगर पहुंची। यहां मुझे एक अन्य 19 साल की युवती मिली। उसने मेरे बारे में जानकारी ली। मेरे से कहा दोस्ती करोगी तो मैंने उससे दोस्ती की और कहा कि दवाई लेने सरवटे स्टैंड जा रही हूं। उसने कहा कि मैं तुम्हें अपने दोस्त की ऑटो रिक्शा से सरवटे स्टैंड ले चलती हूं। उसने अपने दोस्त छनू उर्फ मक्कू को कॉल किया और ऑटो रिक्शा बुलवाया। दोनों लड़कियां उसी ऑटो रिक्शा में बैठकर स्टैंड पहुंची। बसवाले से दवा लेने के बाद एलआईजी पर साथ आई 19 वर्षीय युवती का एक अन्य दोस्त राज मिला। मक्कू यहां से चले गया। इसके बाद तीनों नजदीक ही पैदल एलेक्सा मैदान पहुंचे। शाम करीब 6 बजे हम तीनों (पीड़िता, युवती और राज) गार्डन में बैठकर बात कर रहे थे। वहां दो बाइक से तीन लड़के आए। तीनों ने हमसे विवाद किया। कहा कि यहां क्या अश्लीलता फैलाने आए हो। उसके बाद हमारे साथ बैठ गए और युवती के दोस्त राज को मारपीट कर भगा दिया। इसके बाद हम दोनों लड़कियों को अपनी बाइक पर बैठकर साथ चलने के लिए कहा। हमें धमकाकर कहा कि हम जहां कहते हैं, चलो। इससे हम काफी डर गईं। एक बाइक पर दो लड़कों ने बीच में मुझे बैठाया। एक अन्य बाइक पर तीसरे लड़के ने युवती को बैठाया। वे शहर में कई जगह घुमाने लगे। बाइक पर बैठाने के बाद दोनों युवक मुझसे गंदी हरकत करते रहे। चौराहे पर युवती ने पुलिसकर्मियों को देखकर शोर मचा दिया। इस पर पुलिसकर्मियों ने पीछा किया और सबसे पहले हमारी वाली बाइक रोकी। मुझे साथ ले जा रहे दोनों लड़कों से नाम पते पूछे। युवती के शोर मचाने पर दूसरी बाइक से उसे ला रहा संजय मिश्रा नाम का लड़का भाग गया। इसके बाद में पुलिस से मुझसे बात करके नानी को बुलाया। वहां से हमें थाने भेजा गया।(जैसा पीड़िता ने पुलिस को बताया)।

पुलिस के इन 5 सवालों का जवाब नहीं दे पाई लड़की और युवती

पहला - दोनों युवतियों के बीच एक ही मुलाकात में इतनी गहरी दोस्ती कैसे हो गई? क्या आप दोनों एक-दूसरे को पहले से जानती थीं?

दूसरा - दवा लेने के बाद युवती सीधे घर क्यों नहीं गई? नए दोस्तों के साथ अनजान ऑटो रिक्शा में बैठकर क्यों घूमती रही?

तीसरा - प्रेस कॉम्प्लेक्स के गार्डन में क्यों गईं? वहां सहेली और उसके दोस्त के साथ बैठकर क्या कर रही थी?

चौथा - दो बाइक पर आए तीन युवकों ने ऐसा क्या देखा कि उन्होंने तुम पर अश्लीलता फैलाने के आरोप लगाए?

पांचवां - जब युवकों ने बाइक पर बैठने के लिए धमकाया तो विरोध क्यों नहीं किया? तभी शोर क्यों नहीं मचाया?

आईआईएम इंदौर का 25वां दीक्षांत समारोह

7 कोर्स के 802 छात्रों को मिली डिग्री; इस साल सबसे अधिक 18 पीएचडी

इंदौर (नप्र)। आईआईएम इंदौर का 25वां दीक्षांत समारोह हुआ। इसमें 7 कोर्स के 802 छात्रों को डिग्री प्रदान की गई। इस साल संस्था द्वारा सर्वाधिक छात्रों को पीएचडी दी गई, जिसमें रेगुलर पीएचडी 18 को और एग्जीक्यूटिव पीएचडी 3 प्रतिभागियों को दी गई। इस साल डिग्री प्राप्त करने वालों में लड़कियां 281 और लड़के 521 रहे। 12 छात्रों को 13 गोल्ड मैडल भी प्रदान किए गए, जिसमें एक छात्रा स्वर्णिमा आनंद को 2 गोल्ड मैडल दिए गए। मुख्य अतिथि मॉर्गन स्टैनले इंडिया के एमडी रिधम देसाई थे। उन्होंने छात्रों को खुद का स्टार्टअप शुरू करने के लिए कहा। इसके साथ ही उन्होंने अर्थव्यवस्था के 5 ऐसे क्षेत्र बताए, जहां आने वाले समय में अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने छात्रों से कहा यदि नौकरी करते हुए भी अपना बिजनेस करना चाहते हैं तो स्टॉक मार्केट में पहले दिन से निवेश कीजिए। और ये निवेश अनुमान के आधार पर नहीं, बल्कि इस विचारधारा से कीजिए जैसे आप उस बिजनेस के पार्टनर हैं। अध्यक्षता आईआईएम इंदौर के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष एमएम मुरुगप्पन और निदेशक प्रो. हिमांशु राय ने की। मुरुगप्पन ने बताया आईआईएम इंदौर में बढ़ती छात्रों की संख्या को देखते हुए जल्द ही कैंपस के इन्फ्रास्ट्रक्चर में भी बढ़ोतरी की

जाएगी।

समारोह में पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन मैनेजमेंट, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, फाइव ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट, एग्जीक्यूटिव पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन मैनेजमेंट, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम फॉर वर्किंग एग्जीक्यूटिव इन मुंबई, डॉक्टोरल प्रोग्राम इन मैनेजमेंट और एग्जीक्यूटिव डॉक्टोरल प्रोग्राम इन मैनेजमेंट के छात्रों को डिग्री दी गई। आईपीएम के बीए डिग्री प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को भी डिग्री प्रदान की गयी।

इन्हें मिले संस्था की तरफ से गोल्ड मेडल

उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए आईआईएम के जिन टॉपर को मेडल मिले, उनमें पीजीपी प्रोग्राम के मेरुल शाह, अनुभव कर, अभिषेक जैन और प्राची काकानी हैं। वहीं पीजीपी एचआरएम से शिखा गुणवाल को गोल्ड मैडल दिया गया। 5 वर्षीय आईपीएम प्रोग्राम में स्वर्णिमा आनंद को 2 गोल्ड मैडल और लोकेश सांगेवार को एक गोल्ड मैडल दिया गया। इसके अतिरिक्त सांग्पो लुईस कश्यप, प्राची जैन, सुरभि सिंह, पिनक मेंगले और अल्बर्ट जोसफ को भी गोल्ड मेडल दिया गया।

गोल्ड मैडलिस्ट की स्वर्णिम सीख

स्टार्टअप में मदद करूंगी

मैंने ह्यूमन रिसोर्सेज में डिग्री ली है और आगे जाकर मैं खुद की एचआर कंसल्टिंग फर्म खोलना चाहती हूं। मैं स्टार्टअप में सहयोग करना चाहती हूं, जिससे वो एनालिटिक्स की मदद से अलग चीजों को मैनेज कर सकें।

- शिखा गुणवाल, पीजीपी एचआरएम टॉपर

इंदौर में कूलर के गोदाम में लगी आग

तंग बस्ती में लोगों ने जुगाड़ से बुझाई आग

इंदौर (नप्र)। इंदौर के नयापुरा इलाके में एक कूलर के गोदाम में आग लग गई। यहां आग की लपटें देख फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई।

सूचना के बाद दमकलें मौके पर पहुंची। यहां आग पर काबू कर लिया गया है। फायर ब्रिगेड के मुताबिक कोतवाली इलाके के नयापुरा में आग लगने की सूचना मिली थी। यहां एक टैंकर पानी डालकर आग पर काबू किया गया। नयापुरा में अधिकतर गोदाम बने हुए हैं। जहां संकरी गलियां हैं। यहां दमकल के पहुंचने के पहले ही लोगों ने पाइप डालकर दोनों तरफ से आग पर काबू पाने की कोशिश की थी।

एमजीएम कॉलेज के स्टूडेंट्स ने दिया धरना

40 छात्रों को प्रेक्टिकल में फेल करने पर दोबारा जांच की मांग

इंदौर (नप्र)। इंदौर के एमजीएम कॉलेज के स्टूडेंट ने सोमवार सुबह कॉलेज के मेन गेट पर धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने कॉलेज प्रबंधन पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की। स्टूडेंट का कहना है कि एमबीबीएस फाइनल ईयर के करीब 40 स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल में फेल कर दिया गया है। इन स्टूडेंट्स को थ्योरी में अच्छे नंबर मिले थे।इन स्टूडेंट्स का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जाए। कॉलेज प्रबंधन ने आश्वासन तो दे दिया लेकिन अब तक मामले की जांच शुरू नहीं की गई है। इसके चलते आक्रोश स्टूडेंट्स धरने पर बैठ गए। कॉलेज प्रबंधन का कहना है कि इसकी जांच के लिए एक कमेटी गठित की गई है।

एमपीपीएससी ने अप्रैल-मई की परीक्षाएं जून में शिफ्ट की

सहायक प्राध्यापक सहित अन्य परीक्षाओं का ये है शेड्यूल

इंदौर (नप्र)। मध्यप्रदेश लोकसेवा आयोग (एमपीपीएससी) ने लोकसभा चुनाव के तहत अप्रैल-मई में परीक्षा की तारीख नहीं रखते हुए परीक्षा शेड्यूल को जून में शिफ्ट कर दिया है। जून में तीन परीक्षाएं होगी। 9 जून को 820 से अधिक रिक्त पदों के लिए सहायक प्राध्यापक की परीक्षा होगी। सहायक प्राध्यापक के साथ ही 129 खेल अधिकारी और 200 ग्रंथ पाल के पद भी हैं। पहले परीक्षा अप्रैल में होने वाली थी।राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 पहले अप्रैल में होना थी लेकिन लोकसभा चुनाव मतदान अलग-अलग चरणों में होने के कारण परीक्षाओं को आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया। परीक्षाएं सरकारी कॉलेजों में आयोजित होती है, वहां चुनावी गतिविधियों के कारण परीक्षा करवाने में आयोग को दिक्कतें आ रही थी। परीक्षाएं 23 जून को होगी। वहीं जून आखिर में राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा 2023 भी होगी। परीक्षा की तारीख 30 जून रहेगी। वहीं जुलाई से दिसंबर के बीच 9 अन्य भर्ती परीक्षा भी रखी है। इसकी जानकारी आयोग ने पोर्टल पर दी है। इनका शेड्यूल पोर्टल पर आयोग ने अपलोड किया है।

इंदौर के राउ चौराहे पर माता-पिता की हादसे में मौत

पढ़ाई कर रहे बच्चों को ब्याज सहित 60 लाख देने के आदेश

इंदौर (नप्र)। कोदरिया से इंदौर आ रहे दंपती को राऊ स्थित गोल चौराहे के पास ट्रक ने ऐसी टक्कर मारी कि दोनों की मौत हो गई। कोदरिया में आलू चिप्स का कारखाना संचालित करने वाले श्याम और पत्नी प्रेमदेवी बच्चों को जल्द ही लौटने का बोलकर घर से निकले थे। कोर्ट ने बच्चे और दादा-दादी को जीवन यापन के लिए ब्याज सहित 60 लाख रुपए से अधिक दिए जाने के आदेश जारी किए हैं। घटना 31 मार्च 21 को सुबह की है। दोनों बेटे रितिक और आदर्श स्कूल, कालेज में पढ़ाई कर रहे हैं। वहीं दादा गिरधारीलाल और दादी नथियादेवी की जिम्मेदारी भी पोतों पर आ गई।

घर-एम्बुलेंस पर पत्थर फेंके

पुलिस ने कहा मामला आपसी लेनदेन का, तीन पर एफआईआर

इंदौर(नप्र)। इंदौर के द्वारकापुरी में घर पर पथराव करने, एम्बुलेंस के कांच फोड़ने और महिला को धमकाने के मामले में तीन लोगों पर केस दर्ज किया है। आरोपी रुपए के लेनदेन में घर पहुंचे और पीड़ित परिवार पर हमला किया। इस दौरान आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। लेकिन थाने के स्टाफ ने विवाद की जानकारी टीआई को नहीं दी। दूसरे दिन पीड़ित परिवार थाना प्रभारी के पास पहुंचा और पूरा घटनाक्रम बताया। टीआई ने मामले की गंभीरता को देखते हुए केस दर्ज करने के आदेश दिए हैं।द्वारकापुरी पुलिस ने महिला सोनू बिरला निवासी विदुर नगर की शिकायत पर विशाल पुत्र भैया लाल, अश्विन भालसे निवासी विदुर नगर और मोहित बंकट निवासी अहीरखेड़ी पर धमकाने और तोड़फोड़ के मामले में केस दर्ज किया है। सोनू ने बताया कि वह प्रेम प्रॉपर्टी ऑफिस के सामने रहते हैं। शनिवार को विशाल अपने साथियों को लेकर घर पहुंचा और पति कृष्णा के बारे में पूछने लगा। मैंने कहा वे घर पर नहीं हैं तो विशाल और उसके साथ आए बदमाशों ने घर के शीशे और एम्बुलेंस पर पथराव कर दिया। यह देखकर आसपास के लोग भी इकट्ठा हो गए। बाद में पुलिस को जानकारी दी।

इंदौर से शारजाह-दुबई फ्लाइट्स का समय बदला

35 मिनट से एक घंटे बाद आएगी-जाएगी

इंदौर (नप्र)। इंदौर एयरपोर्ट पर दुबई और शारजाह की फ्लाइट्स पर समर शेड्यूल लागू हो गया है। शेड्यूल के अनुसार इंदौर से दुबई और शारजाह जाने वाली उड़ानों के समय में बदलाव हुआ है। करीब 30 से 1 घंटे तक फ्लाइट्स लेट आएंगी, जाएंगी।ट्रेवल एजेंट्स के अनुसार एयर इंडिया एक्सप्रेस द्वारा हर मंगलवार और रविवार को शारजाह-इंदौर-शारजाह फ्लाइट संचालित है। इसके अलावा गुरुवार को दुबई-इंदौर-दुबई के बीच उड़ान आती-जाती है। इंदौर से वापसी जाने वाली फ्लाइट दुबई और शारजाह में आधी रात को पहुंचाएगी। ऐसे में वहां होटल में महज 5 से 6 घंटे रुकने पर ही पूरे 24 घंटे का पैसा चुकाना पड़ेगा क्योंकि सुबह 10 बजे का चेकआउट रहता है।

काशी फ्लाइट में पहले दिन 70 यात्रियों ने किया सफर

इंदौर से काशी (वाराणसी) के लिए भी एक दिन पहले रविवार को उड़ान शुरू हुई थी। इस उड़ान में पहले दिन 72 सीटर विमान में 70 यात्री रवाना हुए। यह उड़ान सुबह 8.25 बजे वाराणसी के लिए रवाना हुई। वापसी में यह उड़ान रात 10.15 बजे इंदौर आएगी। इसके शुरू होने से काशी विश्वनाथ के दर्शन करने वालों को सुविधा मिलेगी। इसके अतिरिक्त राजकोट के लिए उड़ान का संचालन पूरी तरह से बंद हो गया है। सात महीने ही इस उड़ान का संचालन किया जा सका।

यह रहेगा नया शेड्यूल-यात्रियों को समय बदलने से होगा यह नुक़सान

नए शेड्यूल में पर्यटकों को असुविधा होगी। इंदौर से शारजाह उड़ान से जाने वाले पर्यटकों को अधिक परेशानी होगी। मध्यरात्रि के करीब उड़ान शारजाह पहुंचाएगी।

विदेशों में होटल चेक इन दोपहर दो बजे से होता है। यात्री रात 2 बजे वहां पहुंचेंगे। एयरपोर्ट से निकलकर होटल पहुंचते- पहुंचते रात की 3 बज जाएगी। होटल में सुबह 10 बजे चेक आउट टाइम होता है। इस तरह से कुछ घंटे सोने के लिए पूरे दिन का किराया यात्रियों को भरना पड़ेगा। दुबई में यही असर होगा।

कोर्ट में गवाही दी तो जान से मार देंगे

रणजीत हनुमान प्रभात फेरी में हत्या के गवाह छोटे भाई को धमकी ; मामला दर्ज

इंदौर (नप्र)। इंदौर में रणजीत हनुमान प्रभात फेरी के दौरान जान गंवाने वाले युवक के भाई को धमकी मिली है। 4 जनवरी को प्रभात फेरी के दौरान शुभम रघुवंशी की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। केस में छोटा भाई मुख्य गवाह है। धमकी देने वालों ने उसे कोर्ट में गवाही देने से मना किया है। नहीं मानने पर जान से खत्म कर देने की बात कही है। जिसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा। युवक की शिकायत पर पुलिस ने धमकाने वालों के खिलाफ केस दर्ज किया है।

मृतक के छोटे भाई को किस ने दी जान से मारने की धमकी

मृतक शुभम का छोटा भाई सौरभ पिता नरेंद्र रघुवंशी (23) निवासी गोमा की फेल मां रेखा रघुवंशी और दोस्त पीयूष कौशल के साथ तुकोगंज थाने पहुंचा। उसने पुलिस को बताया कि वो निजी ऑफिस में काम करता है। 3 महीने पहले बड़े भाई शुभम रघुवंशी की हत्या अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र में हुई थी। मामले में वो मुख्य गवाह है।

29 मार्च को रात करीब पौने दस बजे वो कोरी समाज की धर्मशाला के यहां किराना दुकान के पास खड़ा था। तभी अभिषेक शर्मा उर्फ नन्नी पंडित निवासी भागीरथपुरा गाड़ी से आया। वहां पास ही में बबलू और पीयूष भी खड़े थे। उनके सामने बोला कि अगर तूने कोर्ट में जाकर गवाही दी तो तुझे जान से खत्म कर देंगे। इसके साथ ही गालियां देने लगा। उसे रोकने की कोशिश की तो वो भाग गया। तुकोगंज पुलिस ने सौरभ की शिकायत पर आरोपी अभिषेक उर्फ नन्नी पंडित के खिलाफ धारा 153ए, 294 और 506 में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

इंदौर में दिल्ली के व्यापारी को आया कार का अलर्ट

मालिक ने होटल के नीचे आकर पुलिस को दी सूचना,गार्ड पकड़ाया

इंदौर (नप्र)। इंदौर के तुकोगंज इलाके में दिल्ली से आए एक व्यवसायी की कार पार्किंग से लापता हो गई। उन्हें मोबाइल पर अलर्ट आया। वह पार्किंग में आए तो कार तुकोगंज के आसपास के इलाके में घूमते मिली। उन्होंने डायल 100 को सूचना दी। जिसमें पुलिस ने लोकेशन से कार को पकड़ा। कार होटल का ही गार्ड चला रहा था। उसने कार के ट्रायल लेने की बात कही। पुलिस ने हिरासत में लिया है। उससे पूछताछ की जा रही है।तुकोगंज टीआई जितेन्द्र यादव ने बताया कि सुबह 4:30 बजे दिल्ली में रहने वाले मनीष कुमार के मोबाइल पर ट्रैकिंग सिस्टम पर मैसेज आया कि कार चल रही है। इसके बाद वह नीचे आए।

पार्किंग में कार नंबर देखी तो नहीं मिली। उन्होंने अपने मोबाइल से डॉयल 100 को सूचना की। जिसमें एसआई ओमप्रकाश रघुवंशी को मैसेज आया। कार की जानकारी निकाली तो वह गुलमोहर कॉलोनी पलासिया में खड़ी थी। जिसमें गार्ड विनोद पुत्र रामलखन तिवारी निवासी राय बरेली, उत्तर प्रदेश को पकड़ा। वह होटल का गार्ड निकला।

शादी के 3 महीने बाद मांगे डेढ़ करोड़

पति लेता था डिप्रेशन की दवाई ; पत्नी ने पूछा तो फ्लैट में बंधक बनाया

इंदौर (नप्र)। इंदौर के भंवरकुआ थाना में व्यापारी की बेटी ने दहेज प्रताड़ना की शिकायत की है। पुलिस ने तीन दिन पहले पति और सास-ससुर पर केस दर्ज किया है। भंवरकुआ पुलिस के मुताबिक इंद्रपुरी निवासी 28 साल की नवविवाहिता ने पति चिन्मय, ससुर अमोल और सास अंजलि पर दहेज प्रताड़ना सहित अन्य गंभीर धाराओं में केस दर्ज कराया है। दो पन्नों की एफआईआर में बहू ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। शादी के तीन महीने बाद ही मुझे गुलाम जैसा बंद फ्लैट में रखा गया।

मम्मी-पापा से बात नहीं कर सकूं इसलिए मेरा फोन ले लिया। मेरे फोन से सभी के नंबर भी डिलीट कर दिए। दिसंबर 2023 में शादी के बाद से मम्मी-पापा से एक बार भी नहीं मिली। पीड़िता ने खुद और अपने माता-पिता की जान का खतरा भी बताया।

पीड़ित बहू ने पुलिस को बताया कि...

- दिसंबर 2023 में उसकी शादी उज्जैन के आनंदम रिसोर्ट में हुई। माता-पिता ने इकलौती बेटी होने के कारण करीब 30 लाख रुपए खर्च किए। लाखों के जेवर भी उपहार में दिए।

शादी के बाद ससुराल वाले मुझे कुल देवी के दर्शन कराने गोवा ले गए। यहां पति चिन्मय छोटी-छोटी बातों पर मुझसे झगड़ा करने लगा। वह गोवा जाते समय पूरे रास्ते नशे की दवा लेता रहा।

- गोवा से पुणे वाले फ्लैट पर आए तो पता चला कि पति चिन्मय बहुत गुस्सा करता है। हर छोटी बात पर आपा खो देता है। इसी गुस्से को शांत करने के लिए सास अंजलि उसे दवाएं देती है। पति चिन्मय डिप्रेशन में रहता। वह ताकत बढ़ाने वाली दवाएं भी लेता था। यह बात भी शादी के समय ससुराल वालों ने हमसे छिपाई।

- मैंने इन दवाओं के बारे में पूछा तो सभी मुझसे विवाद करने लगे। विवाद इतना कि कई बार मन में सुसाइड करने का ख्याल आता। लेकिन मैं इन बातों को इग्नोर करती रही। सोचा नई-नई शादी है। आगे चलकर सब ठीक हो जाएगा।

- कुछ समय बाद पति चिन्मय ने मेरे मम्मी-पापा से बात करने लिए रोकना शुरू कर दिया। मेरा मोबाइल बार-बार चेक करता और उसे अपने पास रख लेता था। मम्मी-पापा से बात करती तो कहता कि उसके बारे में कुछ नहीं बताए। मुझे गुलाम की तरह फ्लैट में कैद करके रखा गया। मैं अपने मम्मी-पापा से बात नहीं कर सकूं इसलिए फोन से सबके नंबर हटा दिए। दिसंबर 2023 में शादी के बाद मम्मी-पापा से एक बार भी नहीं मिली। मैं आगे पढ़ना चाहती थी, लेकिन मुझे पढ़ने नहीं दिया। मेरी नौकरी भी छुड़वा दी। पिछले महीने 23 फरवरी को इंदौर में मायके पक्ष में एक रिश्तेदार की मौत हो गई। मुझे उनके यहां बैठने आना था। लेकिन पति ने आने नहीं दिया।

पति कहता- तुम माता-पिता की इकलौती बेटी..उनसे कहो प्रॉपर्टी बेचकर डेढ़ करोड़ दें

पीड़िता ने बताया कि पति मेरे चरित्र पर संदेह करने लगा। पढ़ाई को लेकर अपशब्द कहे। मुझसे बार-बार कहता कि अपने मां-बाप की इकलौती बेटी हो। पूरी संपत्ति की वारिस हो। इसलिए अपने मम्मी-पापा से कहो कि वे संपत्ति बेचें और मुझे डेढ़ करोड़ रुपए दें। मैं फैक्ट्री डालना चाहता हूं। इसके लिए मुझे जमीन खरीदना है।

संपादकीय

कच्चातिवू मुद्दा उछालने के मायने

देश में जारी लोकसभा चुनाव प्रक्रिया के बीच पांच दशक पुराने कच्चातिवू द्वीप का मुद्दा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भले ही राजनीतिक लाभ की दृष्टि से उछाला हो, लेकिन इसे अब उठाने का देश की विदेश नीति और पड़ोसी देशों के साथ भारत के रिश्तों पर क्या असर पड़ेगा, यह भी गंभीरता से सोचा जाना चाहिए। देश के धुर दक्षिण में भारत की समुद्र तटीय सीमा से पाक जलडमरू मध्य में स्थित यह छोटा सा द्वीप 1974 में भारत ने श्रीलंका को सौंप दिया था। तब देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। यह द्वीप श्रीलंका को क्यों सौंपा इस पर अब राजनीति हो रही है। खास बात यह है कि यह मामला सीधे तौर पर तमिलनाडु से जुड़ा है इस राज्य में पहले ही दौर में यानी 19 अप्रैल को वोट डलने हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को एक ट्वीट कर सभी को चौंका दिया कि नए तथ्य बताते हैं कि कैसे कांग्रेस ने कच्चातिवू द्वीप श्रीलंका को दे दिया। इससे सभी भारतीयों में गुस्सा है और लोगों के दिमाग में फिर से ये बात साफ़ हो गई है कि वह कांग्रेस पर यकीन नहीं कर सकते। भारत की एकता को कमज़ोर करना, भारत के हितों को नुकसान पहुंचाना कांग्रेस के 75 साल के कामकाज का तरीका रहा है। मेरठ में अपनी चुनाव सभा में मोदी ने कहा कि ये इंडिया गठबंधन के लोग देश की एकता को तोड़ते रहे हैं। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में समुद्र में एक टापू है- कच्चातिवू द्वीप सुरक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये देश की आज़ादी के समय भारत के साथ था। लेकिन चार-पांच दशक पहले इन लोगों ने कह दिया कि ये द्वीप फालतू है, ज़रूरी ही नहीं है। इस तरह इंडी अलायंस के गठबंधन के लोगों ने मां भारती का एक अंग काट दिया। एक अंग्रेजी अखबार ने एक आरटीआई के हवाले से रिपोर्ट छापी, जिसमें दावा किया कि 1974 में भारत सरकार के 'ढुलमुल रवैये' के कारण ये द्वीप श्रीलंका के पास चला गया। ये आरटीआई तमिलनाडु के बीजेपी चीफ़ के. अन्नामलाई ने दायर की थी, जिसके जवाब में ये जानकारी सामने आई। मामला तूल पकड़ते ही विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी कच्चा तिवू द्वीप पर प्रेस कान्फ्रेंस कर कहा कि डीएमके और कांग्रेस ने ऐसे बर्ताव किया है कि सबकुछ अब केंद्र सरकार के हाथ में है और उन्होंने कुछ किया ही नहीं। उन्होंने कहा कि जून 1974 में विदेश सचिव और तमिलनाडु के तत्कालीन मुख्यमंत्री करुणानिधि के बीच बात हुई। कच्चातिवू पर भारत और श्रीलंका के अपने अपने दावे हैं। तमिलनाडु कहता है कि ये राजा रामनाथ की रियासत थी। भारत का कहना है कि ऐसा कोई भी दस्तावेज़ नहीं है जिससे ये दावा हो कि कच्चातिवू श्रीलंका का हिस्सा रहा है। 1974 में भारत और श्रीलंका के बीच एक समझौता हुआ और मैरीटाइम सीमा दोनों देशों के बीच तय की गई। इस बीच कांग्रेस इस मुद्दे पर सफाई देने की मुद्रा में है तो तमिलनाडु में सत्तारूढ़ डीएमके कहा कि कि उसने 1974 में इस समझौते का विरोध किया था। उल्टे डीएमके ने पलटवार करते हुए पीएम मोदी से 'चीन की भारतीय ज़मीन पर कब्जे' को लेकर जवाब मांगा। हालांकि डीएमके ने इस द्वीप को लेकर 1991 में विधानसभा मे एक प्रस्ताव पारित कर कच्चातिवू को वापस भारत में शामिल करने की मांग की। मोदी के बयान का साफ संकेत इंडिया गठबंधन में शामिल कांग्रेस और डीएमके में फूट डालना और चुनाव में भाजपा के लिए इसका राजनीतिक लाभ लेना है। लेकिन इससे श्रीलंका से रिश्ते बिगड़ेंगे, उसका क्या?

नजरिया

नवीन कुमार

(मुंबई के वरिष्ठ पत्रकार हैं)

महाराष्ट्र : भाजपा की महायुती व विपक्ष की आघाड़ी में मनभेद

महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जिस तरह से सीटों को लेकर बंदरबांट वाला नजारा देखने को मिला उससे इतना तो स्पष्ट है कि भाजपा की महायुती और विपक्ष की आघाड़ी पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। ये बादल बता रहे हैं कि महायुती और आघाड़ी दोनों में भले ही मतभेद को नकारा जा रहा है लेकिन इन दोनों में मनभेद तो बने हुए हैं ही और इससे चुनाव के समय नकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं।

लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने शिवसेना (एकनाथ शिंदे गुट) और एनसीपी (अजित पवार गुट) के साथ महायुती बनाई है और विपक्ष की महाविकास आघाड़ी में शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट), एनसीपी (शरद पवार गुट) के साथ कांग्रेस शामिल है। राज्य की 48 लोकसभा सीटों के बंटवारे का खेल खेला जा रहा है। जाहिर-सी बात है कि महायुती में भाजपा खुद को बड़ा मानती है तो उसे ज्यादा सीटें चाहिए और उधर आघाड़ी में शिवसेना (उद्धव गुट) बड़े भाई की भूमिका में है इसलिए वह भी ज्यादातर सीटें अपने हिस्से में रखना चाहती है। इस बार के चुनाव में भी भाजपा और शिवसेना (उद्धव गुट) के बीच ही कड़ा मुकाबला होने की संभावना जताई जा रही है। भाजपा और शिवसेना का पारंपरिक गठबंधन टूट चुका है और एक-दूसरे को हराने के लिए डटे हुए हैं। 2019 के चुनावी नतीजे को देखें तो 48 सीटों में से भाजपा ने 23 और शिवसेना (अविभाजित) ने 18 सीटें जीती थी। एनसीपी (अविभाजित) 4 और कांग्रेस एक सीट पर ही सिमट गई थी।

भाजपा के सामने एक ही लक्ष्य है नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। इसके लिए भाजपा की ओर से अपील की जा रही है कि हर सीट पर मोदी को वोट देना है यानी कि हर सीट पर मोदी ही उम्मीदवार हैं। मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए मोदी की गारंटी वाला जुमला को भी प्रचारित किया जा रहा है। जब मोदी ही गारंटी हैं तो महायुती में शामिल दूसरी पार्टियों को अपनी क्षमता का पता कैसे चल पाएगा। ऐसे में सीटों के बंटवारे में भाजपा का हावी होना स्वाभाविक है और भाजपा ने शिंदे और अजित को इसका एहसास भी करा दिया है। भाजपा के स्वभाव को जानते हुए शिंदे और अजित अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने के लिए मशक्कत करने लगे हैं। इस वजह से स्वाभाविक तौर पर महायुती में भी अपनी उपस्थिति मजबूत रखने के लिए शिंदे और अजित उन सीटों को पाने के लिए संघर्ष करने लगे जिस पर वर्तमान में उनके सांसद हैं।

शिंदे और अजित पर अपनी पार्टी के मुखिया होने की भी तो जिम्मेदारी है। इसलिए सीटों के बंटवारे में समय लगना भी स्वाभाविक है। लेकिन जिस तरह से शिंदे और अजित पर भाजपा का दबाव तंत्र हावी हुआ है उससे यह संदेश तो मिलता है कि महायुती में सब कुछ भाजपा की मर्जी से होगा। चर्चा है कि भाजपा ने तीन अंदरूनी सर्वे कराया है जिसके आधार पर शिंदे गुट और अजित गुट को बताया गया कि उनके पास जीत वाली सीटों की गारंटी नहीं है। अब इस तरह से राजनीतिक ताकत का एहसास कराया जाएगा तो किसी भी राजनीतिक पार्टी की स्थिति क्या हो सकती है इसकी कल्पना की जा सकती है। बावजूद इसके शिंदे और अजित ने उस सर्वे को ज्यादा तवज्जोह नहीं दी।

भाजपा को भी अपनी ताकत के बारे में पता है। 105 विधायक होने के बावजूद भाजपा सत्ता से दूर थी। उसने सबसे पहले शिंदे की मदद से शिवसेना को तोड़ा। शिंदे को मुख्यमंत्री का पद सौंपते हुए राज्य में सत्ता स्थापित की। 40 विधायकों और 13 सांसदों को लेकर शिंदे ने हिंदुत्व के नाम पर भाजपा से गठबंधन किया।

इस गठबंधन को बहुमत की कमी नहीं थी। लेकिन भाजपा ने एनसीपी को तोड़कर अजित गुट को भी महायुती में शामिल कर लिया। अब लोकसभा चुनाव में सीटों को लेकर उठापटक होना लाजिमी है। भाजपा को विश्वास है कि मोदी की वजह से उसे हर सीट पर विजयी मिलेगी। इसलिए महायुती में शिंदे और अजित गुट को कम सीटें देने का भाजपा ने प्रयोग किया। शिंदे ने अपने जीते हुए सांसदों की सीटों पर दावा किया तो अजित ने 7 सीटें मांग ली। इससे भाजपा का 35 सीटें अपने हिस्से में रखने का सपना टूटने लगा। इसके बाद महायुती में उत्तर भारतीय विरोधी राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) को भी शामिल करने का सियासी खेल खेला गया। इसके जरिए शिंदे और अजित दोनों गुटों पर दबाब पड़ा।

मनसे के हिस्से में भी दो-तीन सीटें देने पर चर्चा हुई। ये सीटें शिंदे और अजित गुट से देने की बात हुई। मनसे के लिए अजित गुट से ओबीसी नेता छगन भुजबल को कमजोर करने के लिए उनकी सीट पर भी दावा किया गया। जबकि भाजपा अपनी सारी सीटें सुरक्षित रखना चाहती थी। इसका शिंदे गुट में बड़ा विरोध हुआ। इस विरोध को दबाने के लिए राजनीतिक हलकों में यह चर्चा रही कि शिंदे गुट की शिवसेना में मनसे को मर्ज कराया जाएगा और फिर शिवसेना का प्रमुख राज ठाकरे को बनाया जाएगा। ऐसी चर्चा से शिंदे गुट में बौखलाहट तो जायज है। यह सबको पता है कि आज राज ठाकरे से ज्यादा बड़ा है शिंदे का राजनैतिक हैसियत। राज के साथ ठाकरे शब्द जुड़ा हुआ है जिससे उनका महत्व बढ़ जाता है। भाजपा की यह सोच हो सकती है कि अगर उद्धव ठाकरे को परास्त करना है और उनके मराठी वोट को बांटना है तो महायुती में ठाकरे परिवार के राज ठाकरे को शिंदे से ज्यादा महत्व देना पड़ेगा।

लेकिन बतौर मुख्यमंत्री शिंदे ने मोदी और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उन परियोजनाओं को आगे बढ़ाया जिसे उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली आघाड़ी सरकार ने रोक दिया था। मराठा आरक्षण आंदोलन से निपटते हुए शिंदे ने 10 फीसदी आरक्षण देने का अपना वादा भी पूरा किया। इससे उनका जनाधार बढ़ा है और इसका फायदा उन्हें चुनाव में मिल सकता है। उधर बारामती सीट पर अजित को अलग तरह से संघर्ष करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। फडणवीस और शिंदे के करीबी माने जाने वाले पूर्व विधायक विजय शिवतारे ने तो पवार परिवार के खिलाफ संघर्ष का ऐलान कर दिया है। वह पवार परिवार को हराने के लिए बारामती से चुनाव लड़ना चाहते हैं। इससे अजित को अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार को विजय दिलाना कठिन हो गया है। इस सीट से शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले के लिए जीत की राह आसान हो रही है। शिवतारे के फैसले से अजित गुट ने शिंदे सरकार से बाहर होने की धमकी तक दे दी है। महायुती में जिस तरह से शिंदे को दबाने के प्रयास हुए हैं उससे आने वाले चुनावी नतीजे पर शक किया जाने लगा है।

महायुती में ही अजीबोगरीब हलचल नहीं है। विपक्ष की आघाड़ी में भी आपसी तालमेल बराबर नहीं दिख रहा है। यूं तो विपक्ष के इंडिया गठबंधन के राष्ट्रीय स्तर पर मजबूती को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र ही एक ऐसा राज्य है जहां विपक्ष की आघाड़ी से भाजपा सहमी हुई है। मनभेद के बावजूद आघाड़ी से यह उम्मीद बनी हुई है कि यह भाजपा के सपने को तोड़ने में कामयाब हो सकती है। इसकी वजह यह मानी जा रही है कि शिवसेना (उद्धव गुट) और एनसीपी (शरद गुट) के पारंपरिक वोटर पूरी सहानुभूति के साथ जुड़े हुए हैं। वैसे, शिवसेना के बार-बार टूटने का अपना इतिहास है। लेकिन शिवसेना कभी खत्म नहीं हुई है। अब भी यह माना जा रहा है कि टूटने बिखरने के बावजूद शिवसेना की विरासत उद्धव के पास है और वह इस लोकसभा चुनाव में उसी विरासत का परचम लहरा सकते हैं। अपने इसी आत्मविश्वास के साथ उद्धव ने आघाड़ी में सबसे ज्यादा सीट पाने का हक जताया है।

83 साल के शरद भी खुद को अपने भतीजे अजित से ज्यादा युवा मानते हैं और उन्हें चुनौती देते हुए अपनी एनसीपी को फिर से खड़ा करने में जुटे हुए हैं। शरद राजनीति के मंजे हुए खिलाड़ी हैं उन्हें राजनीति की हर चाल पता है। इस आघाड़ी में कांग्रेस भी है और किसी दूसरे राज्यों के मुकाबले महाराष्ट्र में उसे अपना जनाधार मजबूत दिख रहा है। इसलिए उसने एनसीपी से ज्यादा सीटों पर दावा किया है। लेकिन सीटों को लेकर आघाड़ी में भी तनातनी है। महायुती और आघाड़ी के राजनीतिक दलों के बीच भले ही सीटों की अदला बदली के साथ बंटवारा हो जाए लेकिन उनके मनभेद आसानी से मिटने वाले नहीं हैं। इसलिए यह आशंका बनी हुई है कि ये आपस में ही एक-दूसरे की सीट को धोखे में रख सकते हैं और इसका नतीजा चुनाव के बाद देखने को तो मिलेंगे ही।

समस्या

ललित गर्ग

लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।

बेरोजगार युवा नये भारत की ताकत कैसे होंगे?

दुनिया की तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर भारत में युवा- बेरोजगारी की दुखद तस्वीर चिन्तनीय है। भारत को युवा-शक्ति का देश कहा जाता है, युवाओं की संख्या, क्षमता और ऊर्जा को देश की ताकत के तौर पर पेश किया जाता और उन्हें विकास का वाहक बताया जाता है, बावजूद इसके अब अगर देश का युवा बेरोजगारी की समस्या का सामना करते हुए अपने सपनों को टूटते-बिखरते देख रहा है तो यह स्थिति एक त्रासदी एवं विडम्बना ही कहीं जायेगी, इसे सरकार की नाकामी ही मना जायेगा। लोकसभा चुनाव में बेरोजगारी की यह स्थिति मुद्दा क्यों नहीं बन रही है? भारत में बेरोजगारी की स्थिति पर मानव विकास संस्थान यानी आइएचडी के साथ मिल कर अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन यानी आइएलओ ने 'इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024' तैयार की है जिससे उजागर हुए बेरोजगारी के चिन्ताजनक तथ्यों पर गौर करने एवं आवश्यक कदम उठाने की जरूरत है। रिपोर्ट के निराशाजनक आंकड़े दो तथ्यों को रेखांकित करते हैं-बेहतर भुगतान करनेवाली नौकरियों के आकांक्षी शिक्षित युवाओं को खपा सकने वाली नौकरियों का अभाव और शिक्षा की गुणवत्ता में खामियां जिसके चलते बड़ी तादाद में शिक्षित युवा अब भी नौकरी के मानक को पूरा करने में अक्षम हो रहे हैं। दोनों ही स्थितियां सरकार की नीतियों की खामी को ही सामने ला रही है।

ताजा रपट सरकार की नीतियों, विकास एवं आर्थिक उन्नति की विसंगति को ही उजागर कर रही है। जिसमें बताया गया है कि देश में अगर बेरोजगार लोगों की कुल संख्या एक सौ है तो उसमें तिरासी लोग युवा हैं। अगर देश की बेरोजगारी की तस्वीर में तिरासी फीसद युवा दिख रहे हैं, तो इससे कैसे देश की ताकत में इजाफा होगा? इस अहम रपट में उजागर हुए कुछ विरोधाभासी तथ्यों एवं आंकड़ों पर भी गौर करने में मदद मिलती है। माना जाता है कि बेरोजगारी की समस्या काफी हद तक शिक्षा और कौशल विकास के अभाव का भी नतीजा है। मगर आइएलओ की रपट के मुताबिक, देश के कुल बेरोजगार युवाओं की तादाद में करीब दो दशक पहले के मुकाबले अब लगभग दोगुनी बढ़ोतरी हो चुकी है। खासतौर पर कोरोना महामारी के असर वाले वर्षों में इसमें तेज गिरावट दर्ज की गई। सोचने की जरूरत है कि नया भारत एवं विकसित भारत बनने के दौर में विकास के रास्ते में बेरोजगारी एवं युवा-सपनों को आकार देने का क्या हल है?

निश्चित तौर पर टेक्नोलॉजी से जुड़े बदलावों ने कौशल और रोजगार के प्रकारों की मांग को भी प्रभावित किया है। रिपोर्ट के अनुसार उच्च और मध्यम कौशल केन्द्रित नौकरियों में युवाओं ने बेहतर प्रस्तुति दी है। हालांकि, इन क्षेत्रों में नौकरी की इनसिक्योरिटी अभी भी परेशानी का सबब बनी हुई है। क्योंकि युवाओं में बुनियादी डिजिटल लिटरेसी की कमी भी कायम है। इस वजह से उनकी रोजगार की क्षमता में रुकावट आ रही है। बेरोजगारी की दुखद तस्वीर के बीच एक खराब स्थिति यह है कि इस दौरान ठेकेदारी प्रथा में वृद्धि हुई है। रपट के मुताबिक, संगठित क्षेत्रों में भी कुल कर्मचारियों का कुछ प्रतिशत हिस्सा ही नियमित है और वे दीर्घकालिक अनुबंधों के दायरे में आते हैं। ऐसी स्थिति में अंदाजा लगाया जा सकता है कि आजीविका से जुड़ी व्यापक असुरक्षा की स्थितियों का युवाओं एवं उनके परिवारों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता होगा। विडंबना यह है कि बढ़ती बेरोजगारी के साथ घटती आय का सामना कर रहे परिवारों में सीधा असर यह पड़ता है कि बच्चों और खासतौर पर लड़कियों की शिक्षा बाधित होती है।

भारत की चेतना को नया निखार देने का दायित्व युवापीढ़ी पर माना जा रहा है, उनसे बहुत-बहुत आशाएं है आजादी के अमृतकाल में लेकिन युवाओं के साथ बेरोजगारी एवं आर्थिक अभाव का दंश जुड़ा रहेगा तो देश कैसे आगे बढ़ेगा? वर्ष 2000 में पढ़े-लिखे युवा बेरोजगारों की संख्या रोजगार से वंचित कुल युवाओं में 35.2 फीसद थी, वहीं 2022 में यह बढ़ कर 65.7 फीसद हो गई। यह स्थिति तब है, जब इस अध्ययन में उन पढ़े-लिखे युवाओं को भी शामिल किया गया, जिन्होंने कम के कम दसवीं तक की शिक्षा हासिल की हो। इससे एक जटिल स्थिति यह पैदा होती है कि जितने लोगों को रोजगार मिल सका, उनमें से नब्बे फीसद श्रमिक अनौपचारिक काम में लगे हुए हैं, जबकि नियमित काम का हिस्सा बीते पांच वर्षों में काफी कम हो गया है। हालांकि सन् 2000 के बाद इसमें बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। आखिर क्या कारण है कि देश में गरीब और हाशिये के तबकों के बीच दसवीं के बाद पढ़ाई छोड़ने की दर आज भी उच्च स्तर पर बनी हुई है? आधी-अधूरी शिक्षा और कौशल-विकास के अभाव की समस्या का सामना करते युवा वर्ग की जगह अर्थव्यवस्था में कहां और किस रूप में है? राजनीतिक नारेबाजी में देश में युवाओं की बढ़ती तादाद और ताकत को एक उम्मीद के तौर पर पेश करने में कोई कमी नहीं की जाती है। मगर वादों या घोषणाओं के नीतिगत स्तर पर जमीन पर उतरने की हकीकत कई बार उसके उलट होती है। लगता है राजनेताओं के लिये युवा केवल जीत हासिल करने का माध्यम है। सवाल है कि इस विरोधाभासी स्थिति के रहते विकास की राह कहां पहुंचेगी? कैसे युवा अपनी ऊर्जा एवं क्षमताओं का उपयोग देश विकास में करेंगे? रिपोर्ट के मुताबिक युवा महिलाओं, खासतौर पर हायर सेकेंडरी पास महिलाओं को रोजगार हासिल करने में काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

हाल के वर्षों में कृषि में रोजगार बढ़ा है पर मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र की हिस्सेदारी स्थिर है। स्वरोजगार में युवाओं के सामने जटिल प्रशासनिक एवं कानूनी व्यवस्था एक बड़ी बाधा है। जीएसटी की जटिल प्रक्रिया ने व्यापार शुरु करने से पहले ही युवाओं को घुटने टेकने को विवश कर दिया है। इन विरोधाभासी हालातों में विकास परियोजनाओं से ही रोजगार के अवसर बढ़ने की उम्मीद रहती है। इस क्षेत्र में रोजगार की स्थिरता 2047 तक विकसित भारत बनने के सपने पर पानी फेर सकती है। इसलिए अधिक रोजगार पैदा करने वाली विकास परियोजनाओं को बढ़ाने की चुनौती बरकरार है। हर साल श्रमबल में शामिल होने वाले नए लोग अब बड़ी संख्या में स्वरोजगार और आकस्मिक श्रमिक के रूप में आ रहे है। स्वरोजगार का बढ़ना तो अच्छा संकेत माना जा सकता है पर आकस्मिक श्रमिकों का बढ़ना नहीं। सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने यह कहकर नई बहस एवं युवा-घावों को गहराने का काम किया है कि 'यह सोचना गलत होगा कि सरकार बेरोजगारी की समस्या को दूर कर सकती है।' उन्होंने कहा कि सरकार ने नई शिक्षा नीति बनाई है और कौशल विकास के प्रयास किए हैं। सरकार ने ये प्रयास रोजगार की स्थितियों की सुधारने के लिए ही किए हैं। रोजगार देना व्यावसायिक क्षेत्र का काम है। सरकार के सलाहकार होने के नाते नागेश्वरन को यह भी समझाना होगा कि नीतियों का लाभ उठाकर आगे बढ़ा व्यावसायिक क्षेत्र यदि अपेक्षित रोजगार उपलब्ध नहीं करा पा रहा है तो सरकार को ही उचित एवं प्रभावी कदम उठाने होंगे। रोजगार सृजन की स्थिति में अपेक्षित सुधार दर्ज नहीं होना सरकार एवं उनके नीति निर्माताओं के लिए चिंता का सबब होना चाहिए। अब जबकि आम चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, राजनीतिज्ञों को न सिर्फ अपने प्रचार अभियानों में, बल्कि उसके बाद नीति-निर्माण में भी नौकरियां सुनिश्चित करनी होंगी और तकनीकी रूप से विकसित हो रही अर्थव्यवस्था के लिए शिक्षण व प्रशिक्षण की गुणवत्ता को प्राथमिकता देना सुनिश्चित करना होगा।

भारी-भरकम टोल टैक्स फिर भी सड़क पर पैबंद

देश- प्रदेश के हाईवे पर टोल टैक्स, जो अभी तक वैसे भी कम नहीं था, अब एक अप्रैल से इसमें 7.5 फीसदी की वृद्धि की जा रही है। खबर है कि मध्यप्रदेश के 6 स्टेट और 4 नेशनल हाईवे पर अब ज्यादा टैक्स चुकाना होगा। इसमें भोपाल-देवास तथा भोपाल-ब्यावरा फोरलेन सड़क शामिल है। बहुत बढ़िया, आखिर बाज़ार से कर्ज लेकर चलने वाली सरकारों से उम्मीद भी क्या ही की जा सकती है। सो, टोल टैक्स बढ़ाना हरेक वर्ष के कर्मकांड की तरह हो गया लगता है।

मुद्दा

आरबी त्रिपाठी

लेखक स्तंभकार हैं।

अखबार में यह खबर पढ़कर हमें हाल ही में जयपुर-जबलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भोपाल से ब्यावरा फोरलेन और एबी रोड पर जाने का सफर याद आ गया। कुछ निजी कारणों से इन रुट पर दर्जन भर से अधिक मर्तबा आना जाना लगा रहा। हमारी यात्रा के वक्त इस रुट पर भोपाल से ब्यावरा तक ही पहले 90 रुपये और ब्यावरा के समीप 75 रुपये टैक्स वसूला गया था। इस भारी भरकम वसूली के बावजूद भोपाल से ब्यावरा के बीच कोई पचासों से ज़्यादा जगह इस कथित फोरलेन सड़क की हालत यह है कि जगह जगह सड़क पर पैबंद लगे हैं। इसके चलते वाहन उछलते, कूदते और लहराते हुए चलते हैं। यही नहीं फ्लाई ओवर की भी हालत कमोबेश ऐसी ही है।

यदि कोई अनजान व्यक्ति जो पहली बार इस फोरलेन पर ड्राइव कर रहा हो उसका भगवान ही मालिक है। इस रोड पर अनेक जगह सड़क और पुल-पुलियाओं का लेवल इतना ऊंचा-नीचा है कि सोचने को मजबूर होना पड़ता है कि कौन सी टेक्नोलॉजी से यह निर्माण हुआ है और इसके इंजीनियर कहां से इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर आये हैं। कई जगह पूर्व में सड़क को उखाड़कर नये सिरे से मरम्मत या कहें कि पैबंद लगाने के काम को इस तरह अंजाम दिया गया है कि कोई गैर इंजीनियर व्यक्ति भी बता देगा कि यहां सड़क टूटी है जिसे पैबंद लगाकर काम चलाया जा रहा है। इन दिनों चिलचिलाती धूप में यह और भी स्पष्ट नज़र आता है।

दरअसल खस्ताहाल सड़कों के सुधार, पुनर्निर्माण और मेनटेनेंस के लिये टोल टैक्स लगाने, वसूलने की यह परिपाटी शुरू की गई होगी, ऐसा उल्लेख मिलता है। बीओटी यानी बिल्ड,आपरेट और ट्रांसफर का सिस्टम भी लाया गया था। इसमें पहले भोपाल - देवास फोरलेन और फिर इंदौर तक सिक्स लेन को लाया गया। भोपाल, देवास, इंदौर रोड तो ठीक-ठाक है लेकिन भोपाल से नरसिंहगढ़ होकर ब्यावरा तक बनी फोरलेन सड़क पर लगे पैबंद अखरने वाले प्रतीत होते हैं।

वैसे भी भोपाल - ब्यावरा फोरलेन सड़क निर्माण की शुरुआत से ही विवादों में घिर गई थी। पहले निर्माण एजेंसी ठेका छोड़कर चलती बनी तो बहुत समय तक रोड आधी अधूरी पड़ी रही जो खास तौर पर रात के समय वाहन चालकों के लिये मुसीबत का सबब बन गई थी। जैसे - तैसे फोरलेन बनी तो लेकिन पहली दूसरी बारिश में ही अपने असली रूप में आ गई। मरम्मत और पुनः मरम्मत के चलते लगे पैबंद अब साफ नज़र आते हैं। दूसरी ओर इस रोड पर टोल टैक्स भरपूर वसूला जा रहा है। ब्यावरा के नजदीक टोल टैक्स पर मारपीट की घटनाएं हो चुकी है। सोचिये, इस महत्वपूर्ण रोड से कौन नहीं गुज़रता होगा? अब तो राजगढ़ जिले से राज्य मंत्री मण्डल में दो मंत्री शामिल हैं। अब पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद तथा लोकसभा चुनाव में राजगढ़ से उम्मीदवार दिग्विजय सिंह भी इन्हीं सड़कों पर पद यात्रा करते प्रचार के लिये निकलेंगे तब वे भी इसे रू-ब-रू देखेंगे ही।

आखिर कल्याणकारी सरकार लोक लुभावन नारों, वादों और जुमलों से लोकप्रियता हासिल करती रही है। सो, एक बार फिर देश भर के मतदाता आने वाले दिनों में देश के भविष्य का चुनाव करने जा रहे हैं तो इस तरह के सवाल उठाये जाना लाजिमी है। मुद्दों से ना तो भागा जा सकता है और ना इनकी उपेक्षा की जाना चाहिये।

सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए उमेश त्रिवेदी द्वारा पी.जी. इंफ्रास्ट्रक्चर एण्ड सर्विसेस प्रा. लि., राउखेड़ी, देवास रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 662, साईं कृपा कॉलोनी, बॉम्बे हॉस्पिटल के सामने, इंदौर से प्रकाशित।

प्रधान संपादक - उमेश त्रिवेदी
संपादक (म.प्र.) - गिरीश उपाध्याय
वरिष्ठ संपादक - अजय बोकिल
स्थानीय संपादक - हेमंत पाल
प्रबंध संपादक - अरुण पटेल

(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र इंदौर रहेगा)
RNI No. MPHIN/ 2015/ 66040,
Mobile No.: 09893032101
Email- subahsaverenews@gmail.com

'सुबह सवेरे' में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं। इनसे समाचार पत्र का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

व्यंग्य

प्रभुनाथ शुक्ल

(वरिष्ठ पत्रकार, लेखक एवं समीक्षक)

सियासी गंगा में डुबकी लगाइए और पवित्र हो जाइए

देखिए! आप कितना भी पाप करिए, लेकिन एक बार गंगा स्नान कर लीजिए सारे पाप धूल जाएंगे। हमारे यहाँ तो यहाँ तक कहा गया है कि गंगा दर्शन मात्र से हमारी मुक्ति हो जाती और सारे पाप धुल जाते हैं। इसीलिए अब लोग पुण्य की चिंता छोड़ दिए हैं और पाप पर पाप किए जा रहें हैं। एक-दो पाप नहीं पूरा घड़ा ही पाप से भर रहें हैं। दरअसल उनके पुण्य में ही पाप की आत्मा बसी है। हमारे वेद और शास्त्रों में गंगा स्नान बेहद पवित्र माना गया है। इसीलिए लोग गलत कार्य करने में कभी नहीं डरते हैं। क्योंकि उनके पास पाप धोने के लिए गंगा है। अब गंगा भी पापियों का पाप धोते-धोते मैली हो चली हैं। आजकल लोग अब गंगा से अधिक पवित्र पाप धोने के लिए सियासी गंगा को मानने लगे हैं।

सच मानिए! पाप धोने का आजकल सबसे मॉडर्न तरीका भी आ गया है। वह है सियासी गंगा में स्नान। इस गंगा में स्नान करना बेहद पुण्य फलदायी होता है। कहते हैं की सियासी गंगा का स्नान गंगा से भी पवित्र होता है। इस गंगा में स्नान करने से सारे कलुष धुल जाते हैं। इस गंगा में स्नान से कई पीढ़ियां तर जाती हैं। लेकिन इस गंगा में स्नान की शर्त भी है। सियासी गंगा में स्नान का फल तभी मिलता है जब चुनावों का मौसम हो। आप भर्ष्टाचार को शिष्टाचार बना लिए हों। आप के खिलाफ जितनी जांच एजेंसिया हों सब

लगी हों। आप विपक्ष में रह कर कितना भी भ्रष्टाचार, बलात्कार, लूट, हत्या जैसा अपराध और पाप किए हो सब धूल जाता है। बस एक बार आप सत्ता की गंगा में डुबकी लगा लिए तो आपके सारे पाप धुल जाएंगे। फिर आपके पास जाँच की आंच कभी नहीं आएगी। सत्ता में आने के बाद फिर आप पाप का घड़ा भरना शुरू कर दीजिए।

आजकल चुनावी मौसम में सियासी गंगा में नहाने का दौर चल पड़ा है। ऐसे घाटों पर बड़ी भीड़ दिख रही है। इस भीड़ में वामपंथ, दक्षिण पंथ और सेकुलर का तटबंध टूट गया है। जिस गंगा में लोग अपने पाप की सियासी गठरी लेकर कूद रहें हैं वह भी अपवित्र और मैली हो चला है। लेकिन सियासी घाट पर बैठे पंडे सबसे पवित्र होने का दावा कर रहें हैं और डुबकी लगाने वाले का चंदन लगा और दुपट्टा ओढा स्वागत कर रहे हैं। सियासी गंगा में वे डुबकी लगा अपने भर्ष्टाचार को भले छुपा लें, लेकिन लोकतंत्र में तो उनका पाप तभी धुलेगा जब मतदाता उनके माथे पर जीत का छापा-तिलक लगाएगी। क्योंकि यह पब्लिक है सब जानती है।

कानून और न्याय

विनय झैलावत

(पूर्व असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल एवं वरिष्ठ अधिवक्ता)

वैवाहिक मामलों में समझौते के बाद मुकरना संभव नहीं !

हाल ही में मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ के न्यायमूर्ति सुबोध अभ्यंकर ने एक पूर्व पत्नी के द्वारा समझौता होने के बाद भी दोनों पक्षों के मध्य चल रहे फौजदारी मुकदमे को वापस लेने से इंकार करने के आधार पर पत्नी पर एक लाख का मुआवजा पति को देने का आदेश दिया है। पत्नी अपने पति से पचास लाख रुपये एकमुश्त राशि समझौते के एवज में ले चुकी थी।

पारिवारिक मामलों में अक्सर देखा जाता है कि कई बार दोनों पक्ष के बीच में समझौता होने के बाद भी कई बार एक पक्ष मुकर जाता है। ऐसा ही कुछ मामला न्यायमूर्ति सुबोध अभ्यंकर के समक्ष आया। यहां पर पति-पत्नी के बीच में हुए समझौते एवं न्यायालय द्वारा पारित तलाक की डिक्री को न मानते हुए पत्नी ने विभिन्न दायर केसों को वापस लेने से इनकार किया। महिला द्वारा दहेज उत्पीड़न, हमला और सहमति के बिना गर्भपात के सर्वव्यापी आरोप लगाए गए थे। उच्च न्यायालय ने कहा कि वह आपसी सहमति से समझौता और तलाक की डिक्री के बाद पत्नी मामले को वापस लेने के लिए बाध्य थी। लेकिन, उसने जानबूझकर, गलत उद्देश्यों के साथ अपने द्वारा दायर केसों को भी वापस लेने से इंकार कर दिया।

न्यायमूर्ति अभ्यंकर ने कहा कि इस प्रकार समझौता करने और उसके बदले में पचास लाख रुपये लेने के बावजूद, अपने पति और उसके परिवार के खिलाफ आपराधिक मामला जारी रखने में महिला का आचरण स्पष्ट रूप से अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। पीठ ने कहा कि एक लाख रुपये की कास्ट केवल बेईमान पक्षकार को आगाह करने के लिए लगाई गई है कि वे अदालतों में इन आधारों पर नहीं जा सकते हैं, जो गंभीर मुकदमेबाजी के लिए हैं। न्यायमूर्ति ने कहा कि ऐसे पक्षकारों को किसी भी तरह से अदालतों का मूल्यवान समय बर्बाद करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। अदालत ने महिला की सहमति के बिना दहेज उत्पीड़न, हमला करने और गर्भपात के आरोपों से संबंधित मामले को रद्द कर दिया और पत्नी को चार सप्ताह में अपने पूर्व पति को एक लाख रूपये देने का आदेश दिया।

यह पहला मामला नहीं है जब किसी न्यायालय ने समझौते से पीछे हटने पर कड़ा रूख लिया है। इससे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट भी एक मामले में ऐसा ही रूख ले चुका है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि सहमति की शर्तें शामिल पक्षों पर आपसी दायित्व पैदा करती हैं। न्यायालय ने यह माना कि तलाक की कार्यवाही में एक पत्नी के लिए इसके लाभ स्वीकार करने के बाद सहमति की शर्तों से बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी। पति द्वारा पिछले साल दायर एक याचिका का निपटारा करते हुए न्यायमूर्ति अमित बोरकर की एकल पीठ ने पत्नी को निर्देश दिया था कि, वह दो महीने के भीतर तलाक के लिए सहमति की शर्तों के प्रावधानों के तहत प्रकरणों को समाप्त करे और इससे पीछे न हटे। उच्च न्यायालय के समक्ष पति की याचिका में कहा गया था कि पत्नी सहमति की शर्तों के अपने हिस्से का पालन करने से इंकार कर रही थी। पति अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को चुनौती देने

के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष आया था, जिसने समझौते का सम्मान करने के लिए अपनी अलग हो चुकी पत्नी को निर्देश देने की उसकी याचिका को खारिज कर दिया था।

उच्च न्यायालय ने पति के वकील के तर्क सुनने के बाद कहा कि पति ने पत्नी के रखरखाव के लिए एकमुश्त निपटान के रूप में निर्धारित राशि का भुगतान करके और उसे एक आवासीय फ्लैट में स्थानांतरित करके सहमति की शर्तों का पालन किया था। न्यायालय ने कहा कि यदि वह दो महीने में घरेलू हिंसा और क्रूरता के मामलों को वापस लेने और बच्चे को प्रवेश देने के लिए सहमति की शर्तों के अपने हिस्से का पालन करने में विफल रहती है, तो फ्लैट तथा पूरी राशि उन्हें वापस करना होगी। उनका एक नाबालिग बच्चा भी था। पति ने उसके द्वारा क्रूरता का आरोप लगाते हुए पुणे की एक अदालत में तलाक की अर्जी दायर की। तलाक की कार्यवाही को एक मध्यस्थ के पास भेजा गया था। मुकदमे के दौरान दंपति मामले को सौहार्द्रपूर्ण ढंग से निपटाने के लिए सहमत हुए थे।

तलाक एक ऐसी प्रक्रिया है जो कानूनी रूप से विवाह समाप्त करती है। यह कई प्रकार से संभव है। आपसी-सहमति से तलाक विवाह को समाप्त करने का सबसे आसान तरीका है। आपसी सहमति से तलाक तब होता है, जब दोनों पति-पत्नी एकमत हो शादी को समाप्त करने के सहमत होते हैं। इस तरह के तलाक में, दोनों पक्ष चाइल्ड कस्टडी, संयुक्त-संपत्ति का विभाजन, रखरखाव आदि प्रमुख मुद्दों पर सहमत होते हैं। तलाक के लिए पक्षकारों को उस शहर के परिवार न्यायालय में तलाक आवेदन करने की आवश्यकता होती है जहां दोनों पक्ष एक साथ रहे अथवा जहां पर विवाह हुआ हो या जहां वैवाहिक प्रक्रिया उत्पन्न हुई हो अथवा वह स्थान जहां पर पत्नी वर्तमान में रह रही हो।

भारत में आपसी सहमति से तलाक हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 और विशेष विवाह अधिनियम, 1954 द्वारा शासित होता है। आपसी सहमति से तलाक के लिए हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 बी और विशेष विवाह अधिनियम की धारा 28 के तहत विवाह के एक साल बाद ही आपसी सहमति से तलाक की मांग की जा सकती है। दोनों पक्षों को तलाक के लिए पारस्परिक रूप से सहमत होना होगा और यह स्थापित करना होगा कि याचिका दायर करने से पहले वे कम से कम एक वर्ष से अलग रह रहे हैं। यदि न्यायालय आश्वस्त हो कि दोनों पक्षों के बीच सुलह की कोई संभावना नहीं है तो छह महीने की पुनर्विचार अवधि की छूट दे सकता है। न्यायालय गुजारा भत्ता, बच्चे की कस्टडी और संपत्ति के बंटवारे जैसे मुद्दों के संबंध में पक्षों द्वारा किए गए समझौते की शर्तों पर भी विचार करेगी। यदि पक्ष किसी समझौते पर पहुंचने में असमर्थ हैं, तो न्यायालय आपसी सहमति से समाधान की सुविधा के लिए मध्यस्थता का आदेश दे सकती है। आपसी सहमति से तलाक की प्रक्रिया आमतौर पर विवादास्पद तलाक की तुलना में तेज और कम विरोधात्मक होती है और इसे कुछ महीनों में पूरा किया जा सकता है।

भारत में आपसी-सहमति से तलाक की प्रक्रिया आमतौर पर याचिका दायर करने से शुरू होती है। इसमें पहला चरण संबंधित परिवार न्यायालय में एक संयुक्त याचिका दायर करना है। इस संयुक्त याचिका पर दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं। तलाक की याचिका में दोनों पक्षकारों का एक संयुक्त बयान होता है कि उनके असंगत मतभेदों के कारण वे अब एक साथ नहीं रह सकते हैं और उन्हें तलाक दिया जाना चाहिए। इस कथन में संपत्ति के बंटवारे, बच्चों की कस्टडी आदि का समझौता भी है। याचिका दायर करने के लिए दोनों पक्षों की अपने वकील के साथ परिवार न्यायालय में उपस्थिति अनिवार्य होती है। न्यायालय पक्षकारों द्वारा दायर याचिका की जांच करने के बाद दोनों पक्षों के बयान दर्ज करने का आदेश देता है। कुछ मामलों में, न्यायालय मध्यस्थता कराने का प्रयास करता है, जब दोनों पक्षों के बीच सुलह की कोई गुंजाइश नहीं होती, तो तलाक प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाता है।

पक्षकारों के बयान दर्ज किए जाने के बाद, न्यायालय द्वारा पहले प्रस्ताव पर एक आदेश पारित किया जाता है। इसके बाद न्यायालय द्वारा पक्षकारों को तलाक पर पुनर्विचार के लिए 6 महीने का समय दिया जाता है, जिसके बाद दूसरा प्रस्ताव दाखिल करना होता है। पहले प्रस्ताव के 6 महीने के बाद या सुलह अवधि के अंत तक, यदि दोनों पक्ष साथ रहने के लिए सहमत नहीं होते हैं, तो वह दूसरे प्रस्ताव के लिए न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो सकते हैं। यदि 18 महीने की अवधि के भीतर दूसरा प्रस्ताव दाखिल नहीं किया जाता, तो न्यायालय तलाक की डिक्री पारित नहीं करता है। तलाक की डिक्री मामले के तथ्य, परिस्थितियों और दोनों पक्ष के बयानों के आधार पर, न्यायालय तलाक की डिक्री पारित कर देती है।

आपसी सहमति से तलाक में हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 ख (2) के अनुसार, आपसी सहमति से तलाक के मामलों में, न्यायालय ने विवाह बचाने के उद्देश्य से तलाक पर पुनर्विचार करने के लिए छह महीने की समय अवधि अनिवार्य कर दी थी। इसे सुलह अवधि या पुनर्विचार अवधि भी कहा जाता है। इस अवधि के समाप्त होने पर, कोई भी पक्ष आपसी तलाक के लिए अपनी सहमति वापस लेने का निर्णय ले सकता है। 2024 के नए तलाक नियमों के अनुसार, आपसी सहमति से तलाक के लिए यह सुलह-अवधि या पुनर्विचार अवधि अब अनिवार्य नहीं है। यदि पति-पत्नी सहमत हों तो न्यायालय अपने विवेक अनुसार इसके बिना ही तलाक दे सकता है, इससे आपसी सहमति से तलाक की प्रक्रिया में तेजी आएगी।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 2017 में माना है कि इस अवधि को 4 विशिष्ट शर्तों के तहत यदि तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर न्यायालय यदि उचित समझता है, तब छूट दी जा सकती है। इसके लिए धारा 13ख (2) के तहत दूसरी प्रस्ताव के लिए याचिका के साथ एक अतिरिक्त आवेदन दाखिल करना होगा जो सूचीबद्ध करेगा कि आपके मामले में कूलिंग अवधि क्यों लागू नहीं है। आपसी सहमति से तलाक लेना आवश्यक झगड़े एवं काफी समय परेशानियां और पैसा बचाता है। अतः पारस्परिक सहमति, तलाक का सबसे अच्छा विकल्प है।

दृष्टिकोण

राजेंद्र बज

(लेखक 34 वर्षों से पत्रकारिता में निरंतर सक्रिय वरिष्ठ पत्रकार और साहित्यकार हैं)

नागरिकों को भ्रमित करना, यह कैसी राजनीति है ?

राजनीति से संबंधित एक समय में एक मुद्दे पर एक बात आती है, इस आधार पर जनता जनार्दन अपना अभिमत बना लेने की स्थिति में आने लगती है। लेकिन संचार क्रांति के दौर में तत्क्षण ही उस बात के विपरीत कोई दूसरी बात सामने आ जाती है। ऐसे में आम नागरिक वास्तविकता से कोसों दूर हो जाते हैं। आमतौर पर ऐसा किसी मामले विशेष पर ही नहीं होता, अपितु हर एक बात के उलट कोई दूसरी बात सामने आ जाती है। इसके चलते नागरिकों का मनोमस्तिष्क एक अजीब-सी भूलभुलैया में उलझ कर रह जाता है। यह स्थिति पूर्व की तुलना में विगत दो-तीन दशक से बहुतायत में देखने में आ रही है।

ऐसे में नायक को खलनायक और खलनायक को नायक निरूपित करना आसान होता जा रहा है। इसके चलते देश-प्रदेश के नागरिकों में मतिभ्रम की स्थिति दिखाई देती है। सीधे तौर पर इसका लाभ अवांछित वर्ग को ही मिला करता है। वैसे भी राजनीति से विश्वसनीयता का नाता तो काफी पहले टूट चुका था। काफी हद तक यह माना जाता रहा है कि झूठ का दोहराव, झूठ को भी सच का बाना पहना देता है। लेकिन अब तो सुरसुरी छेड़ कर भी मन वांछित परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। राजनीति में बिना संदर्भ या प्रसंग के अर्थ का अनर्थ करना, राजनीतिक कौशल के रूप में लिया जा रहा है।

हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। इस नाते अनेकता में एकता और एकता में अनेकता के चलते हर व्यक्ति देखी या सुनी बात को अपनी बौद्धिक क्षमता के आधार पर ही ग्रहण करता है। हर कोई किसी बात को मानने के लिए तर्क का मोहताज भी नहीं होता। अनेक अवसरों पर तो किसी बात के प्रस्तुतिकरण की भाव-भाषा शैली के आधार पर आम नागरिक किसी निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं। इस आधार पर कोई न कोई निश्चित धारणा बना लेते हैं। यह जरूरी नहीं कि ऐसी धारणा तर्कसम्मत ही हो। राजनीति में भाई-भतीजावाद और

जातिवाद के चलते ऐसी धारणा आमतौर पर पूर्वाग्रह युक्त ही रहा करती है।

वैसे यह भी माना जा सकता है कि हर किसी व्यक्ति या उसके विचार का कोई ऐसा दौर होता है - जो अपने-अपने कालखंड में सर्वमान्य होता है। लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं दी जा सकती कि आने वाले दौर में वह कभी विवादित नहीं होगा। इस कथन की प्रमाणिकता को इस आधार पर भी समझा जा सकता है कि बीते दौर के महापुरुष भी आज कटघरे में खड़े कर दिए जाने लगे हैं। ठीक इसी प्रकार जिन्हें किसी दौर में समाज व राष्ट्र के लिए अवांछित समझ गया, उनको आज महिमामंडित भी किया जाने लगा है। इसके चलते कल का सच, झूठ और आज का झूठ, कल को सच हो सकता है। राजनीति में सत्य की खोज दुष्कर होती जा रही है।

निश्चित ही यह स्थिति समाज व राष्ट्र की सेहत के लिए अच्छी नहीं मानी जा सकती। जाहिर है कि जब नागरिकों में मतभिन्नता का पैमाना छलक जाएगा तब तमाम तरह की विरोधाभासी स्थिति दिखाई देने लगेगी। वैसे भी आजकल राजनीति में रुझान रखने वाला वर्ग दो हिस्सों में बंटा हुआ है। एक वर्ग ऐसा है जो यह मानता है कि देश प्रगति पथ पर द्रुत गति से दौड़ रहा है। लेकिन एक दूसरा वर्ग ऐसा भी है जो यह मानता है कि देश पतन के गर्त में जा रहा है। वैसे यह स्वाभाविक है कि सबका अपना-अपना एक विशेष नजरिया होता है। लेकिन वास्तविकता तो कोई एक ही हुआ करती है। जो कि हर दृष्टि से अकाट्य होती है।

वर्तमान दौर की राजनीति में प्राचीन अवधारणाओं को तोड़-मरोड़ कर प्रस्तुत किया जाने लगा है। नागरिकों को भ्रमित करते हुए राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि के लिए व्यक्तिगत एवं सामाजिक दोषारोपण ही नहीं, अपितु जन-जन के आराध्य के प्रति भी अनुचित टिप्पणियों का दौर जारी है। वैसे राजनीति धर्म नीति से प्रेरित होना चाहिए, इसमें दो मत नहीं, लेकिन धर्म के आधार पर राजनीति तो सर्वथा अनुचित ही है। यह अत्यंत आश्चर्यजनक है कि दलीय स्वार्थ से प्रेरित होकर नागरिकों की आस्था और विश्वास के साथ खिलवाड़ भी किया जाने लगा है। ऐसे में जन सामान्य के लिए यह समझना मुश्किल हो रहा है कि सच क्या है और गलत क्या है ?

विश्व ऑटिज़्म जागरूकता दिवस

सुनील शुक्ल

ऑटिज़्म कोई बीमारी नहीं एक विकार है और इसे स्वीकारना हमारी जिम्मेदारी है

आपको नहीं लगता कि पिछले कुछ सालों से हमे थोड़ा अलग तरह का व्यवहार करने वाले बच्चे कुछ ज़्यादा नज़र आने लगे हैं। ये बच्चे मानसिक बीमारी या मनोरोग से ग्रस्त नहीं होते हैं बल्कि अमूमन सामान्य बच्चों की तरह ही दिखते हैं। जी हाँ, आपने ठीक पहचाना, ये बच्चे ऑटिज़्म से प्रभावित होते हैं। खुशी की बात है कि ऑटिस्टिक बच्चों और लोगों पर अब बात होने लगी है और उनको मुख्य धारा में लाने के लिए सरकार समेत तमाम बड़े संस्थान और स्वयंसेवी संगठन भी कमर कस के लगे हुए हैं लेकिन अभी तो बहुत कुछ किया जाना बाक़ी है।

सन् 2007 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा हर साल 2 अप्रैल को 'विश्व ऑटिज़्म जागरूकता दिवस' के रूप में नामित किए जाने की घोषणा से इस पर तवज्जो दी जाने लगी। संयुक्त राष्ट्र का आशय ऑटिस्टिक लोगों के लिए सभी मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता की पूर्ण प्राप्ति की पुष्टि और बढ़ावा देना है। दूसरों के साथ समान आधार के साथ संयुक्त राष्ट्र महासभा प्रस्ताव (ए/आरईएस/62/139) ऑटिज़्म के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने के महत्त्व पर ज़ोर देता है। आज, 17 साल बाद, हम ऑटिस्टिक लोगों और समाज में उनके योगदान की स्वीकृति और सराहना को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता बढ़ाने से कुछ हद तक आगे बढ़ गए हैं।

ऑटिज़्म दरअसल कोई बीमारी नहीं बल्कि एक तरह का विकार है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक़ 'ऑटिज़्म यानी ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर (एएसडी) विकास संबंधी ऐसा विकार है जिसका असर संवाद और व्यवहार पर पड़ता है और यह किसी भी उम्र में परिलक्षित हो सकता है।' ऑटिज़्म को 'स्पेक्ट्रम' विकार के रूप में जाना जाता है क्योंकि लोगों द्वारा अनुभव किए जाने वाले लक्षणों के प्रकार और गंभीरता में व्यापक भिन्नता होती है और हर प्रभावित व्यक्ति में ये एकदम अलग होता है।

वरिष्ठ शिशु रोग विशेषज्ञ और गांधी मेडिकल कॉलेज, भोपाल की पूर्व प्राध्यापक डॉ. शीला भाम्बल ने बताया कि 1975-80 में तो ऑटिज़्म की स्पष्ट पहचान नहीं हो पाती थी। अलबत्ता धीरे-धीरे इस पर शोध और फ़ोकस किया गया तब ये बात सामने आई कि किसी बच्चे के ऑटिज़्म प्रभावित होने में उसके माता-पिता की कोई कमी या दोष नहीं होता है। इसकी पहचान बढ़ते शिशु की गतिविधियों में प्रचलित पैमानों के आधार पर की जाती है। मसलन आम तौर पर कोई शिशु 13 महीने में कम से कम एक शब्द अर्थ के अनुसार बोलता है। कुछ बच्चे देर से बोलना शुरू करते हैं। ऑटिज़्म प्रभावित बच्चे भी देर से बोलते हैं लेकिन घर पर दादी-नानी कहती हैं कि चिंता की कोई बात नहीं, इसका बाप भी देर से बोला था, इसलिए डॉक्टर तक पहुँचाना टलता जाता है और ऑटिज़्म की पहचान में देर हो जाती है। शिशु की वृद्धि और विकास के प्रचलित पैमाने के अनुसार यदि बच्चा छह महीने की उम्र तक मुस्कुराहट या खुशी की अभिव्यक्ति न दे, नौ महीने तक चेहरे की भाव भंगिमा और आवाज़ों की नक़ल न करे, 12 महीने तक बड़बड़ या लाड़-दुलार न करे, 14 महीने तक इंगित इशारा न करे अथवा हाथ न हिलाए, 16 महीने तक एक भी शब्द न बोल पाये, 18 महीने तक कोई काल्पनिक खेल या नाटक नहीं करे, 24 महीने तक कम से कम दो-तीन शब्दों का वाक्य न बोल सके तो समझ लीजिए कि मामला गंभीर है और तुरंत चिकित्सकीय परामर्श की आवश्यकता है। इसके अलावा भी अभिभावकों, परिवारजनों एवं परिचितों को ये मशविरा दिया जाता है कि कोई बच्चा कुछ-कुछ नीचे वर्णित जैसा व्यवहार करे तो तुरंत शिशु रोग विशेषज्ञ को दिखायें-

- माँ को देखकर खुशी या कोई भाव न प्रकट करता हो
- भावशून्य चेहरा
- हर वक्त अपने में ही खोया रहता हो
- किसी से आँख न मिलाता हो
- स्पष्ट न बोल पाता हो
- एक ही रट लगाए रहता हो आदि, आदि

टेंडर केयर हॉस्पिटल की शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. श्रुति सरकार का कहना है कि 'ऐसा नहीं है कि ऑटिज़्म अब नज़र आने लगा है, ये तो पहले से ही था किंतु अब युवा पालक-अभिभावक अपने बच्चे को लेकर थोड़े ज़्यादा सजग हैं इसलिए मामले सामने आने लगे हैं।' ऑटिज़्म का असर कम, ज़्यादा अथवा बहुत ज़्यादा हो सकता है इसीलिए इसको एक विस्तार या स्पेक्ट्रम के रूप में समझा जाता है। ऑटिज़्म से प्रभावित बच्चों अथवा लोगों में अक्सर ये बातें पाई जाती हैं-

- अन्य लोगों के साथ सामान्य बातचीत और संप्रेषण में कठिनाई
- सीमित रुचियाँ और बार-बार दोहराव वाला व्यवहार
- ऐसे लक्षण जो स्कूल, काम-काज और जीवन के अन्य क्षेत्रों में कार्य करने की उनकी क्षमता को प्रभावित करते हैं

सीधे शब्दों में कहें तो ऑटिज़्म या ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक दिमाग़ी विकृति या दोष है जिसमे प्रभावित इंसान न तो अपनी बात ठीक से कह पाता है और न ही दूसरों की बात समझ पाता है। वो किसी से भी संवाद स्थापित नहीं कर पाता। ये बच्चे अपने में ही खोए रहते हैं और किसी-किसी ये लक्षण बचपन में ही नज़र आने लगते हैं। जितना जल्दी इन संकेतों को भाँप लिया जाए और समुचित प्रयास किये जायें उतना ही जल्दी और बेहतर इस पर नियंत्रण किया जा सकता है।

भारत में ऑटिज़्म की मौजूदगी लगातार बढ़ रही है। इंडियन जर्नल ऑफ़ पीडियाट्रिक में प्रकाशित सन् 2021 के अध्ययन की रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर 68 बच्चों में से एक ऑटिज़्म से प्रभावित होता है। लड़कियों की तुलना में लड़कों में ऑटिज़्म अधिक पाया जाता है। ऑटिज़्म से प्रभावी पुरूष-महिला अनुपात 3:1 है अर्थात लड़कियों की तुलना में तीन गुना अधिक लड़के ऑटिज़्म से प्रभावित होते हैं।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक़ दुनिया में हर 160 बच्चों में एक ऑटिज़्म से प्रभावित होता है किन्तु वयस्कों में ऑटिज़्म को बताने वाला कोई विश्वसनीय आँकड़ा मौजूद नहीं है जो एक नयी चुनौती है। सेंटर फ़ॉर डिज़ीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन का एक अनुमान अमरीका की 2.21 फ़ीसदी आबादी को ऑटिज़्म से प्रभावित दर्शाता है। इन आँकड़ों से साफ़ ज़ाहिर है कि ऑटिज़्म सिर्फ़ बच्चों में ही नहीं बल्कि बड़ों में भी हो सकता है। और तो और ये किसी भी उम्र में हो सकता है। बालिगों में ऑटिज़्म की पहचान करना बच्चों की तुलना में कठिन है क्योंकि वयस्कों में ऑटिज़्म के लक्षण अन्य मानसिक विकारों के लक्षणों के साथ परस्पर आच्छादित होते रहते हैं। अभी भी ऑटिज़्म होने के सही कारणों का ठीक-ठीक पता नहीं है, इस पर शोध चल रही है। फिर भी ऑटिज़्म विकसित होने की बढ़ती संभावना से जुड़े कुछ कारकों में शामिल हैं-

- सगे भाई-बहन का ऑटिस्टिक होना
- बच्चे के जन्म के समय माता-पिता की उम्र अधिक होना
- कुछ निश्चित जीन स्थितियाँ होना (जैसे डाउन सिंड्रोम, फ़्रैजाइल एक्स सिंड्रोम)
- जन्म के समय वज़न बहुत कम होना

ऑटिस्टिक बच्चों के माता-पिता को तमाम नसीहतें देना बहुत आसान है किन्तु हक़ीक़त में उन्हें कितना कुछ करना पड़ता है ये वही जानते हैं। चाँदनी पाठक की साढ़े चार साल की बेटी आर्या ऑटिस्टिक है। जब वो डेढ़ साल की थी तब माँ ने महसूस किया कि आर्या अन्य बच्चों की तरह प्रतिक्रिया नहीं देती है। कुछ दिन इंतज़ार के बाद चिकित्सक से संपर्क किया तब बताया गया कि वो ऑटिस्टिक है। तब तक आर्या पौने दो साल की हो चुकी थी और कोविड की दूसरी लहर शबाब पर थी। चाँदनी कहती हैं कि डॉक्टर ने सख़्ती से कह दिया था कि अभी इस पर पूरा ध्यान दो तो स्थिति नियंत्रण में आ सकती है। जितना देर करोगी उतना ही कठिन और नामुमकिन होता जाएगा। चाँदनी और उनके पति आशीष ने कड़ी मेहनत की, बच्चे के साथ लगे रहे तब आज इस मुक़ाम पर पहुँचे हैं कि आर्या सामान्य बच्चों के साथ के जी वन में पढ़ रही है। चाँदनी बताती हैं कि वैसे तो आर्या का व्यवहार अब काफ़ी ठीक है फिर भी कई दिक़्क़तें आती रहती हैं। इसी तरह तृप्ति अरोरा (परिवर्तित नाम) का 11 वर्षीय बेटा एक आवासीय विशेष विद्यालय में रहता है। वो अपेक्षाकृत शांत है और रंगों से खेलता रहता है। उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती उसे निरंतर व्यस्त रखना है जो न केवल बेहद मुश्किल है बल्कि अत्यंत ख़र्चीला भी। तृप्ति संपन्न परिवार से हैं इसलिए ख़र्च वहन करने का मसला नहीं है बावजूद इसके प्रशिक्षित और निष्ठावान विशेष शिक्षक या अनुदेशक मिलना दूभर है। उनका समय से पहले जन्मा दूसरा बच्चा अभी सवा साल का है और कमज़ोर है। अब उनकी चिंता यही है कि कम से कम वो ऑटिस्टिक न हो। एक आम परिवार के लिए ऑटिज़्म का उपचार और प्रबंधन कर पाना न सिर्फ़ कठिन है बल्कि काफ़ी मँहगा है। फिलहाल सरकारी अस्पतालों में ये सुविधा अभी उपलब्ध नहीं हैं।

भोपाल के वरिष्ठ शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. अतुल कटारिया का कहना है कि शहरों में ऑटिज़्म ठीक होने की दर पहले से बेहतर हो रही है और संतोष है कि लोग ऑटिज़्म को स्वीकार कर रहे हैं जिसका मूल कारण जागरूकता और जल्दी पहचान है। किंतु अभी भी दूरस्थ अंचलों में लोगों को जागरूक करने और चिकित्सक तक पहुँचाने के लिए सघन प्रयास करना होंगे। डॉ. कटारिया कहते हैं कि ऑटिज़्म प्रभावित बच्चे का सामान्य स्कूल में दाख़िला होना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि ऐसे बच्चों के लिए स्कूलों में भी कुछ शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए या विशेष शिक्षक नियुक्त किया जाना चाहिए ताकि प्रभावित बच्चे पर नज़र रखी जा सके और ज़रूरत पड़ते ही तुरंत हस्तक्षेप किया जा सके। उनका मानना है कि थेरेपी के नियोजन और क्रियान्वयन में चिकित्सक, उपचार दल, अभिभावक और स्कूल की सम्मिलित सहभागिता होनी ज़रूरी है।

आज भारत और मध्यप्रदेश में कई संस्थाएँ ऑटिज़्म प्रभावित बच्चों के लिए काम कर रही हैं और उनका जीवन बेहतर बनाने की कोशिश कर रही हैं। भोपाल में भी आरुषि, उमंग, लक्ष्य, आधार और आनन्दम आवासीय केन्द्र सहित कई संस्थाएँ कार्यरत हैं जहाँ दिनभर बच्चों को तरह-तरह की गतिविधियों और उपचार से ऑटिज़्म से निजात पाने की कोशिश की जाती है। आरुषि में मिट्टी के काम भी बच्चों को सिखाया जाता है जिसके बेहतर परिणाम मिल रहे हैं। आजकल 'क्ले थेरेपी' पर बहुत शोध हो रहे हैं और ये पाया जा रहा है कि किसी भी मानसिक विकार से ग्रस्त व्यक्ति में लचीली मिट्टी साथ समय बिताने से प्रतिक्रिया और संचार की शुरुआत हो सकती है।

शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. जगमीत कौर चावला, जो बच्चों के विकास में दक्षता रखती हैं बताती हैं कि ऑटिज़्म का कोई लक्षित इलाज नहीं है लेकिन चिकित्सा उपचार (थेरेपी) और अनुशासित प्रबंधन से काफ़ी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। डॉ. चावला के भोपाल स्थित आधार सेंटर में ऑटिज़्म प्रभावित बच्चों की वैज्ञानिक तरीक़े से देखभाल की जाती है। आधार सेंटर में समाहित उपचार के अन्तर्गत विशेष शिक्षा (स्पेशल एजुकेशन), आँख से आँख मिलाना (आई कांटैक्ट), अपनी बात कह सकना (कम्युनिकेशन), प्रसाधन आदतें, रोज़मर्रा के क्रियाकलाप आदि का विधिवत प्रामाणिक प्रशिक्षण दिया जाता है। कुल मिलाकर लब्बेलुआब है कि ऑटिज़्म प्रभावित बच्चे भी सामान्य बच्चों के साथ एक ही स्कूल में पढ़ सकें और काफ़ी हद तक एक सामान्य जीवन जी सकें। ऑटिज़्म प्रभावित व्यक्ति को उसके लक्षणों की गंभीरता और ज़रूरत के हिसाब से चिकित्सक दवाइयाँ भी देते हैं जिससे चिड़चिड़ापन, आक्रामकता, दोहराव वाला व्यवहार, अति सक्रियता, एकाग्रता मं कमी, चिंता और अवसाद आदि में कुछ हद तक नियंत्रण किया जा सकता है।

डॉ. चावला कहती हैं कि ऑटिस्टिक बच्चों में एक ही काम को बार-बार लगातार कर सकने की विलक्षण क्षमता होती है। वे कभी बोर नहीं होते हैं। उनकी कंप्यूटर सहजता भी अचंभित करती है। इसी गुण को देखते हुए स्विट्ज़रलैंड सहित कई देशों में ऑटिस्टिक लोगों का इस्तेमाल उद्योगों में किया जाता है। कई ऑटिस्टिक व्यक्ति बेहद प्रतिभाशाली होते हैं। कुछ ऑटिज़्म से प्रभावित प्रसिद्ध हस्तियाँ हैं- मशहूर पेंटर, अन्वेषक लियोनार्डो दा विंसी और माइकलएंजिलो, महान वैज्ञानिक आईज़ेक न्यूटन और अल्बर्ट आइंस्टीन, अभिनेता एंथोनी हॉपकिन्स, शतरंज ग्रैंडमास्टर बॉबी फ़िशर, संगीतकार बीथोवन, मोज़ार्ट और बॉब डायलेन, फ़िल्मकार अल्फ्रेड हिचकॉक और स्टीवन स्पीलबर्ग, मनोवैज्ञानिक कार्ल जुंग, लेखक जॉर्ज ऑर्वेल और जेन ऑस्टिन, माइक्रोसॉफ़्ट संस्थापक बिल गेट्स और फ़ुटबॉल खिलाड़ी लियोनिल मैसी आदि।

आज के डिजिटल युग में सामान्य ऑटिज़्म के साथ-साथ आभासी ऑटिज़्म (वर्चुअल ऑटिज़्म) एक नयी चुनौती है। ऑटिज़्म पैरेंटिंग मैगज़ीन के अनुसार वर्चुअल ऑटिज़्म एक ऐसी अवस्था है जो तीन साल से कम उम्र के बच्चों में देखी जाती है। मोबाइल या टेबलेट के स्क्रीन के बहुत ज़्यादा नज़दीक रहने या स्क्रीन पर अत्यधिक वक़्त बिताने की वजह से ऐसा होता है। यदि बच्चा बहुत देर तक टीवी या स्क्रीन को लगातार देखता है, तो उसमे ऑटिज़्म जैसे लक्षण या संकेत विकसित हो सकते हैं। सब कुछ जानते हुए भी युवा अभिभावक यदि खुद पर और बच्चों पर पाबंदियाँ न लगा पाएँ तो इसको रोक पाना असंभव है। आज हमारे पास कम से कम ऑटिज़्म पर बात करने, उस पर फ़ोकस करने, उसकी पहचान और निदान के अवसर तो हैं। जागरूकता से हम ऑटिज़्म के प्रबंधन के हर पहलू को बेहतर जान सकते हैं। किंतु सिर्फ़ जान लेना जी काफ़ी नहीं, तुरंत कार्यवाही ज़रूरी है। इसलिए जब भी हमे अपने परिवार में या अपने आसपास कोई भी बच्चा या वयस्क ऐसा दिखे जिसमें ऑटिज़्म के कुछ लक्षण परिलक्षित होते हों तो तुरंत पहल करें और उसे विशेषज्ञ चिकित्सक के पास पहुँचायें। माना राह कठिन है किन्तु हम सबके समुचित प्रयास से ही ये मुमकिन हो सकेगा।

अधिकारी-कर्मचारी निर्वाचन कार्यों को पहले दें प्राथमिकता : कलेक्टर

अवैध कॉलोनियों के निर्माण पर तुरंत लगाए अंकुश

बैतूल। लोकसभा निर्वाचन के अनुक्रम में निर्वाचन कार्यों में लगे सभी अधिकारी एवं कर्मचारी सौंपे गए दायित्वों का प्राथमिकता से निर्वहन करें। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी कलेक्टोरेट सभागार में सोमवार को निर्वाचन कार्यों में लगे अधिकारियों एवं कर्मचारियों से उन्हें सौंपे गए दायित्वों की बिन्दूवार समीक्षा कर रहे थे। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी अक्षत जैन, सहायक कलेक्टर ऐश्वर्य वर्मा, एडीएम जयप्रकाश सैय्याम, एडीएम राजीव नंदन श्रीवास्तव एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी मकसूद अहमद सहित सभी विभागीय अधिकारी एवं राजस्व अधिकारी उपस्थित थे।

अवैध कॉलोनियों पर लगाए अंकुश- कलेक्टर श्री नरेन्द्र सूर्यवंशी ने सभी एसडीएम एवं तहसीलदारों को संबोधित करते हुए कहा कि अवैध कॉलोनियों की बढ़ती संख्या की वजह उनके निर्माण को प्रारंभ अवस्था में ना रोककर उसके वैध होने का इंतजार करना है। यह सोच उचित नहीं है। किसी भी क्षेत्र में यदि इस प्रकार की कॉलोनी बनना शुरू होती है उसी समय उनके विरूद्ध कार्रवाई करें। फिर इन कॉलोनियों के विरूद्ध रेरा जैसे दूसरे आयोग कार्रवाई करते है। जब हम अपना काम ईमानदारी से नहीं करते तब दूसरी एजेंसियों हमारा काम करती है। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से समन्वय करें। ऐसी संपत्तियों के क्रय विक्रय पर भी रोक लगाए।

बंदरों को करें रेस्क्यू- कलेक्टर ने विगत दिनों बंदरों के द्वारा राहगीरों को काटे जाने की घटनाओं पर अधिकारियों से चर्चा की। उन्होंने कहा कि वन विभाग के अधिकारियों से कहा कि बंदरों को रेस्क्यू करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि बेहद खेदजनक है कि जिम्मेदार अपनी बढ़ती अधिकारी जिम्मेदारी एक दूसरे पर डाल रहे है। उन्होंने कहा कि आप लोग आपसी समन्वय के साथ काम करें। आम आदमी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। मानव जीवन सुरक्षा प्रशासन की जिम्मेदारी है और हमें हर हाल में उन्हें सुरक्षा प्रदान कराना है।

लंबित विभागीय जांच को करें एक माह में पूर्ण- कलेक्टर ने अधिकारियों से कहा कि आपके अधीनस्थ विभाग में विभागीय जांच काफी लंबे समय से लंबित है। इन पर आप लोग कार्रवाई नहीं कर रहे। पुरानी शिकायतें नहीं निपटाने के कारण नई शिकायतें पुरानी शिकायतों में जुड़ जाती है। विभागीय जांच की संख्या बढ़ती जाती है। एक माह के भीतर लंबित विभागीय जांच पूरी करें। उन्होंने लायजनिंग कार्य में लगे अधिकारियों से कहा कि आब्जर्वर हमारे अतिथि है जो हमारे संसदीय क्षेत्र में निर्वाचन कार्य संपादन कराने आए है। वे भौगोलिक स्थिति से परिचित नहीं है। उनके साथ प्रोटोकॉल और डेकोरम को मेंटेन करें। वो कभी कहीं भी संसदीय क्षेत्र का भ्रमण कर सकते है और उनके भ्रमण स्थल पर पहुंचने पर उनके प्रवास, सुरक्षा आदि व्यवस्था अपडेट रखे।

मतदान केन्द्रों पर हो आवश्यक सुविधाएं- जिला निर्वाचन अधिकारी ने 8 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान केन्द्रों पर मतदाताओं के लिए मूलभूत सुविधाएं, विद्युत व्यवस्था, पेयजल एवं सुरक्षा व्यवस्था अपडेट रखें। दिव्यांग और 85+ मतदाताओं के लिए व्हीलचेयर, रैम्प आदि व्यवस्थित रखने के निर्देश दिए।

खुल कर करो मतदान

मेहंदी, फेस पेन्टिंग, रैली निकालकर किया प्रेरित

बैतूल। चुनाव किसी भी श्रेणी का हो देशहित में मतदान अवश्य करना चाहिए। इसी उद्देश्य को लेकर मप्र शासन मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत स्वीप के नोडल अधिकारी के आदेश के परिपालन मे आगामी लोकसभा निर्वाचन 26 नवम्बर 2024 को मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के उद्देश्य से एवं मतदाता जागरकता अभियान के अंतर्गत जेएच कालेज प्राचार्या डॉ.विजेता के चौबे के संरक्षण मे स्वीप के जिला सहायक नोडल

अधिकारी डॉ.सुखदेव डोंगरे, एनसीसी की लेफ्टिनेट डॉ.कमलेश अहिरवार की उपस्थिति मे प्रभारी प्राचार्य डॉ.अनिता सोनी ने एनएसएस के 100 स्वयसेवकों को मतदान की शपथ दिलाई। एनएसएस के स्वयसेवको अनिवार्य मतदान विषय पर मेहंदी प्रतियोगिता में 09 एवं फेस पेन्टिंग प्रतियोगिता 9 स्वयंसेवकों ने सहभागिता की। मेहंदी प्रतियोगिता प्रथम नेहा किरोदे, द्वितीय मिताली नेमा और तृतीय सोनम पाटिल और फेस पेन्टिंग मे प्रथम अजय, उठले, द्वितीय निशा किरोदे, तृतीय मुस्कान बडखाने स्थान प्राप्त किया। स्वयंसेवक अंजली रावन्धे को उनके जन्मदिन पर पुष्पगुच्छ एवं पेन भेंट किया गया। प्रतियोगिता सम्पन्न कराने मे दलनायक आयुष घिड़ोडे, उपदलनायक अंजली नागोरे, सुरभि जैन, ऋषक पारिसे, नवीन नागले, हिमाशु पाटिल, अक्षय मालवी, कोमल देशमुख, दुर्गाप्रसाद मोरले, कुणाल केकतपुरे आदि का सराहनीय योगदान रहा।

कलेक्ट्रेट कार्यालय में राष्ट्रगान जन-गण-मन का हुआ सामूहिक गायन

बैतूल। माह के प्रथम शासकीय कार्य दिवस पर सोमवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय परिसर में राष्ट्र गान जन-गण-मन का सामूहिक गायन हुआ। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी की उपस्थिति में गायन के समय सीईओ पंचायत अक्षत जैन, एडीएम जे.पी. सैयाम, उप जिला निर्वाचन अधिकारी मकसूद अहमद, संयुक्त कलेक्टर अनिल सोनी, उप जिला अध्यक्ष अजीत मरावी सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे। सामान्य प्रशासन विभाग के आदेशानुसार सभी शासकीय कार्यालयों में अधिकारी, कर्मचारियों द्वारा प्रत्येक माह के प्रथम कार्य दिवस पर राष्ट्रगान गाया जाता है। जिला मुख्यालय पर यह कार्यक्रम प्रतिमाह के प्रथम कार्य दिवस पर कार्यालय प्रारंभ होने के तत्काल पूर्व समारोहपूर्वक आयोजित किया गया।

मोटर पंप चोरी करने वाले तीन आरोपियों को किया गिरफ्तार, तालाब से चुराई थी मोटर

बैतूल। दिनेश पिता सुकुमार हलदार निवासी पूंजी कैंप ने रिपोर्ट किया कि 29 मार्च को दरमियानी रात को खेत में बने तालाब में से मोटर पंप को कोई अज्ञात चोर चोरी कर ले गया है। मोटर पंप सीआरआई कंपनी की जिसकी कीमत 11925 रुपए है। फरियादी की रिपोर्ट पर अज्ञात के खिलाफ धारा 379 भादवि का कायम कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान विश्वसनीय मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई की गोलाई खुर्द के तीन लडके मोटर पंप बेचने के लिए ग्राहक ढूंढ रहे है। सूचना मिलने पर वरिष्ठ अधिकारीयो को

अवगत कराकर थाना चोपना से थाना प्रभारी उपनिरीक्षक राकेश सरयाम, सहाउपनिरी राजेश कलम,प्र आर 539 ज्ञानसिंग टेकाम,आर आशुतोष,राहुल ,आर चालक मनदीप द्वारा ग्राम गोलाई खुर्द से तीन संदेही रामकिशन पिता करन सिंह पंड्राम उम्र 27 साल, सोहन पिता वालेसिंग उईके उम्र 21 साल,सुनील पिता रमेश बरकड़े उम्र 21 साल सभी निवासी गोलाइखूर्द को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। आरोपियों ने 29 मार्च को फरियादी दिनेश के तालाब से मोटरपंप चोरी करना स्वीकार किया है। आरोपी रामकिशन पंड्राम के घर से चोरी की सीआरआई कंपनी की 2 एच पी की मोटर पंप एवं घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल बरामद की किया है। तीनो आरोपियो को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया जा रहा है ।

श्री राम जन्मोत्सव आयोजन 17 अप्रैल को

अपील हिन्दू समाज से

बैतूल। समाजसेवी गंज क्षेत्र के फ़ेमस बाबू कचौड़ी के संचालक ने भगवान श्री रामचंद्र जी के जन्मोत्सव के पावन अवसर पर विशाल भव्य शोभा यात्रा बुधवार शाम 5 बजे सदर स्थित गेंदा चौक से निकलेगी। हिन्दु समाज ने अपील कि की कार्यक्रम को सफल बनाने हेतू सहयोग प्रदान करें।

संजय शर्मा 3 अप्रैल को भरेंगे नामांकन

कांग्रेसियों ने ज्यादा से ज्यादा संख्या में शामिल होने की अपील की

नर्मदापुरम। नरसिंहपुर संसदीय क्षेत्र के कांग्रेस के प्रत्याशी तेंदूखेड़ा के पूर्व विधायक संजय शर्मा 3 अप्रैल को दोपहर 11:00 बजे होशंगाबाद कलेक्ट्रेट में नामांकन दाखिल करने के बाद विशाल आम सभा को संबोधित करेंगे कांग्रेस प्रत्याशी संजय शर्मा का नामांकन दाखिल करने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मध्य प्रदेश के प्रभारी जितेंद्र भंवर सिंह, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी प्रदेश के सह प्रभारी संजय कपूर वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तंखा पूर्व मंत्री मुकेश नायक होशंगाबाद लोकसभा के आठों विधानसभाओं के सभी कांग्रेस प्रत्याशी, कांग्रेस जिला अध्यक्ष एवं समस्त वरिष्ठ पदाधिकारी समेत कई वरिष्ठ नेता, कार्यकर्ता जन होशंगाबाद पहुंचेंगे एवं आम सभा को संबोधित करेंगे नर्मदापुरम के वार्ड क्रमांक 9 की जिला पंचायत सदस्य हाकम सिंह गुर्जर ने जिला वार्ड एवं सुहागपुर विधानसभा के समस्त वरिष्ठ कांग्रेस पदाधिकारी जिला पंचायत सदस्य जनपद सदस्य पंच एवं सरपंचों, आम नागरिकों, कार्यकर्ता से अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने की अपील की है।

सेन समाज ने ली मतदान की शपथ

सेन समाज का होली मिलन संपन्न

बैतूल। सर्व सेन समाज कल्याण एवं विकास समिति का होली मिलन समारोह काशी तालाब में संपन्न हुआ। जिसमें एक-दूसरे को रंग लगाकर बधाई दी। साथ ही समाज के जिला अध्यक्ष रमेश बोरखड़े ने सभी उपस्थित स्वजातीय बंधुओं को अनिर्वाय मतदान की शपथ दिलवाई। इस मौके पर उपाध्यक्ष संजु श्रीवास व राजु मालवी ने बताया कि आज समाज के लोगों ने शपथ ली है कि स्वयं भी मतदान करेंगे और लोगों को भी प्रेरित करेंगे। इस अवसर पर एमएल बघेले, सचिव रामनारायण उच्चसरे, युवा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष दीपक मालवी, भगवान दास बोरकर, सदन कुरावले, पवन मालवी, दिनेश देशकर, हरिराम उच्चसरे, सेवाराम उच्चसरे, उदल जयसिंगपुरे, प्रफुल्ल बघेले, मनोहर श्रीवास, महावीर सोनकपुरिया, संजु नगदे,सदन कुरावले, सुंदरलाल सोलंकी, मदन कु रावले सहित बड़ी संख्या में सामाजिक बंधु मौजूद थे।

खेत मालिक पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज

मामला नरवाई की आग में बुजुर्ग के जिंदा जलने का

बैतूल। आठनेर खेत में नरवाई की आग की चपेट में आने से एक बुजुर्ग की दर्दनाक मौत हो गई थी। बुजुर्ग घास और लकड़ी में लगी आग को बुझा रहा था। यह आग पास के खेत में नरवाई जलाने के कारण घर तक पहुंच गई थी। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। इस मामले में आठनेर पुलिस ने नरवाई जलाने वाले खेत मालिक राजिक खान पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज करते हुए उसे अभिरक्षा में ले लिया है। यह हादसा जिला मुख्यालय से करीब 40 किमी. दूर आठनेर थाने के अंतर्गत ग्राम उमरी लालखेड़ी में रविवार की शाम को हुआ था। सूचना मिलने पर पुलिस और फायर बिग्रेड मौके पर पहुंची थी आग पर काबू पाया था। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम उपरांत परिजनों को सौंप दिया है।खेत मालिक पर दर्ज किया मामला 7 आठनेर प्रभारी सारविंद धुर्वे ने बताया कि उमरी निवासी जोगी पदाम उम्र 60 साल की खेत की नरवाई की आग से जलने के कारण मौत हो गई थी। मृतक के पुत्र भुरूलाल पदाम की शिकायत पर पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू दी है। इस मामले में नरवाई जलाने वाले खेत मालिक राजिक खान पर भी गैर इरादतन हत्या की

धारा 304 का मामला दर्ज कर अभिरक्षा में लिया गया है। नरवाई की आग से हुई थी ग्रामीण की मौत आग लगने के पीछे जो कारण सामने आए है उसमें बताया जा रहा है कि लालखेड़ी निवासी राजिक खान नाम के व्यक्ति ने अपने खेत मे नरवाई जलाई थी । नरवाई की आग खेत के पास जोगी पदाम के घर सामने रखी लकड़ी और घास तक पहुंच गई थी । इसी आग को बुझाने के दौरान वो आग की चपेट में आ गया और आग लगने से उसकी मौत हो गई। पुलिस की सूचना पर दमकल की टीम मौके पर पहुँची और आग पर काबू पाया गया। पुलिस भी इस मामले में जांच कर रही है और पता कर रही है कि इस घटना में किसी की लापरवाही तो नहीं है।

विद्युत कटौती शेड्यूल, आज इन स्थानों पर बंद रहेगी बिजली

बैतूल। मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड बैतूल शहर द्वारा 2 अप्रैल को 11 केव्ही टाऊन-2 में मेंटेनेंस कार्य किया जाना है। मेंटेनेंस कार्य के चलते मंगलवार को प्रातः 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक लिंक रोड, चंद्रशेखर वार्ड, कारगिल चौक, बारस्कर कॉलोनी, इंदिरा वार्ड, पीडब्ल्यूडी कॉलोनी, कोठी बाजार, कंपनी गार्डन, आजाद वार्ड, गर्ल्स कॉलेज, वीवीएम कॉलेज, तल्लैया मोहल्ला, अंबेडकर चौक, उमप किराना, राठी अस्पताल, ड्रीम होम्स कॉलोनी, नेहरू पार्क आदि क्षेत्र में विद्युत सप्लाई बंद रहेगी।

सदर में 3 अप्रैल को विद्युत सप्लाई रहेगी बाधित- मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड बैतूल जोन 02 के प्रबंधक शहर ने बताया 3 अप्रैल को 11 केव्ही सदर में मेंटेनेंस कार्य किया जाएगा। मेंटेनेंस कार्य के चलते प्रातः 9.30 बजे से दोपहर 1 बजे तक एमपीईबी कॉलोनी, अग्रिहात्री कॉलोनी, सतपाल आश्रम, प्रताप वार्ड, सुपर किराना, सिंडीकेट बैंक, एसबीआई बैक, गेंदा चौक, ब्रम्हकुमारी आश्रम, मानस नगर, आईटीआई, एफसीआई गोडाउन, विनायक रेसीडेंसी, बसंत पेट्रोल पंप, गाड़ाघाट रोड, सोनाहिल कॉलोनी में विद्युत सप्लाई बाधित रहेगी।

11 केव्ही टिकारी में बिजली कटौती 4 अप्रैल को- टिकारी के 11 केव्ही फीडर में 4 अप्रैल को मेंटेनेंस कार्य प्रस्तावित है। मेंटेनेंस कार्य के चलते गुरुवार को प्रातः 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक बच्चा जेल, प्रताप वार्ड, महावीर वार्ड, अखाड़ा चौक, जेरी चौक, गाराघाट पंप, पटने आ चक्की, नागदेव मंदिर टिकारी, ईशाई चौक, नर्स ट्रेनिंग स्कूल, कृष्णापुरा ठाकरे की चाल, मोती वार्ड, डॉ.कसेरा, गोठी कॉलोनी, फांसी खदान से दादावाड़ी, डॉ.पाडी गौठाना नाका, शारदा नगर, वैष्णवी नगर, गंगोत्री कॉलोनी, कमानी गेट, थाना चौक, मांग मोहल्ला, दुर्गा वार्ड, गूड़ बाजार, गांधी चौक, साईं मंदिर टिकारी में विद्युत सप्लाई बंद रहेगी।

इटारसी रोड क्षेत्र में विद्युत कटौती 5 अप्रैल को- 5 अप्रैल दिन शुक्रवार को इटारसी रोड 11 केव्ही फीडर में मेंटेनेंस कार्य चलते प्रातः 9.30 बजे से दोपहर 1 बजे तक फॉरेस्ट नाका, बालाजी विहार, गाड़ाघाट, इटारसी रोड, चक्कर रोड, अनुराग टेन्ट हाऊस, सरस्वती स्कूल, बसंत पेट्रोल पंप, बीईडी कॉलेज क्षेत्र में विद्युत सप्लाई बाधित रहेगी। इसी प्रकार 6 अप्रैल दिन शनिवार को 33 केव्ही टिकारी टाऊन में मेंटेनेंस कार्य किया जाना है। मेंटेनेंस कार्य चलते 33/11केव्ही हमलापुर एवं टिकारी सब स्टेशन से निकलने वाले सभी 11 केव्ही फीडर प्रभावित रहेगी।

पुलिस द्वारा चलाया जा रहा है वारंटियों की धरपकड़ का अभियान

बैतूल। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर गिफ्तारी व स्थाई वारंटियो की धरपकड़ का अभियान बैतूल पुलिस द्वारा चलाया जा रहा है । इस हेतु वरिष्ठ अधिकारियो द्वारा थाना क्षेत्र के वारंटियों को शतप्रतिशत तामिल करने के निर्देश मिले है। इसी तारतम्य में थाना आठनेर पुलिस द्वारा विगत 02 वर्षो से फरार 02 स्थाई वारण्टियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। थाना प्रभारी के निर्देशन में आठनेर पुलिस की टीम द्वारा जेएमएफसी न्यायालय भैंसदेही के न्यायालय से जारी अपराध 110/18 धारा 498 ए,323,506 भादवि व द.प्र.क्र. 736/16 परिवादी विकास धारा 138 एनआईटी एक्ट मे आरोपी स्थाई वारंटी क्रमाशः मन्नु पिता भद्दू उईके जाति गोडं उम्र 35 साल निवासी कोयलारी थाना आठनेर व मनोज पिता युवराज इवने उम्र 35 साल निवासी गाम बोरपेंड को दिनांक 30/03/2024 व 31/03/2024 की दरम्यानी रात्रि सकुनत में दबिश देकर गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है । सभी स्थाई वारण्टियो को माननीय न्यायालय भैंसदेही पेश किया जा रहा है। उपरोक्त 02 स्थाई वारण्टी पिछले 02 वर्षो से फरार चल रहे थे । उक्त स्थाई वारण्टियो को उनकी सकूनत ग्राम कोयलारी व बोरपेड से गिरफ्तार किये जाने में थाना आठनेर के उनि मागीलाल ठाकरे, सउनि दिनेश धुर्वे, आर क्र. 617 अजय, चालक क्र. 559 किशोर की सराहनीय भूमिका रही है।

व्याख्यान माला संपन्न, भारतीय ज्ञान परंपरा में निहित है पर्यावरण चेतना : डॉ.साधना पांडे

बैतूल। जेएच कॉलेज में संचालित ईको क्लब द्वारा पर्यावरण शिक्षण कार्यक्रम अंतर्गत 'भारतीय वैदिक एक पांम्परिक ज्ञान प्रणाली को पुनः जीवंत करना' विषय व्याख्यान का आयोजन किया गया। मुख्य वक्ता प्रो. डॉ.साधना पांडे ग्वालियर ने अपने व्याख्यान में वर्तमान संदर्भ में भारतीय ज्ञान परिचय की उपयोगिता को सारगर्भित किया। उन्होने भारत की प्राचीन शिक्षा पद्धति पर भी प्रकाश डालते हुए हमारे वेदों में उल्लेखित कृषि, निकितन और पर्यावरण संरक्षण की विधियों को भी समझाया। जो कि समग्रतापूरक आधारित तथा कला कौशल के ज्ञान से परिपूर्ण थी। उन्होने विशेष रूप से हमारे प्राचीन ग्रंथ संत सुरपाल द्वारा लिखित वृक्ष आयुर्वेद में उल्लेखित कृषि पद्धति और वर्तमान समय में इसके महत्व से छात्र-छात्राओं को अवगत करया। उन्होने बताया कि अब हमें सस्टेनेबल डवलपमेंट की जगह रिजनटेटिव सस्टेनिबिलिटी

डवलपमेंट को ज्ञान में लाना होगा। अभी हम प्राकृतिक संसाधनों को जिस रूप में मिले हैं उन्हें अगली पीढी को वैसा ही सौंपना है। कार्यक्रम की आयोजक ईको क्लब प्रभारी डॉ.अल्का पांडे ने कहा कि भारतवर्ष के प्राचीनतम वैदिक एवं पारम्परिक ज्ञान में पर्यावरण संतुलन पर आधारित ध्यान दिया गया है। किन्तु पश्चिम सभ्यता के प्रभाव में आकर मानव ने सस्टेनेबल डवलपमेंट तथा पर्यावरण संरक्षण के सिद्धांतो की अवहेलना की है। प्राचार्या डॉ.विजेता चौबे ने सभी विद्यार्थियों को पर्यावरण से संबंधित प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन कर अपने प्राजेक्ट कार्य पूर्ण करने की बात कही। विद्यार्थियों ने प्रश्न पूछकर अपनी जिज्ञासा का समाधान किया। कार्यक्रम में प्रो.अर्चना सोनारे, डॉ.अर्चना मिश्रा, प्रो.सुनीता गढ़ेकर, डॉ.महेन्द्र नावंगे, प्रो.दिपिका साहू सहित एक सैंकड़ा से अधिक विद्यार्थी मौजूद थे।

नर्मदापुरम की हलचल..

संजीव डे राय

प्रबंधन नहीं शिक्षक सफाई दे रहे..!

एक निजी स्कूल में शिक्षकों के सामूहिक स्तीफा देने की चर्चा चौक चौराहों पर हो ही रही है। बात फैली तो वहां के शिक्षक सफाई देने सोशल मीडिया पर आ गए, स्कूल की तारीफ के पुल बंधने लगे, स्कूल में सब कुछ ठीक है। इस सफाई से बू आती है, हालांकि स्कूल प्रबंधन चुप है। लेकिन बात तो सिद्ध होती है स्कूल की अंदरूनी हालत ठीक नही है। एक डर स्कूल प्रबंधन पर साफ तौर पर दिखाई देता है वो डर किसका है यह पालक बेहतर जानते है बच्चों को ऐसे स्कूल में डालना है जो साफ सुथरा माहौल बच्चो को दे सके।

मुख्यालय पर ऐसे कैसे अधिकारी..

हैरान करने वाली बात यह है कि झूठ की बुनियाद पर चल रहे सीबीएसई पाठ्यक्रम संचालित करने वाले निजी स्कूल की शिकायत मिलने पर शिक्षा विभाग के आला अधिकारी स्कूली प्रबंधन पर कार्रवाई वजनदारी से नहीं कर पाते...? मसला शांति निकेतन मांटेसरी सीनियर सेकेंडरी सीबीएसई पाठ्यक्रम चलाने वाली संस्था का ले लिया जाए यहां देढ़ दर्जन शिक्षकों ने सेशन खत्म होते ही सामुहिक स्तीफा दिया है, ज्वाइंट डायरेक्टर एजूकेशन के पूछे जाने पर बताया स्कूल प्रबंधन स्तीफा देने की बात स्वीकार करते हुए कहते है शिक्षक जनवरी में ही जाने की कह रहे थे जो सेशन समाप्ति पर गये, सामुहिक नहीं वे अलग अलग और स्तीफा देने का कारण भी कि कोई पिगनेंट (गर्भवती) है, किसी के पति का स्थानांतरण हो गया तो कोई हायर एजूकेशन के लिए स्कूल छोड़ गया। बीस साल स्कूल की सेवा करने वाले नियमित सीनियर शिक्षकों के स्तीफा देने की बात पर गौर करने वाली बात यह है कि चुनाव होने, अधिसूचना जारी है ऐसे में किसका स्थानान्तरण हो सकता है यह स्कूल प्रबंधन से पूछा जाना था खैर जिम्मेदार ने पूछना उचित नहीं समझा लेकिन उन्हें यह बात संज्ञान लेनी ही चाहिए कि सीबीएसई पाठ्यक्रम संचालित करने वाले इस स्कूल में एक साथ क्वालीफाई शिक्षक बाहर गांव के आकर पढ़ने वाले शिक्षक बच्चों की शिक्षा पर प्रभाव तो नहीं डालेंगे क्योंकि शिक्षा देने वाली संस्था ने एक तरह से शिक्षा व्यापारिक बना रखी है।

कहते थे ना आरटीओ कार्यालय में बहुत कुछ ठीक-ठाक नहीं है...

करीब आठ दिनों से आरटीओ कार्यालय में भूचाल सा है दीवार हिलती नजर आ रही। पर अधिकारी के चहरे पर शिकन नहीं..? कारण यहां से लेकर वहां उपर तक अधिकारी की सब से सेटिंग बताई जाती है.. गाड़ी नंबर CA 2624 संदीप साहू के नाम पर दर्ज है बगैर उसकी की सहमति और हस्ताक्षर से आरटीओ कार्यालय में गाड़ी अशोक पाल के नाम पर ट्रांसफर हो गई। संदीप को जब जानकारी मिली उन्होंने कलेक्टर और सीएम हेल्पलाइन 181 पर शिकायत दर्ज करा दी, आरटीओ ने फौरन कोतवाली में एफआईआर हेतु लिफाफे में पत्र लिखकर भेज दिया। लेकिन संबंधित को बीमार बताकर गाड़ी ट्रासंफर कराने वाले दलाल राजेश ने आरटीओ मैडम के हाथ पैर जोड़कर चिरौरी करते हुए किसी तरह शिकायत वापस बुलवा ली इस काम के लिए सुना जा रहा है कि उसे 70 हजार देने पड़े मजेदार बात इसमें यह भी सुनाई दे रही है कि भोपाल एमपीएसआरटी से विभाग में आरटीओ में आई महिला बाबू कर्मचारी ने भी इस काम में अलग से एक हजार रुपए ट्रांसफर मामले में दलाल से झटके थे।

सीसी डब्ल्यूएल से बगैर अनुमति लिए लोक निर्माण विभाग निर्माण कैसे कर रहा..

पचमढ़ी हिल स्टेशन पर हाईकोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ाते हुए बगैर सीसी डब्ल्यू एल (मुख्य वन प्राणी संरक्षक) से अनुमति लिए बगैर ही लोकनिर्माण विभाग साडा की जमीन पर हवाई पट्टी निर्माण कर रहा और जितने प्रशासनिक जिम्मेदार विभाग नियम कानून का पालन कराने वाले हैं वे सब ख़ामोश हैं..! जबकि निर्मित की जा रही हवाई पट्टी वाला क्षेत्र ईको सेंसेटिव जोन सहित सतपुड़ा टाइगर रिजर्व वर्ल्ड लाइफ कोर एरिया सेंसेटिव क्षेत्र से लगकर है। उच्च न्यायालय द्वारा वैसे भी पचमढ़ी हिल स्टेशन पर सभी तरह के निर्माणों को लेकर पाबंदी है फिर हिल स्टेशन पर नियम विरुद्ध निर्माण कैसे किया जा रहा है..? लगभग छह महीनों से बगैर अनुमति के लोकनिर्माण विभाग के उपयंत्री कैलाश गुर्दे कार्य करा रहे हैं। इसमें मजेदार बात यह है कि 100 फुट चौड़ी, 25 फुट गहरी और करीब देढ़ किलोमीटर क्षेत्र में खोदी गई 40 हजार धन मीटर मिट्टी कहां फैंकी गई यह रहस्य भी एक जांच का विषय है।

और अब अंत में चलते-चलते

बेशकीमती ट्रस्ट की जमीन पर अपना ट्रस्टी बनाने की जुगत..

नगर की बेशकीमती अरबों की जमीन पर उदासी मंदिर ट्रस्ट को बचा पाने में ट्रस्ट अध्यक्ष (कलेक्टर) की भूमिका उदास समझ आती है दो एकड़ के उपर बेशकीमती इस रकबे के ट्रस्ट में उदासी सम्प्रदाय के संतों के बजाय दूसरे दीगर ट्रस्टी बनकर एक तरह से अपना मकसद साध रहे हैं। तीन पीढ़ियों से ट्रस्ट की जमीन पर बतौर किरायेदार अब ट्रस्ट के लिए ये रहवासी जिन्होंने किराया देना बंद कर अब किरायेदार नहीं बल्कि कब्जाधारी साबित हो रहें। न्यायालय ने भी 2014 में तीन माह के लिए ट्रस्ट के ट्रस्टी अभिषेक शुक्ला को सचिव इस बात पर नियुक्त किया था वो ट्रस्ट की भूमि से अतिक्रमण हटाने और ट्रस्ट हित में वैधानिक कार्यवाही करेंगे लेकिन ऐसा अब तक कुछ नहीं हुआ। ट्रस्ट में 9 ट्रस्टियों में उदासी सम्प्रदाय के 4 सदस्य और बाकी पांच सदस्यों में सुदर्शनाचार्य, पं वैभव शर्मा, अभिषेक शुक्ला, डां अतुल सेठा, पवनसुत दास और सरकारी वकील के के थापक थे। ट्रस्ट के दो सदस्य दुर्गा दास उदासी और शंकर दास उदासी भोपाल की मृत्यु हो जाने पर उनकी जगह नये सदस्यों ट्रस्टी बनाने को लेकर बैठक हुई है। निर्णय रखा गया उदासी सम्प्रदाय का साधु या किसी साध्वी जो नगर की स्थाई हो को ट्रस्टी मनोनीत किया जाए। इस पर सहमति नहीं बन पाई यह खबर अन्दर के खाने से आ रही है। सुना गया है स्थानीय अच्छे लोगों का जुड़ाव धार्मिक ट्रस्ट की जमीन बचाने हेतु ट्रस्टी बनाए जाने के लिए जिसमें प्रशांत उर्फ मुन्नू दुबे, पूर्व पार्षद राधव सहित रामजी दास बाबा ट्रस्ट मंहत परिवार से संबंधित और मुकेश अग्निहोत्री का नाम बैठक में ट्रस्टी बनाने के विचार के लिए उठे, ऐसा समझा जा रहा है कि बैठक में जबरिया मुकेश अग्निहोत्री का नाम उछालकर कोरम पूरा करने के नाम पर मुकेश के नाम का उपयोग अपना ट्रस्टी बनाने की साज़िश रची है।

होली मिलन समारोह में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय शामिल हुए

भाजपा का होली मिलन समारोह ग्राम सिमराली विधायक कालु सिंह ठाकुर निवास पर संपन्न

धार। भारतीय जनता पार्टी धार महु लोकसभा क्षेत्र के सभी आठों विधानसभा में होली मिलन समारोह आयोजित कर रही है इसी क्रम में रविवार को जिले की धरमपुरी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम सिमराली क्षेत्रीय विधायक कालु सिंह ठाकुर के निवास पर भाजपा कार्यकर्ता का होली मिलन समारोह आयोजित किया गया जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व राष्ट्रीय महासचिव, कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय शामिल हुए ।

इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष मनोज सोमानी, लोकसभा चुनाव प्रभारी नंदकिशोर पाटीदार,संयोजक प्रभु राठौर, जिला प्रभारी श्याम बंसल,भाजपा प्रदेश मंत्री जयदीप पटेल,जिला पंचायत अध्यक्ष सरदार सिंह मेड़ा,पूर्व जिला अध्यक्ष विनोद शर्मा,रमेश धाड़ीवाल,दिलीप पटोंदिया,पूर्व सांसद गजेंद्र सिंह राजुखेड़ी,भाजपा लोकसभा सीट प्रत्याशी सावित्री ठाकुर,विधायक कालू सिंह ठाकुर,लोकसभा चुनाव सह प्रभारी लक्षण नायक,अशोक जैन,राजेश अग्रवाल,मुकेश परमार,रवि परिहार भाजपा जिला मीडिया प्रभारी संजय शर्मा,मंडल अध्यक्ष हुकुम वसुनिया सहित जिला पदाधिकारी एवं भाजपा वरिष्ठ नेता मंचासीन थे।झ मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं देते हुए नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए जनता से समर्थन मांगा। नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का

हमारा एक ही लक्ष्य है हम यही आज होली की शुभकामनाओं के साथ संकल्प लेकर प्रत्येक बूथ के पर जाकर चुनावी प्रबंधन के साथ कार्यकर्ता एक जुट होकर चुनाव अभियान को सर्वव्यापी बनाए। उन्होंने कहा की होली का त्यौहार शांति सद्भावना का एक प्रतीक है आज हम एक दूसरे को मोदी गुलाल लगाकर गले मिल रहे हैं । कार्यकर्ताओं उमंग और उत्साह के साथ पार्टी प्रत्याशी सावित्री ठाकुर की ताकत को मजबूती देते हुए केंद्र में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने में लग जाए।

श्री विजयवर्गीय जनजाति नर्तक टोली के बिच पहुंचकर मादल बजाय– होली मिलन समारोह कार्यक्रम में कैलाश विजयवर्गीय मंच से उतरकर जनजाति नर्तक टोली के बिच पहुंचकर मादल बजाय तथा आदिवासी गीतों पर थिरके उनके साथ भाजपा प्रत्याशी सावित्री ठाकुर और विधायक कालु सिंह ठाकुर भी झूम उठे। समारोह का संचालन भाजपा नेता अशोक जाट ने किया। जानकारी भाजपा जिला मीडिया प्रभारी संजय शर्मा ने दी।

लोकसभा चुनाव के दृष्टिकोण से भाजपा की महत्वपूर्ण कामकाजी बैठक सम्पन्न

भाजपा की कामकाजी बैठक को मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने संबोधित किया

धार। भारतीय जनता पार्टी जिला संगठन की एक महत्वपूर्ण कामकाजी बैठक रविवार को गुजरी समीप निजी होटल में सम्पन्न हुई। लोकसभा चुनाव से संबंधित यह महत्वपूर्ण बैठक को पूर्व राष्ट्रीय महासचिव एवं कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने संबोधित कर मार्गदर्शन दिया। सर्व प्रथम अतिथियों ने पितृ पुरुष के चित्रों पर माल्यार्पण कर विधिवत आरंभ किया।

इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष मनोज सोमानी,लोकसभा संयोजक प्रभु राठौर,लोकसभा चुनाव प्रभारी नंदकिशोर पाटीदार,विधायक उषा ठाकुर और कालू सिंह ठाकुर ने भी संबोधित किया। बैठक में नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि मोदी जी का डंका अंतिम छोर तक बजना चाहिए। आपके लोकसभा चुनाव क्षेत्र में 2139 बूथ है और 2 हजार चार सौ प्रमुख जनप्रतिनिधि एवं भाजपा पदाधिकारी गण है। हर एक नेता एक बूथ जिताने का लक्ष्य बना लें तो इस लोकसभा की हम पांच लाख से अधिक वोटो से जीत सकते है। भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता हर एक लाभार्थी से संपर्क करें।

इस अति महत्वपूर्ण बैठक में स्वागत उद्बोधन एवं प्रस्तावना जिलाध्यक्ष मनोज सोमानी ने प्रस्तुत किया। उन्होंने समस्त उपस्थित अतिथियों तथा कार्यकर्ताओं का अभिनंदन किया तथा बैठक की भूमिका पर प्रकाश डाला। जिलाध्यक्ष ने कहा कि लोकसभा चुनावों के चौथे चरण में मतदान होना है।इस बीच हमारे जितने भी कार्यक्रम हैं वो चलते रहेंगे चाहे वो बूथ विजय संकल्प अभियान हो चाहे हितग्राही सम्पर्क अभियान हो अथवा मंडलों, शक्ति केन्द्रों तथा बूथों की बैठकें हों सभी अनवरत चलती रहेंगी। हमारा हर अभियान बूथ तक पहुंचे इसका विशेष ध्यान रखना है। हम सभी को बूथ जीता तो चुनाव जीता के सिद्धांत पर ही इस चुनाव अभियान को संचालित करना है। आगामी समय में लगातार बड़े नेताओं का प्रवास हमारे शक्ति केन्द्र तथा मतदान केंद्रों पर होगा जिसके लिए हमारी भूमिका पहले से तय होनी चाहिए। 6 अप्रैल को पार्टी का स्थापना दिवस है जिस दिन बृहद कार्यक्रम आयोजित होंगें तथा हमारा सारा ध्यान शक्ति केन्द्र और बूथों पर केंद्रित हो ऐसी रूप रेखा आप सब तैयार करें।

भाजपा जिला मीडिया प्रभारी संजय शर्मा ने बताया कि इस महत्वपूर्ण बैठक में इस दौरान लोकसभा चुनाव प्रभारी नंदकिशोर पाटीदार,संयोजक प्रभु राठौर,जिला प्रभारी श्याम बंसल,भाजपा जिला अध्यक्ष मनोज सोमानी व इंदौर जिला अध्यक्ष चिंटू वर्मा,सांसद छत्तर सिंह दरबार,विधायक कालू सिंह ठाकुर और उषा ठाकुर,प्रदेश मंत्री जयदीप पटेल,पूर्व जिला अध्यक्ष विनोद शर्मा,रमेश धड़ीवाल, लक्षण नायक,भाजपा लोकसभा चुनाव प्रत्याशी सावित्री ठाकुर, पूर्व मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तिगांव, लोकसभा चुनाव क्षेत्र के विधानसभा चुनाव प्रभारी सह प्रभारी विधानसभा संयोजक जिला पदाधिकारी,मंडल अध्यक्ष मंडल प्रभारी मोर्चा अध्यक्ष सहित भाजपा नेता व अपेक्षित कार्यकर्ता उपस्थित थे। बैठक का संचालन जिला महामंत्री प्रकाश धाकड़ ने किया तथा आभार प्रकटन का कार्य इंदौर जिला चिंटू वर्मा ने किया ।

दिगम्बर जैन महिला महासमिति निक्षय मित्र सम्मान से सम्मानित

धार। क्षय दिवस के अवसर पर राष्ट्रिय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत जिला विभाग द्वारा जिला चिकित्सालय में कार्यक्रम आयोजित किया गया कार्यक्रम में श्री दिगंबर जैन महिला महासमिति को निक्षय मित्र सम्मान से सम्मानित किया गया सम्मान स्वरूप समिति को ट्राफी दी गई वर्तमान में महिला महासमिति के सदस्यो के सहयोग से 12 बच्चो को 6 माह तक निरंतर पोषण आहार प्रदान किया जा रहा है इस अवसर पर लक्ष्मी बांझल पदमा गंगवाल मीना जैन अर्चना छाबड़ा इंद्रा छाबड़ा शिवानी रावका नेहा छाबड़ा ममता लुहाड़िया एवं उषा गंगवाल मौजूद थी।

आध्यात्मिक संत पंडित मनमोहन मुद्गल पंचतत्व में विलीन, उमड़ा जनसैलाब, घरों से फूलों की वर्षा

हीरालाल गोलानी, सोहागपुर। भारतीय संस्कृति की अलख जगाने वाले प्रदेश के विख्यात गृहस्थ संत पंडित मनमोहन मुदगल का अल्प बीमारी के कारण भोपाल में 76साल की आयु में निधन हो गया। भोपाल से उनके पार्थिव देह को उनके निवास पलाश परिसर शंभू दरबार लाया गया। उनके निधन के समाचार की सूचना मिलने ही नगर के अलावा अन्य नगरों के उनके अनुयायियों का आना आज भी जारी रहा। शंभू दरबार से उनके पार्थिव शरीर के ऊपर उत्कृष्ट मंडप सजाया गया था। उनके अंतिम दर्शन को नगर एवं बाहर आए अनुयाई नागरिक एवं महिलाओं से शंभू दरबार खचाखच भरा हुआ था। यात्रा प्रारंभ होते ही जय शंभू का उद्घोष हुआ।वहीं अन्य नगर से आई बैंड, शहनाई वादक भी मार्मिक गीत गाते चलो रहे थे। वहीं रामधुन, कहीं राधे कृष्णा,धुन। उनकी शवयात्रा पलाश परिसर शंभू दरबार से होकर रामगंज, रामगंज पलकमती नदी रिपटा, राजेन्द्र वार्ड, बिहारी चौक, अस्पताल रोड, कन्या शाला, पुराने थाना, मुख्य बाजार, कमानिया गेट,मातापुरा, से होकर जमनी अंतिम संस्कार केन्द्र पहुंचा। इसके पूर्व कमानिया गेट से लेकर बिहारी चौक तक फूलों की वर्षा होती रही। जगह जगह श्रद्धालुओं ने पेय जल की व्यवस्था की थी। इस अंतिम यात्रा में नगर के अलावा उनके अनुयायियों मुम्बई, भोपाल, रायपुर, करेली, नरसिंहपुर, गाडरवारा, दमोह, सागर, इत्यादि नगरों के भक्त अपने चार पहिया

वाहनों से आए थे। अंतिम संस्कार मंत्रों उच्चारण के साथ किया गया। इसी अवसर पर दो मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उनकी अंतिम यात्रा में समस्त समुदाय के नागरिक, जनप्रतिनिधि, किसान, स्नेहीजन शामिल थे। उनकी अंतिम यात्रा के अवसर पर सोहागपुर नगर के व्यवसायियों ने अपने-अपने प्रतिष्ठान दोपहर एक बजे तक बंद रखे थे।

उल्लेखनीय है पंडित मनमोहन मुदगल ने मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में करीबन 27 से अधिक विभिन्न यज्ञों का आयोजन किया था। वहीं उनके पिताश्री स्वगीर्य भागवत प्रसाद मुद्गल की स्मृति में लगभग 20 सालों से श्री राम कथा का आयोजन करते थे। वहीं विगत लम्बे अरसे से चौदस के दिन शंभू दरबार में आध्यात्मिक बैठक पंडित मनमोहन मुदगल करते थे। जिसमें सोहागपुर के अलावा उनके अनुयायियों की संख्या बहुतायत में रहती थी। आध्यात्मिक शक्ति के भावनात्मक समर्पण से कष्टों का निवारण होता था।इसी कारण विगत 40 सालों से उनके कष्ट निवारण की उपलब्धि से अनुयायियों की संख्या में इजाफा होता गया। पूर्व पार्षद लक्ष्मीनारायण सोनी ने कहा कि नगर ही नहीं प्रदेश का एक सितारा ब्रह्म में समा गया।उनके रिक्त स्थान की पूर्ति होना असंभव है।

प्रशासन की अनदेखी

शासकीय समर्थन मूल्य खरीदी केंद्र स्थापित किया 16 किलोमीटर दूर, चुनाव बहिष्कार की चेतावनी

हीरालाल गोलानी सोहागपुर

प्रशासन की अनदेखी की बानगी देखिए कि ग्रामों के पास के सुविधाजनक खरीदी वेयरहाउस को दरकिनार करके क्षेत्र के किसानों को हतोत्साहित करने के उद्देश्य से ग्राम भानपुर, गलचा, भटगांव, मदनपुर, पालादेवरी, धूरखेडी, खिमरा, महुआखेड़ा,सेकाखेडी के किसानों को करीबन किसी ग्राम को 12 किलोमीटर, किसी ग्रामको 13किलोमीटर, किसी ग्राम को ग्राम को 16 किलोमीटर का फासला तय करके अपना गेहूं बेचने जाना पड़ेगा।इस मामले में प्रशासन की अनदेखी के कारण भारी संख्या में किसानों के साथ कांग्रेस नेताओं ने अनुविभागीय अधिकारी बृजेंद्र रावत को अपनी व्यथा बताई। किसानों ने कहा कि इतनी दूरी पर खरीदी केंद्र स्थापित करने से किसानों को ट्रेक्टर व्यय,डीजल खपत,समय व्यय आदि बातें एसडीएम को बताकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन अनुविभागीय अधिकारी बृजेंद्र रावत को सौंपा गया। ज्ञापन में चेतावनी दी गई है कि यदि हमारी उक्त जायज मांग तीन दिन के अन्दर नहीं मानी गई। तथा पीताम्बरा वेयरहाउस में खरीदी केंद्र स्थापित नहीं किया गया तो हमें लोकतंत्र के पवित्र मतदान का बहिष्कार करने को बाध्य होना पड़ेगा। जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की रहेगी।इस अवसर पर रणबीरसिंह पटैल, पुष्पराज सिंह पटैल , सरपंच आजादसिंह सहित कई किसान उपस्थित थे।

इस अवसर पर पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष एवं विधानसभा चुनाव प्रत्याशी पुष्पराज सिंह पटैल ने सुबह सवेरे

संवाददाता से चर्चा करते हुए कहा कि मुख्य सचिव वीणा राणा एवं वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन के साथ बैठक के उपरांत जारी आदेश को बदल दिया है । जिसमें नए आदेश के मुताबिक वेयर हाउस में पुराने गेहूं का स्टॉक है तो भी खाली होने पर वहां सरकारी गेहूं का स्टॉक हो सकेगा।हालांकि, पुराने गेहूं को अलग रखना होगा और नए गेहूं को रखने के लिए अलग स्थान पर मार्किंग करना होगा। श्री पटैल कहा कि सोहागपुर विधानसभा में भाजपा के हार जाने के तल्खी चल रही है। शासन के निर्देश हैं कि किसानों को करीबन 5 किलोमीटर के दायरे में खाद्यान्न बेचने की सहुलियत दी जाए। लेकिन तल्खी के कारण किसानों के हक मारे जा रहे हैं। आपने आरोप लगाया कि भाजपा अपने आप को किसानों की सरकार कहती है। लेकिन यहां क्षेत्र के किसानों को हतोत्साहित किया जा रहा है। आपने आगे कहा कि इशारों से जिन वेयरहाउसों को खरादी,या खाद्यान्न का रखाव नहीं देना है। ऐसे वेयरहाउसों में किसी वेयरहाउस में 1हजार बोरी, कहीं दो हजार खाद्यान्न नहीं उठाकर।उनका हक छीना जा रहा है। रितु वेयरहाउस में गई थी भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा ।

आपने आरोप लगाया कि अंजनेरी के सोमानी वेयरहाउस में खराब खाद्यान्न मिलने पर मालिक पर एफआईआर, लेकिन सत्ता के सिपाहासलार रितु वेयरहाउस किवलारी में प्रशासन ने मालिक को बचाकर गरीब मेनेजर दो अन्य पर एफआईआर दर्ज किया गया था। लेकिन अभी अभी मामले का निराकरण नहीं होने के बाद भी प्रशासन उसे किलीन चिट देकर चने की खरीदी दे रहा है। जिसमें फफूंद लगी मूंग के बदले अच्छी मूंग बदली जा रही थी। जिसे जानवर भी नहीं खाएं।उप संचालक कृषि नर्मदापुरम उक्त मामले को दर्ज होने से पहले का बताया कर प्रशासन एवं जनता को गुमराह कर रहे हैं। यदि समय रहते प्रदेश के मुखिया मोहन यादव एवं भाजपा संगठन ने क्षेत्र की गतिविधियों पर अंकुश नहीं लगाया तो निश्चित ही विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव में भी भाजपा का वोट बैंक गिरने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। उल्लेखनीय है कि सोहागपुर ब्लाक ने हमेशा लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव में भाजपा को विजयश्री दिलाई है। लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को पहली बार का हार का सामना करना पड़ा है। इसका मंथन भाजपा संगठन को अवश्य करना चाहिए तभी सकारात्मक परिणाम भाजपा की झोली में आएंगे।

पंडित प्रदीप मिश्रा के सिर में लगी चोट

नीमच के मनासा में होने वाली कथा हुई निरस्त

नीमच (एजेंसी)। नीमच जिले के मनासा में कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा की शिव महापुराण कथा निरस्त हो गई है। सोमवार को कथावाचक पंडित मिश्रा कुछ देर के लिए मनासा में मंच पर आए और फिर श्रध्दालुओं से रूबरू होकर खेद जताया और चले गए। उल्लेखनीय है कि जिले के मनासा में एक से सात अप्रैल तक सात दिवसीय शिव महापुराण कथा का आयोजन मनासा के राठौर परिवार द्वारा किया जा रहा था। इसमें प्रख्यात कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के मुखारबिंद से कथा होनी थी। पूर्व में भी कथा की तैयारियों को लेकर प्रशासन ने कथा की अनुमति को निरस्त कर दिया था। इसके बाद सर्व समाज व क्षेत्रिय विधायक सहित जनप्रतिनिधियों ने व्यवस्थाओं का जिम्मा उठाते हुए तैयारियों को अंतिम रूप दिया था। इसके बाद कथा की वापस अनुमति दी गई थी। हालांकि इस दौरान पुलिस प्रशासन ने भी काफी मेहनत की। सोमवार को प्रख्यात कथावाचक पंडित मिश्रा ने मंच से सभी भक्तों को संबोधित करते हुए कहां कि 29 मार्च को आष्ठा में आयोजित होली समारोह में नारियल की सिर में चोट लग गई। जिससे मेरे ब्रेन में सूजन आ गई है। डाक्टरों ने कथा करने से मना किया है। अस्पताल से छुट्टी लेकर में यहां पहुंचा हूं। मैं सभी भक्तों से क्षमा चाहता हूं। स्वास्थ्य सही नहीं होने से कथा नहीं हो सकेगी। अगर स्वास्थ्य में सुधार हुआ तो आगामी कथा होगी। अन्यथा वे भी निरस्त होगी। अगले वर्ष मनासा में कथा का आयोजन होगा। कथा के यजमान भी यहीं रहेंगे। कथा का पूरा खर्चा विट्ठलेश सेवा समिति ही उठाएगी। उन्होंने मंच से सभी का धन्यवाद किया। सभी व्यवस्थाओं के लिए आभार भी जताया। इस दौरान लाखों की संख्या में भक्त मौजूद रहे। इसके बाद मिश्रा पुनः चले गए।

जिस मेयर के फैन राहुल-प्रियंका थे, उसने भाजपा ज्वॉइन की

कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा के महापौर विक्रम अहाके ने छोड़ी कांग्रेस

भोपाल(नप्र)। पूर्व सीएम कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में कांग्रेस को लगातार झटके लग रहे हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने जिस छिंदवाड़ा महापौर विक्रम अहाके की तारीफ की थी, उन्होंने सोमवार को भाजपा जॉइन कर ली। विक्रम ने भोपाल में सीएम हाउस पहुंचकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के समक्ष भाजपा की सदस्यता ली। उनके साथ सभापति प्रमोद शर्मा ने भी पार्टी बदल ली। इससे पहले अमरवाड़ा विधायक कमलेश प्रताप शाह ने कांग्रेस छोड़ी थी। सीएम डॉ. मोहन से विक्रम की मुलाकात रविवार सुबह हुई थी। इसमें प्रदेश और छिंदवाड़ा लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई। साथ ही विभिन्न कर्मचारी वर्गों की समस्याओं को लेकर भी चर्चा हुई, जिस पर मुख्यमंत्री ने विश्वास दिलाया कि लोकसभा चुनाव के बाद विस्तार पूर्वक चर्चा कर कर्मचारी हित में निर्णय लिए जाएंगे। सूत्रों की मानें तो रविवार रात फिर मुख्यमंत्री के साथ महापौर विक्रम अहाके और सभापति प्रमोद शर्मा की मुलाकात हुई। इस मुलाकात में तय हो गया कि विक्रम और सभापति प्रमोद के साथ बड़ी संख्या में छिंदवाड़ा के कांग्रेसी भाजपा में शामिल होंगे।

अब छिंदवाड़ा में भी कमल का फूल खिलेगा: भाजपा जॉइन करने के बाद विक्रम ने कहा- देश-प्रदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। अब छिंदवाड़ा में भी कमल का फूल खिलेगा।

3786 वोट से जीते थे विक्रम अहाके: छिंदवाड़ा नगर निगम में कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी विक्रम अहाके ने 3786 वोटों से जीत हासिल की थी। उन्होंने भाजपा के अनंत धुर्वे को हराया था। 34 वर्षीय विक्रम पेशे से किसान हैं। वे ग्रेजुएट हैं। पिता भी पेशे से किसान हैं और मां आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं। वे जिला कांग्रेस कमेटी में प्रवक्ता के साथ कई दूसरे पदों पर रह चुके हैं। दो साल पहले छिंदवाड़ा नगर निगम चुनाव हुए थे। कांग्रेस प्रत्याशी विक्रम अहाके के चुनाव जीतने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ उन्हें अपने साथ हेलिकॉप्टर से भोपाल लाए थे।

विक्रम के बारे में राहुल गांधी और प्रियंका ने क्या कहा था

छिंदवाड़ा के मेयर विक्रम अहाके के कांग्रेस पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और महासचिव प्रियंका गांधी फैन थे। विक्रम के जीतने के बाद दोनों ने सोशल मीडिया पर उनकी जमकर तारीफ की थी। राहुल एक पोस्ट किया था। जिसका शीर्षक था- मां आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, पिता किसान और बेटा महापौर। उन्होंने विक्रम का लकड़ियां कंधे पर ले जाते, तेंदू पत्ते से कुछ सामान बनाते और मां के पैर छूते 3 फोटो भी पोस्ट किए थे। पोस्ट में उन्होंने लिखा था- अगर सच्ची मेहनत, लगन और ईमानदारी से सपनों के लिए लड़ा जाए, तो इंसान कुछ भी हासिल कर सकता है।

भाई-बहन की अर्थी उठी तो गांव में नहीं जले चूल्हे

नानी को छोड़ने जा रहे थे, ट्रक की चपेट में आने से तीनों की मौत; मां बेसुध

ग्वालियर (नप्र)। मां, नानी को छोड़कर 10 मिनट में वापस आता हूं। साथ में अंजलि भी जा रही है, वो मौसी से मिल लेगी। ये कहकर बेटा घर से निकला। इसके बाद मां, बेटा और बेटी की राह देखती रह गई। गांव के एक लड़के ने उनकी मौत की खबर दी। घटना ग्वालियर की है। नाती-नातिन और नानी की मौत की खबर से बिजौली स्थित चक केशवपुर गांव में मातम पसर गया। हर तरफ खामोशी छा गई थी। असल में 19 वर्षीय शुभम कुशवाह अपनी बड़ी बहन अंजलि (22), नानी द्रोपती (60) को लेकर हुरावली मौसी के घर जा रहा था। एक तेज रफ्तार ट्रक ने पीछे से उन्हें रौंद दिया। पुलिस की निगरानी में रविवार रात 10 बजे चक केशवपुर गांव से भाई-बहन की अर्थियां एक साथ उठीं। किसी ने सोचा भी नहीं था कि सुबह जिनको घर में हंसते-खेलते देखा था वो रात आते-आते हमेशा के लिए खामोश हो जाएंगे। उनकी अंतिम यात्रा में पूरा गांव उमड़ पड़ा था। माहौल इतना गमगीन हो गया था। गांव में शाम को चूल्हा तक नहीं जला है। हर कोई सिर्फ हादसे के बारे में ही बात कर रहा था।

बेटा-बेटी की मौत की खबर से मां हुई बेसुध

घटना की सूचना जब शुभम, अंजलि की मां गिरिजा कुशवाह को मिली तो वह बेसुध हो गईं। तत्काल मामले की सूचना शुभम के ताऊ हरेन्द्र कुशवाह को दी। वे घटनास्थल से कुछ ही दूरी पर थे। वह सीधे स्पॉट पर पहुंचे, लेकिन तब तक सबकुछ खत्म हो चुका था। जब हरेन्द्र ने सुना कि अंजलि और उसकी नानी मौके पर ही खत्म हो गई हैं, शुभम को हॉस्पिटल भेजा गया है। इस पर वह अस्पताल पहुंचे। डॉक्टरों ने शुभम को मृत घोषित कर दिया।

इसी साल लिया था बीएससी में एडमिशन: हरेन्द्र कुशवाह ने बताया कि उनके छोटे भाई बृजेश कुशवाह किसान हैं। खेती ही उनके परिवार की आजीविका का पूरा साधन है। बृजेश और उसकी पत्नी गिरजा के 3 बच्चे थे। सबसे बड़ी बेटी अंजलि, बेटा शुभम और उसका छोटा भाई आदित्य। शुभम ने इसी साल बीएससी में एडमिशन लिया था, जबकि अंजलि बीएससी फाइनल की छात्रा थी।

ऐसे समझिए पूरा हादसा: ग्वालियर के बिजौली स्थित चक केशवपुर निवासी शुभम कुशवाह रविवार को अपनी नानी द्रोपती को मौसी के घर हुरावली छोड़ने जा रहा था। इसी समय उसकी बहन अंजलि भी चलने के लिए जिद करने लगी। बाइक नंबर पर शुभम, बहन अंजलि और नानी द्रोपती को लेकर निकला था। बड़ागांव से उसने हाईवे का रूट पकड़ा। शुभम ने सोचा था कि टोल के आगे हरखेड़ा के मोड़ से वह हाईवे से सिटी में अंदर चला जाएगा। मोहनपुर पुल से कुछ मीटर की दूरी पर पीछे से आया तेज रफ्तार ट्रक उनको रौंदता हुआ निकल गया।

सीसीटीवी कैमरे के फुटेज टोल से मिले

पुलिस ने ट्रक के भागने की दिशा में सर्चिंग की। पुलिस मेहरा गांव के टोल पर पहुंची तो वहां सीसीटीवी कैमरे में ट्रक दिखा। पुलिस ने फुटेज ले लिए हैं। पुलिस का कहना है कि जल्द चालक व चेसिस ट्रक पुलिस की कस्टडी में होगा। हरेन्द्र कुशवाह का कहना है कि पुलिस ने गंभीरता नहीं दिखाई वरना टोल से निकलते ही ट्रक पकड़ा जाता। पुलिस तो हम पर निगरानी रखे हुए थी कि पोस्टमॉर्टम के बाद लाशों को रखकर जाम न लगा दें।

भोपाल में 14 हजार कर्मचारियों की चुनावी ट्रेनिंग शुरू

- ईवीएम, मॉक पोल, वोटिंग की समझ रहे प्रक्रिया; क्या सीखा यह एग्जाम देकर बताना होगा

भोपाल (नप्र)। भोपाल के कुल 14 हजार 761 कर्मचारी सोमवार से लोकसभा चुनाव की एबीसीडी सीख रहे हैं। शहर के 8 सेंटरों पर उन्हें ईवीएम, मॉक पोल, वोटिंग, मतदान सामग्री लेने से लेकर जमा कराने तक की ट्रेनिंग दी जा रही है। ट्रेनिंग में उन्होंने क्या सीखा? इसका वे एग्जाम भी देंगे। परीक्षा में फेल होने वाले कर्मचारी को फिर से ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग 5 दिन एक ही सत्र में सुबह 11 से शाम 4 बजे तक चलेगी। पिछले चुनावों में 2-2 सत्र में कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जाती थी, लेकिन संख्या अधिक होने की वजह से एक दिन में एक ही सत्र होगा। प्रतिदिन एवरेज 3 हजार कर्मचारियों को चुनाव से जुड़ी हर जानकारी दी जाएगी। कुल 72 मास्टर ट्रेनर्स उन्हें ट्रेनिंग देंगे। इनमें ईवीएम मास्टर ट्रेनर्स भी शामिल हैं। जिला पंचायत सीईओ ऋतुराज सिंह ने भी कर्मचारियों को संबोधित किया।

एक घंटे की परीक्षा भी होगी : ट्रेनिंग के बाद कर्मचारियों की एक घंटे की परीक्षा भी होगी। इसमें उनसे ट्रेनिंग से जुड़े सवाल ही पूछे जाएंगे। यदि वे सवालों का जवाब नहीं दे पाते हैं तो उन्हें अगले दिन फिर से ट्रेनिंग दी जाएगी। गायब रहने वाले कर्मचारियों को सस्पेंड किया जाएगा।

सीहोर विधानसभा की ट्रेनिंग वहीं पर होगी

भोपाल लोकसभा में कुल 8 विधानसभा- बैरसिया, नरेला, गोविंदपुरा, हुजूर, भोपाल उत्तर, भोपाल मध्य, भोपाल दक्षिण-पश्चिम और सीहोर शामिल हैं। भोपाल जिले की 7 विधानसभा के कर्मचारियों को यही पर ट्रेनिंग मिलेगी, जबकि सीहोर विधानसभा के कर्मचारियों को सीहोर में ही ट्रेनिंग दी जाएगी। लोकसभा चुनाव में कुल 2299 मतदान केंद्र एवं 64 सहायक मतदान केंद्र है। इस तरह आठों विधानसभाओं में 2363 मतदान केंद्र रहेंगे।

आरजीपीवी में 19.48 करोड़ का घोटाला

30 दिन बाद भी खाली हाथ पुलिस, 3 टीमें आरोपियों की तलाश में जुटीं

भोपाल (नप्र)। आरजीपीवी में 19.48 करोड़ की गड़बड़ी के मामले की 3 मार्च को एफआईआर दर्ज की गई थी। तब से अब तक 30 दिन हो चुके हैं। इसके बाद भी पुलिस मुख्य आरोपियों तक नहीं पहुंच सकी। दावा किया जा रहा है कि आरोपी तत्कालीन रजिस्ट्रार आरएस राजपूत, रिटायर फाइनेंस कंट्रोलर ऋषिकेष वर्मा, तत्कालीन कुलपति प्रो. सुनील कुमार की तलाश में एसआईटी की 3 टीमें जुटी हैं। आधा दर्जन से अधिक संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा चुकी है। इसके बाद भी तीनों आरोपियों का पुलिस कोई सुराग नहीं जुटा सकी है। हालांकि, इस बीच पुलिस ने 22 मार्च को आरबीएल बैंक में बतौर टास्क हेड कार्यरत रहे कुमार मयंक को गिरफ्तार किया था। वहीं, बैरागढ़ के सहायक पुलिस आयुक्त अनिल शुक्ला ने कहा- मामले की जांच की जा रही है, जब्त किए दस्तावेजों की भी तजदीक की जा रही है, आरोपियों की तलाश में पुलिस की तीन टीमें जुटी हैं और कई स्थानों पर हमारे द्वारा दबिश दी जा चुकी है। दूसरी ओर, एफआईआर दर्ज होने के बाद से एवीबीपी कार्यकर्ता आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं ने रविवार को भी भोपाल पुलिस कमिश्नर के कार्यालय पर धरना दिया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने तक धरना समाप्त नहीं किया जाएगा। इस धरने में बड़ी संख्या में छात्राएं भी शामिल रहीं।

गिरफ्तारी को लेकर पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन: इससे पहले एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को पुलिस कमिश्नर हरिनारायणचारी मिश्र को ज्ञापन दिया था। संगठन के सह मंत्री जशवंत यादव बताया कि हमने ज्ञापन में राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भोपाल में चल रहे आर्थिक भ्रष्टाचार के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की थी।

म.प्र. में 1 अप्रैल से नई आबकारी व्यवस्था लागू

दुकानों-गोदामों में शराब की स्टाक एंट्री नहीं तो आज राजसात होगी सिक्योरिटी डिपाजिट

भोपाल (नप्र)। मध्य प्रदेश में एक अप्रैल से नई आबकारी नीति लागू हो गई है। शराब के दामों में 15 फीसदी की वृद्धि के साथ आबकारी आयुक्त ने हर दुकान के स्टाक की जानकारी जिला अधिकारियों से मांगी है। इसको लेकर जारी निर्देश में कहा है कि अगर किसी दुकान का स्टाक वेरिफाई नहीं पाया तो इसके लिए विभाग के अधिकारी जिम्मेदार होंगे। साथ ही यह भी कहा है कि शराब दुकान का नवीनीकरण हुआ हो या नहीं, शराब दुकान और गोदाम का स्टाक ई-आबकारी पोर्टल पर अपडेट करना जरूरी होगा। जिलों को जारी निर्देश में आबकारी आयुक्त अभिजीत अग्रवाल ने कहा है कि सभी शराब दुकानों के लाइसेंस धारकों द्वारा शराब दुकान और उससे संबंधित गोदाम के शेष स्टाक को लेवल वार एंट्री किया जाकर ई-आबकारी पोर्टल पर अपलोड करना होगा। यह काम एक अप्रैल को ही पूरा किया जाना है। जिन दुकानों का नवीनीकरण नहीं हुआ है उनकी आईडी पर भी स्टाक की एंट्री का विकल्प एक अप्रैल को उपलब्ध रहेगा। इसके अंतर्गत 2023-24 के सभी शराब दुकान लाइसेंस धारकों को पूरी करनी है, भले ही लाइसेंस धारक ने 2024-25 के लिए भी नवीनीकरण करा लिया है या दुकान किसी और को आवंटित कर दी गई है।

2 अप्रैल को राजसात होगी सिक्योरिटी डिपाजिट

आबकारी आयुक्त अभिजीत अग्रवाल ने कहा है कि इसकी एंट्री नहीं किए जाने पर शेष स्टाक के निराकरण या हस्तांतरण की प्रोसेस में गड़बड़ी होगी, इसलिए सभी सर्किल प्रभारी की यह जिम्मेदारी होगी कि अपने प्रभार क्षेत्र में सभी शराब दुकानों की एंट्री आज हर हाल में करा दें। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो संबंधित लाइसेंस धारक द्वारा जमा की गई सिक्योरिटी की राशि को 2 अप्रैल को राजसात कर लिया जाएगा। इसके लिए विभाग अलग से कोई नोटिस जारी नहीं करेगा। इतना ही नहीं आबकारी आयुक्त ने लाइसेंस धारक द्वारा की गई एंट्री का वेरिफिकेशन करने के लिए भी जिला कार्यालयों को निर्देश दिए हैं।

म.प्र.की सड़कों पर सफर हुआ महंगा

प्रॉपर्टी की नई गाइडलाइन आज से लागू नहीं होगी, नई दरें चुनाव के बाद

भोपाल (नप्र)। मध्यप्रदेश में प्रॉपर्टी की नई गाइडलाइन आज (एक अप्रैल) से लागू नहीं होगी। 2023-24 की गाइडलाइन के अनुसार ही प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री होगी। सोमवार सुबह यह आदेश सामने आया। महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक मध्यप्रदेश ने लोकसभा चुनाव की आचार संहिता का हवाला देते हुए यह फैसला लिया है। नई दरें चुनाव के बाद लागू होंगी। वहीं प्रदेश में एक अप्रैल से 102 टोल बैरियर में से 10 मार्गों पर टोल टैक्स महंगे हो रहे हैं। इसका सीधा असर इन मार्गों के सफर करने वाले लोगों के जेब पर पड़ेगा।

इसलिए बढ़ाए टोल टैक्स

नेशनल हाईवे में होल सेल प्राइस इंडेक्स (थोक मूल्य सूचकांक) के आधार पर टोल टैक्स के रेट बढ़ाए जाते हैं। दूसरी ओर स्टेट हाईवे के मार्ग जो एमपीआरडीसी की देखरेख में संचालित हैं, उनके निर्माण के दौरान समय-समय पर टोल टैक्स रेट में वृद्धि का प्रस्ताव था। ये सड़कें जब बीओटी में बनाई गई थीं, तभी यह शर्त तय की गई थी कि हर साल एक अप्रैल से टोल रेट में वृद्धि की जाएगी। इस कारण प्रदेश के 4 नेशनल हाईवे और 6 स्टेट हाईवे के टोल टैक्स बढ़ाए गए हैं।

दो दिन में 1600 प्रॉपर्टी की खरीद-फरोख्त

- जिला पंजीयक स्वपनेश शर्मा ने बताया कि शनिवार और रविवार को 1600 से अधिक प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री हुई है
- इन इलाकों में भी सबसे ज्यादा बढ़ाना प्रस्तावित था गाइडलाइन
- मिसरोद वार्ड-52 के दृष्टि ऐनक्लेव, बावड़िया कलां में 44.23 प्रतिशत
- होशंगाबाद रोड पर चिनार सफायर में 42.04 प्रतिशत
- कोलार के कान्हा कुंज ग्राम गेहूंखेड़ा में 42.04 प्रतिशत
- अयोध्या नगर में हाउसिंग बोर्ड के सभी फेज 40.10 प्रतिशत
- अयोध्या नगर के सुरभि परिसर में 40 प्रतिशत
- मिसरोद वार्ड 52 में होशंगाबाद रोड से हटकर कम्फर्ट ऐनक्लेव, खनूजा ऐनक्लेव और लक्ष्मी परिसर में 38.88 प्रतिशत
- अयोध्या नगर वार्ड-68 के भवानी कैंपस में 37.5 प्रतिशत
- कोलार वार्ड 81 के कान्हा कुंज ग्राम बैरागढ़ चीचली में भी 37.5 प्रतिशत
- बावड़ियाकलां की क्रिस्टल स्मार्ट सिटी और डी के 24 कैरेट 36.36 प्रतिशत

सबसे ज्यादा 1228 लोकेशन शहरी इलाकों की

भोपाल में कुल 3900 लोकेशन हैं। इनमें शहर में 3110 और ग्रामीण क्षेत्रों में 790 लोकेशन हैं। नई प्रस्तावित गाइडलाइन में कुल 1443 लोकेशन में गाइड लाइन बढ़ाया जाना तय किया गया था। जिनमें शहरी क्षेत्र में 1228 और ग्रामीण क्षेत्र में 215 लोकेशन शामिल हैं। जिला मूल्यांकन समिति ने प्रस्तावित गाइडलाइन पर चार दिन तक सुझाव मांगे थे। इस पर कुल 20 सुझाव आए हैं। इन पर मंथन के बाद केंद्रीय कमेटी ने प्रस्तावित गाइडलाइन को मंजूरी दे दी। हालांकि, 1 अप्रैल से यह गाइडलाइन लागू नहीं की गई है।

जहां बड़े प्रोजेक्ट, वहां पर बढ़ाए गए थे रेट : जिन इलाकों में ज्यादा रेट बढ़े हैं, वहां या तो बड़े इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चल रहे हैं या फिर प्रस्तावित हैं। मुख्य रूप से कोलार में सिक्स लेन, अयोध्या नगर में 10 लेन रोड प्रोजेक्ट और 100 बेड वाले अस्पताल का निर्माण, भानपुर खंती का खत्म होना प्रमुख कारण हैं।

अप्रैल के पहले सप्ताह मौसम के 2 नए सिस्टम

म.प्र.में वेस्टर्न डिस्टरबेंस का असर कम रहेगा; गर्मी बढ़ेगी

भोपाल (नप्र)। मध्यप्रदेश में 3 दिन तक साइक्लोनिक सर्कुलेशन, ट्रफ और वेस्टर्न डिस्टरबेंस (पश्चिमी विक्षोभ) के असर से मौसम बदला रहा। इसके बाद गर्मी का असर फिर से बढ़ गया है। रविवार को शिवपुरी में दिन का टेम्प्रेचर 41 डिग्री पहुंच गया था। वहीं, रतलाम, खंडवा और नर्मदापुरम भी गर्म रहे। अप्रैल के पहले सप्ताह में मौसम के 2 वेस्टर्न डिस्टरबेंस एक्टिव हो रहे हैं। हालांकि, प्रदेश में इनका असर कम रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार- 2 अप्रैल की रात और 5 अप्रैल को उत्तर भारत में दो वेस्टर्न डिस्टरबेंस एक्टिव होंगे। इसके दो से 3 दिन बाद मध्यप्रदेश में इनका मामूली असर हो सकता है। कुछ जिलों में बादल छा सकते हैं। इसके बावजूद गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। दिन के साथ रातें भी गर्म रहेंगी।

हीट वेव का असर भी रहेगा

आईएमडी भोपाल के वैज्ञानिक अभिजीत चक्रवर्ती ने बताया कि अब प्रदेश के कई जिलों में हीट वेव का असर भी रहेगा। वहीं, गुना, शिवपुरी, छतरपुर, टीकमगढ़, अशोकनगर, जबलपुर, मंडला और बालाघाट में अगले 1-2 तक हीट वेव, यानी गर्म हवाएं भी चलेंगी। रविवार को भी कई जिलों में हीट वेव का असर रहा।